R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 02
16 से 31 अक्टूबर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

हरियाणा, जम्मू-कश्मीर का जनादेश

अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जनता

ये परिणाम महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में क्या रंग दिखाएंगे

वादों, लोकलुभावन घोषणाओं पर निर्भरता पड़ेगी भारी

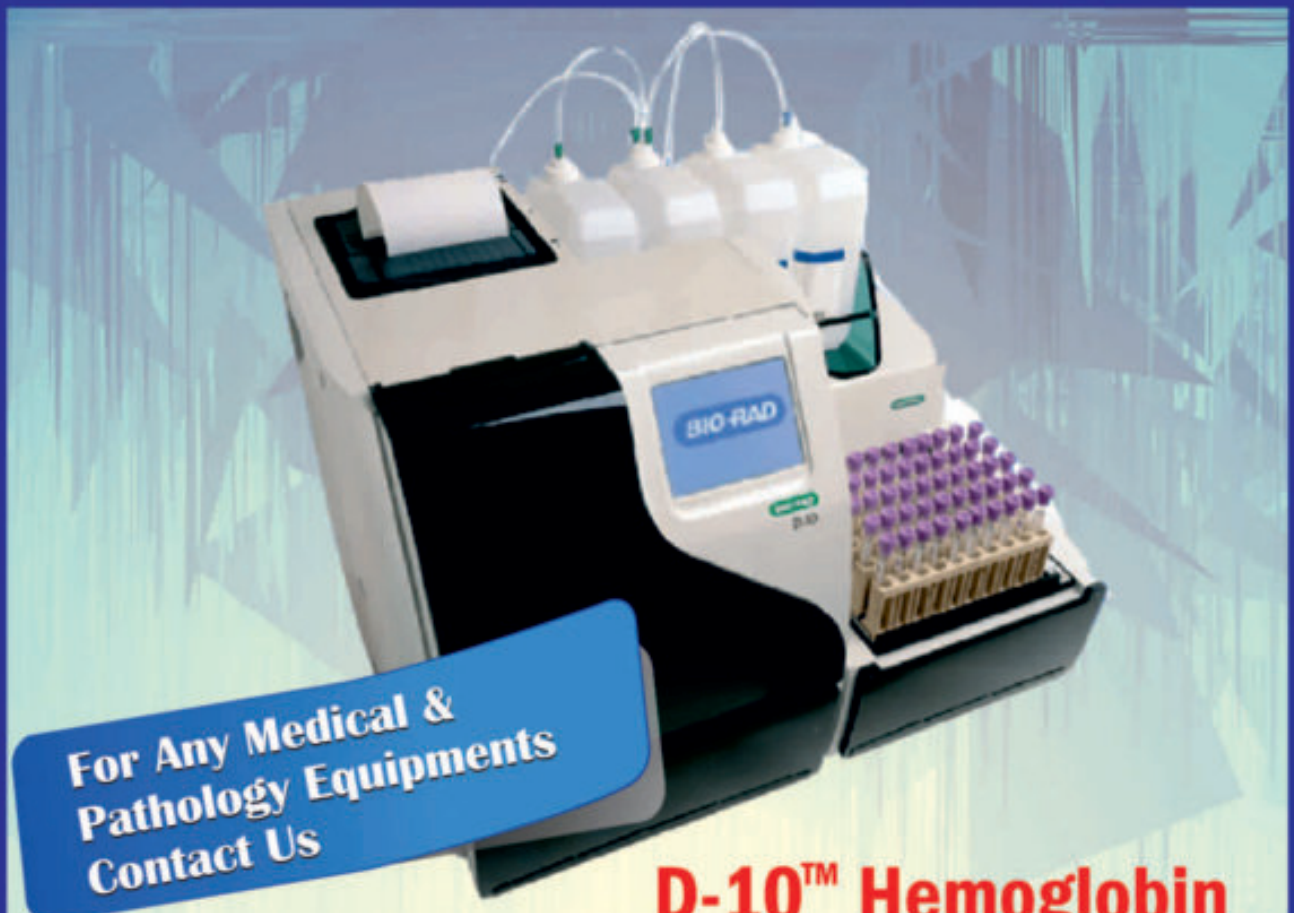

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

भर्राशाही

9 | कंडम गाड़ियों के भरोसे डायल-100

मप्र में अपराध, हादसे और आपदा में लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) डायल-100 पटरी से उतर चुकी है। डायल-100 में उपयोग लाए जाने वाले वाहन पुराने हो गए हैं।

डायरी

10-11 | सुशासन के लिए होगी...

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुशासन का जो मंत्र दिया है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव अनुराग जैन की है। मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही अनुराग जैन जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं...

राजकाज

14 | निगम-मंडलों में जल्द...

मप्र में लंबे समय से राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे नेताओं को फिर निराशा हाथ लग सकती है। इस निराशा की वजह यह है कि भाजपा ने फिलहाल निगम मंडलों की नियुक्तियों को होल्ड कर दिया है। संभवत: संगठन चुनाव के बाद ही निगम-मंडल...

योजना

18 | संवरेगा पुराना वल्लभ भवन

भोपाल के राजधानी बनने के सात साल बाद यानी 1962 में अस्तित्व में आए वल्लभ भवन को अब मॉडर्न लुक मिलेगा। बिल्डिंग के मूल स्वरूप में बदलाव किए बिना यहां विजिटर्स और अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उसी तरह की आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी जैसी वल्लभ भवन की...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

लोकसभा चुनाव के ठीक चार महीने बाद हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि वादों और लोकलुभावन घोषणाओं पर निर्भर रहना पार्टियों को भारी पड़ेगा। क्योंकि अब जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता भावनाओं में बहने वाली नहीं है। समय रहते जो पार्टी जनता के मनोभाव को समझते हुए मैदानी रणनीति पर काम करेगी, वही सिंहासन पर बैठ पाएगी। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर का जनादेश जल्द होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली चुनाव के लिए भी आईने का काम करेगा।

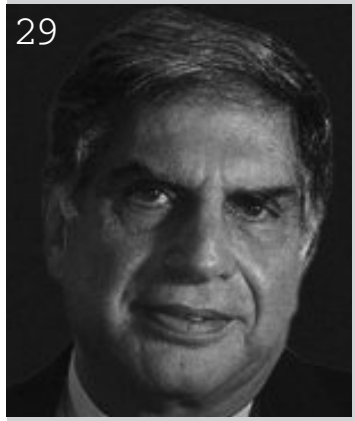

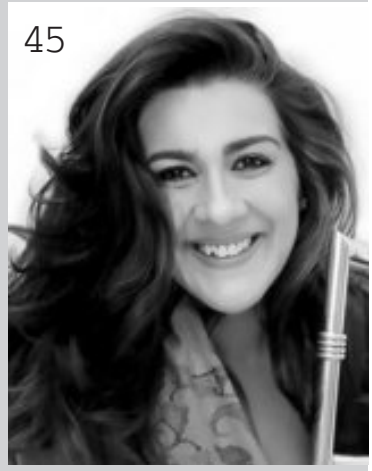

राजनीति

30-31 | मोदी के मन में क्या?

पिछले कुछ हफ्तों में मोदी सरकार को प्रेस द्वारा मिली खराब कवरेज के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम आंकना हमेशा एक गलती है। वे अभी भी भारत में सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं और सबसे चतुर लोगों में से एक हैं। वे आमतौर पर अपने विरोधियों से कम से कम तीन कदम आगे...

महाराष्ट्र

35 | सामाजिक न्याय से सत्ता...

हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार थमने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासी तपिश गरमा गई है। भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए राज्य में सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है तो कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन अपनी वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में पुरजोर तरीके...

बिहार

38 | कब तक टिकेंगे प्रशांत किशोर

चुनावी रणनीति से सक्रिय राजनीति में आने वाले प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक 12 महीने पहले बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। पार्टी का नाम जन सुराज रखा गया है और दलित समुदाय के मनोज भारती इसके...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक
अक्स

वर्ष 23, अंक 2, पृष्ठ-48
16 से 31 अक्टूबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

शराब कर रही कुलीनों के कुनबे की सेहत खराब

शायर निदा फाजली का एक शेर है...

कुछ भी बचा न कहने को हर बात हो गई
आओ कहीं शराब पिएं रात हो गई...

उपरोक्त पंक्तियां मप्र में शराब बंदी के तमाम दावों पर सटीक बैठ रही हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी मामा की छवि चमकाने के लिए प्रदेश में शराबबंदी के लिए तरह-तरह के प्रयोग करते रहते थे, लेकिन शराब से होने वाली आय उन्हें ऐसा नहीं करने देती थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शराबबंदी के नाम पर प्रदेशभर में अहाते तो बंद करवा दिए, लेकिन अब हर कहीं शराब और नशाखोरी हो रही है। यह शराब और नशाखोरी प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि इन्हें मुद्दा बनाकर भाजपाई अपनी ही सरकार पर हमला कर रहे हैं। गौरतलब है कि मप्र में शराबबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर लगातार दबाव बनाया। कई बार वे रात-रातभर धरने पर भी बैठीं। शराब दुकानों पर पत्थरबाजी भी की। उमा भारती का यह विरोध राजनीतिक गुस्सा साबित हुआ। लेकिन प्रदेश की नई सरकार में भी पार्टी के विधायक और नेता शराबखोरी और नशाखोरी को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने तो रीवा आईजी कार्यालय व मऊगंज एसपी कार्यालय में दंडवत होकर कहा कि मेरा गुंडों से मर्डर करवा दो। शराब माफिया को पुलिस सरंक्षण दे रही है। पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई पटेल के समर्थन में उतरे और कहा कि प्रदीप जी आपने सही मुद्दा उठाया है, पर क्या करें? पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इससे नेताओं की खीझ बता रहे हैं। इससे और कुछ हो या न हो कुलीनों के कुनबे की सेहत तो जरूर खराब हो रही है। इसके इतर अगर भाजपा नेताओं के आरोपों और दावों पर गौर करें तो यह बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश में माफिया, अपराधी, नशाखोरी के खिलाफ जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, वे नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में निरंतर लोमहर्षक घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रदेशभर में शराबखोरी की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल में ही शराब दुकानों के बाहर लोग जाम छलकाते नजर आते हैं। गत दिनों आबकारी विभाग और नगर निगम की टीम ने ऐसे लोगों को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि ठेले, गुमठियां भी जब्त कीं। इन ठेले और गुमठियों में बैठकर लोग शराब पी रहे थे। आलम यह है कि अकेले राजधानी में कंपोजिट शराब दुकानों के आसपास अवैध रूप से शराब पीने वालों के विरूद्ध अप्रैल से अब तक कुल 1541 प्रकरण बनाए जा चुके हैं। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भोपाल में अधिकांश शराब दुकानों के बाहर शराबियों का डेरा रहता है। कोलार के नयापुरा में शराब दुकान के बाहर ही जाम छलकाए जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर करोंद, शाहपुरा, अयोध्या बायपास, आनंद नगर, पटेल नगर, हमीदिया रोड समेत अन्य स्थानों पर भी देखने को मिलती है। वहीं प्रदेश में खनन माफिया, ड्रग माफिया, लगातार अवैध गतिविधियों में जुटे हुए हैं। राजधानी भोपाल में ही सरकार की नाक के नीचे एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। यह प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी भोपाल में इस तरह का गोरखधंधा हो सकता है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों के हालात कैसे होंगे। ऐसे में भाजपा नेताओं के विरोध को केवल राजनीतिक स्टंट कहना बेमानी होगी। भाजपा संगठन भले ही इस मामले के बाद नेताओं पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाने की जरूरत है और माफिया, अपराधियों और कालाबाजारियों पर नकेल कसने की जरूरत है।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

सही कदम साबित होगा

मप्र की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार का जोर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर है। इससे अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को गति दी जा रही है। इस प्रयास की न केवल भारत सरकार प्रशंसा कर चुकी है बल्कि अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई है। यह एक अच्छा कदम साबित होगा।

● **महक पाल,** बैतूल (म.प्र.)

नए सीएस अनुभवी हैं

मप्र के नए मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अफसर अनुराग जैन बन गए हैं। अनुराग जैन के सीएस बनने से मप्र में विकास की रफ्तार डबल होगी। अनुराग जैन अनुभवी अधिकारी हैं। और उन्हें केंद्र सरकार के साथ काम करने का अनुभव भी है। जो मप्र के बहुत काम आ सकता है।

● **मुस्कान दांगी,** राजगढ़ (म.प्र.)

सतर्कता बरते सरकार

वन विभाग में वेतन गणना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिससे सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार को ऐसे मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे उसे भविष्य में आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। और सरकारी कर्मचारी पर भी भार न पड़े।

● **हेमंत सूर्यवंशी,** ग्वालियर (म.प्र.)

मप्र आत्मनिर्भर बनने की राह पर

मप्र की मोहन सरकार इन दिनों प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भोपाल को झुग्गीमुक्त करने के लिए समाधान निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कलेक्टर से झुग्गी मुक्त करने की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो, फिर झुग्गियों को खाली कराया जाए। ताकि लोगों को परेशानी न हो। जनप्रतिनिधियों से समन्वय हो। जिले के राज्य स्तर पर लंबित कार्यों का निराकरण कराना बैठक का मुख्य उद्देश्य है। भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से अगले 25 साल के प्लान को ध्यान में रखकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे हों।

● **लिथिलेश सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में एक देश–एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि आजादी के बाद शुरुआती कई सालों तक भारत में एक देश–एक चुनाव ही होता था। यानी कि सभी राज्यों के विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। हमें यह समझना होगा कि एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है?

● **नरेश सोनी,** जबलपुर (म.प्र.)

कुपोषण में आ रही कमी

मप्र में कुपोषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों से मप्र के कुपोषण में एक सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली हैं। इस ऐप के जरिए पिछले एक वर्ष में बच्चों की कुपोषण स्थिति में निरंतर सुधार परिलक्षित हो रहा है। ट्रेकर ऐप के आंकड़ो के मुताबिक अप्रैल 2023 में राज्य में 30 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले थे, जो जुलाई 2024 तक घटकर 27 प्रतिशत रह गए हैं। यह प्रदेश के लिए अच्छी बात है।

● **अजय वर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

अब शक्ति पीठ दिल्ली में

देश की सत्ता का केंद्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जरूर है लेकिन सौ बरस के होने जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति पीठ उसके गठनकाल से ही नागपुर रहती आई है। जब कभी भी भाजपा की सरकार केंद्र में रही, संघ परिवार की आंतरिक समस्याओं का समाधान तलाशने दिल्ली को नागपुर जाते देखा गया। मोदी-शाह युग में लेकिन बहुत कुछ बदला है जिसका एक नतीजा नागपुर का दिल्ली आना बतौर सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों का केंद्र अब दिल्ली बनने जा रहा है। संघ का नया आलीशान भवन दिल्ली के झंडेवालान में बनकर तैयार हो गया है। जानकारों की मानें तो सादगी पसंद संघ का नया भवन अत्याधुनिक तो है ही, पंच सितारा सुविधाओं से भी लैस है। 12 मंजिले तीन टावरों के परिसर में सुरक्षा जांच के लिए एक्सरे मशीनें लगी हैं, तेज रफ्तार वाली लिफ्ट हैं, भव्य सभागार बनाए गए हैं और अतिथियों के लिए भी आवासीय व्यवस्था है। संघ में दूसरे नंबर पर आने वाले सह-सरसंघचालक दत्तात्रेय होसबोले और कई अन्य बड़े पदाधिकारी अब यहीं बैठा करेंगे। संघ परिवार में यह जानने की बड़ी बेचैनी बताई जा रही है कि क्या नागपुर में ही अभी भी संघ का मुख्यालय रहेगा या फिर दिल्ली स्थित इस नए परिसर को ही मुख्यालय घोषित कर दियाा जाएगा?

धामी आगे, बाबा पीछे

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा अब पहले सरीखा नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी आलाकमान का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कम होने की बात चौतरफा कही-सुनी जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बाबा ही हिंदुत्व के असली जननायक हैं और आने वाले समय में ही भाजपा का चेहरा बनाकर राष्ट्रीय फलक पर उतारे जाएंगे, भाजपा सूत्र लेकिन संघ से इतर बातें कर रहे हैं। चर्चा जोरों पर है कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उप्र के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में आगे करने के बजाय पार्टी आलाकमान ने हिंदुत्व के नए चेहरे बतौर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे कर बाबा का कद छोटा करने का काम किया है। धामी को बतौर स्टार प्रचारक दोनों ही राज्यों में पार्टी ने उतारा और यह प्रचार जमकर किया कि समान नागरिक संहिता कानून बनाने वाले धामी मोदी-शाह की जोड़ी भविष्य के उन नेताओं में शुमार हो चुके हैं जो समय आने पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर भाजपा का नेतृत्व संभालेंगे। सूत्रों की मानें तो धामी शीघ्र ही राज्य में सक्रिय वक्फ माफिया के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ने जा रहे हैं।

जगन का अवसान काल

राजनीति में रिश्ते कभी स्थाई नहीं रहते हैं। उभरते सितारे के साथ सभी खड़े होना पसंद करते हैं और डूबते सितारे का साथ छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में धूमकेतु की भांति छाए जगन रेड्डी वर्तमान समय में गर्दिश का दौर देख रहे हैं। अप्रैल 2019 में जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य विधानसभा की 175 सीटों में से 151 सीटें जीत इतिहास रच दिया था। तब सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और उसके नेता एन चंद्रबाबू नायडू का कद आंध्रप्रदेश और देश की राजनीति में खासा घट गया था। 2024 में लेकिन नायडू ने बाजी पलट दी। तेलुगुदेशम पार्टी 135 सीटें जीत बहुमत में आ गई। एनडीए गठबंधन को कुल 164 सीटों में विजय हासिल हुई। लोकसभा सीटों की 25 में से एनडीए गठबंधन 21 सीटों पर विजयी रहा और जगन की वाईएसआर कांग्रेस मात्र 4 सीटें जीत पाई। इन नतीजों के बाद से ही जगन रेड्डी की पार्टी में भारी उथल-पुथल मच गई है। एक के बाद एक बड़े नेता जगन का साथ छोड़ तेलुगुदेशम अथवा भाजपा का दामन थामने लगे हैं। गत सप्ताह जगन के करीबी कहलाए जाने वाले अनुसूचित जाति के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद आर. कृष्णा ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर जगन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।

जदयू के भीतर घमासान

देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश बाबू अक्सर देखा करते थे। अब भी देखते हैं या नहीं, यह कह पाना कठिन है लेकिन उनके करीबियों का दावा है कि अभी भी बिहारी बाबू को अक्सर ऐसा सपना आता है। बीते 19 वर्षों से बिहार के राजसिंहासन पर काबिज नीतीश कुमार की क्षमताओं पर अब लेकिन उनके करीबी ही संदेह करने लगे हैं और कई पुराने सहयोगी उनसे किनारा करते स्पष्ट नजर आने लगे हैं। गत दिनों नीतीश कुमार के विश्वस्त माने जाने वाले केसी त्यागी ने मुख्य प्रवक्ता पद छोड़ जदयू के भीतर चल रहे घमासान को सार्वजनिक करने का काम किया था। अभी पार्टी त्यागी के इस्तीफे से पैदा हुए संकट का समाधान तलाश ही रही थी कि नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी को शर्मसार करने का काम कर दिया। वरिष्ठ मंत्री चौधरी ने एक कविता को अपने एक्स हैंडल में पोस्ट किया- बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए एक-दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए।

रघुवर छोड़ेंगे राज्यपाल पद

81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर में यहां विधानसभा चुनाव होने तय हैं। ऐसे में भाजपा ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह खासा बढ़ गया है। इस बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जानकारों की मानें तो गत वर्ष पार्टी आलाकमान ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देने की नीयत से रघुवरदास को उड़ीसा का राज्यपाल बना प्रदेश की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया था। दास ने तब राज्यपाल पद स्वीकार भी कर लिया था लेकिन उन्हें राजभवन की शान-शौकत रास नहीं आ रही है और वे वापस राजनीति के अखाड़े में उतरने के लिए आतुर हो चले हैं।

सर, मुझे प्रतिनियुक्ति मिल जाएगी ना

केंद्रीय जांच एजेंसी में पदस्थ मप्र कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस कदर भा गई है कि वे मप्र नहीं आना चाहते हैं। आलम यह है कि साहब समय से पूर्व ही अपनी प्रतिनियुक्ति को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयास में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि साहब ने अभी से यह कोशिश शुरू कर दी है कि आगे भी उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए। गौरतलब है कि मप्र के ब्यूरोक्रेट्स का दिल्ली प्रेम जगजाहिर है। जो भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में जाता है, वह वापस आना नहीं चाहता है। लेकिन 2012 बैच के इन आईपीएस अधिकारी का दिल्ली प्रेम ऐसा है, जो पहले कभी भी किसी ब्यूरोक्रेट्स में देखने को नहीं मिला। इन साहब का दिल्ली प्रेम तो इस कदर सातवें आसमान पर पहुंच गया है कि उसको लेकर दिल्ली से लेकर मप्र की प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल, साहब की प्रतिनियुक्ति की अवधि 2027 में समाप्त होने वाली है, लेकिन वे अभी से प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने में लग गए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवधि बढ़ाने के लिए यह कह दिया है कि सर, 2027 में भी मुझे प्रतिनियुक्ति मिल जाएगी ना। और तो और न तो दिल्ली वाले साहब ने सीनियर से बात करने का समय देखा और ना ही उन्हें प्रतिनियुक्ति के बारे में नियम-कायदे ही नहीं पता है। जबकि प्रतिनियुक्ति अवधि के 3 माह पहले आदेश निकाले जाते हैं।

बिल रोकना पड़ा भारी

प्रदेश के एक विभाग में एक महिला आईएएस अधिकारी का बिल रोकना एक अन्य महिला अधिकारी को भारी पड़ा। नाराज मैडम ने उनका प्रदेश के एक बड़े विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर दिया। यह मामला युवाओं के कल्याण से संबंधित विभाग का है। सूत्रों का कहना है कि 1992 बैच की आईएएस अधिकारी विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं। मैडम अक्सर प्रवास पर जाती रहती हैं। ऐसे ही एक प्रवास से लौटने के बाद मैडम ने विगत दिनों टैक्सी का बिल विभाग में पदस्थ वित्त अधिकारी को दिया तथा कहा कि इसका पेमेंट करवा दें। विभाग की वित्तीय व्यवस्था को देखने वाली उक्त मैडम ने अपर मुख्य सचिव का बिल ही रोक दिया। सूत्र बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव यह देखकर आग बबूला हो गईं और आव देखा न ताव वित्तीय व्यवस्था देखने वाली मैडम का ट्रांसफर प्रदेश के एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कर दिया। अपर मुख्य सचिव का यह रूप देखकर विभाग के अधिकारी सकते में हैं। गौरतलब है कि मैडम जिस भी विभाग में रही हैं, वहां विवादों में फंसती रही हैं। खासकर पैसों के मामले में वे अक्सर विभाग पर बोझ डालती रहती हैं। इसके पूर्व भी साड़ियों के बिल पर भी खूब उठापटक हुई थी।

कभी भी फोन उठाना होगा...

कभी-कभी उतावलापन लोगों पर भारी पड़ जाता है। ऐसे ही उतावलेपन के कारण एक आईपीएस अधिकारी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में फंस गए हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में जैसे ही नए मुख्य सचिव की पदस्थापना हुई, अफसरों में उनका सानिध्य पाने की होड़ मच गई। इसी श्रृंखला में बड़े साहब को ब्रीफ करने के लिए इंटेलीजेंस के एक नहीं बल्कि दो आईजी पहुंच गए। दरअसल, जिस समय आईजी साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे, ब्रीफिंग खत्म होने के बाद सेकी बगारने के लिए साहब से पूछ लिया कि क्या कुछ जरूरी रहा करे तो वाट्सएप कर सकते हैं। तब साहब का माथा ठनका और उन्होंने कहा कि जब आपको बता दिया है कोई भी ऑफिसर किसी भी समय मुझे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकता है तो क्या आवश्यकता है वाट्सएप करने की। साहब की सख्ती को देखकर आईजी साहब दबे पांव वहां से निकल लिए। जबकि व्यवस्था के अनुसार मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह की ब्रीफिंग गुप्त वार्ता महानिरीक्षक ही करते हैं। पर साहब ने कभी इस तरीके की ब्रीफिंग ली नहीं है। साहब के सख्त स्वभाव को देखकर पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया है। क्योंकि साहब को लिपी-चुपड़ी बात पसंद नहीं है।

अपने ही जाल में फंसे...

कभी-कभी अफसरों की चालाकी उन पर भारी पड़ जाती है। ऐसी ही चालाकी के जाल में 2011 बैच के एक आईपीएस अधिकारी फंस गए हैं। दरअसल, साहब प्रदेश के एक सीमावर्ती जिले में पुलिस कप्तान के पद पर पदस्थ थे। वहां कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद सरकार ने उनका ट्रांसफर राजधानी में कर दिया। लेकिन उन्होंने आदेश की अनसुनी कर तत्काल आने की बजाय रिलीव होने में 2-4 दिन लगा दिए। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी दिखाई। और यह तक आला अफसरों को कह दिया कि इससे स्पष्टीकरण मांगा जाए। सूत्रों का कहना है कि साहब ओवर कॉन्फिडेंस के कारण फंस गए हैं। वहीं बताया जाता है कि जब साहब अपनी पदस्थापना वाले जिले से रिलीव हुए तो वहीं से सेक्रेटरी होम को फोन लगाना शुरू कर दिया और रास्तेभर उन्हें फोन कर-करके अपने लिए मकान मांगते रहे। इससे होम सेक्रेटरी परेशान हो उठे। बताया जाता है कि साहब को मकान तो अलॉट कर दिया रिक्त होने की प्रत्याशा में। यहां ये बता दें कि बल्लम संप्रदाय के अफसरों से पंगेबाजी पुलिस कप्तान को कितनी महंगी पड़ी।

रसूख पर फिर गया पानी

बुंदेलखंड के एक संपन्न जिले में कुछ साल पहले तक जिस नेता का रसूख सातवें आसमान पर था, आज उस पर पानी फिर गया है। माननीय की प्रदेश की राजनीति में हैसियत यह थी कि उनकी एक तरफा तूती बोलती थी। अपने इस रसूख में साहब इस कदर निरंकुश हो गए थे कि उन्होंने अपने जिले के कई नेताओं को धूल चटाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी। खासकर एक कांग्रेसी नेता के खिलाफ तो इन्होंने अभियान ही चला रखा था। लेकिन समय की जरूरत को देखते हुए उक्त नेताजी माननीय की पार्टी में शामिल हो गए हैं। यही नहीं अब उक्त नेताजी जिले में नंबर-1 की पोजिशन पर आ गए हैं। वहीं जिस माननीय का जिले में एकक्षत्र राज था, वे पीछे हो गए हैं। आलम यह है कि विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भी उन्हें मंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई है। कुछ साल पहले तक प्रदेश की राजनीति में दमखम के साथ दूसरे नेताओं के लिए चुनौती बनकर खड़े रहने वाले ये माननीय आजकल अन्य स्थानीय नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। आलम यह है कि समय को देखते हुए माननीय ने भी अपने आपको सीमित कर रखा है।

कंडम गाड़ियों के भरोसे डायल-100

मप्र में अपराध, हादसे और आपदा में लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) डायल-100 पटरी से उतर चुकी है। डायल-100 में उपयोग लाए जाने वाले वाहन पुराने हो गए हैं। इसका असर यह हो रहा है कि ये जहां-तहां खड़ी हो जाती हैं। शहरों में महज 5 और गांवों में अधिकतम 30 मिनट में पुलिस पहुंचने के दावे अब सिर्फ कागजों पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र तो दूर की बात... इंदौर, उज्जैन जैसे शहरों में भी डायल-100 कहीं पहुंच नहीं रही तो कहीं इतनी देर कर रही है कि तब तक घटना हो चुकी होती है। देरी की वजह से कई बार जान तक संकट में पड़ रही है। डायल-100 की इस दुर्दशा के पीछे की वजह यह है कि जिस कंपनी को काम दिया गया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पूरा हो चुका है। 3 साल से कंपनी एक्सटेंशन पर चल रही है। इसने 2015 में प्रदेशभर में 1,000 वाहन लगाए थे, लेकिन अब आधे से ज्यादा वाहन कंडम हो चुके हैं या सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं हैं। फिर भी कंपनी को हर महीने 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार दे रही है। अभी भी 250 से अधिक वाहन ऑफ रोड हैं। इससे रिस्पॉन्स टाइम बढ़कर 17 मिनट से अधिक हो गया है। अप्रैल, मई और जून में तो यह 30 मिनट से अधिक था। गाड़ियां ऑफ रोड होने के बाद कुछ किराए के वाहन भी लगाए गए हैं।

मप्र में डायल-100 सेवा की शुरुआत 2015 में हुई। पुणे की कंपनी भारत विकास ग्रुप (बीवीजी) को काम मिला था। वाहनों के बेड़े में 1,000 टाटा सफारी शामिल की गई थीं। कॉल सेंटर का काम भी इसी कंपनी के पास है। 80 कॉल टेकर हैं। यहां रोजाना औसतन 22 हजार कॉल आते हैं, इनमें से तकरीबन 6,000 कॉल्स ऐसे हैं, जिनमें पुलिस की तुरंत सहायता की दरकार होती है। वर्ष 2020 में कंपनी का ठेका खत्म हो गया था, पर नई कंपनी का चयन नहीं होने से हर छह महीने में एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मेसर्स बीवीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कार्यकाल 30 सितंबर तक था, उसके बाद कंपनी के काम को आगे नहीं बढ़ाया गया है। नए वाहनों के संचालन के लिए नया टेंडर भी जारी नहीं किया गया है। खास बात यह कि तत्कालीन **मुख्य सचिव** वीरा राणा ने 27 सितंबर को काम को आगे बढ़ाने वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में डायल-100 में संचालित होने वाले वाहन पूरी तरह से अवैध हो गए हैं। ऐसे में अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा।

मप्र में डायल-100 सेवा शुरू होने के बाद से बीवीजी कंपनी वाहनों के संचालन का जिम्मा संभाल रही है। कंपनी का कार्यकाल साल 2020 में पूरा हो गया था। उसके बाद नई कंपनी नहीं आने के कारण तीन वर्ष तक छह-छह माह के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। साल 2020 का दौर कोरोना वायरस संक्रमण का था। इस कारण नया टेंडर जारी नहीं हो पाया था। लिहाजा तय किया गया कि बीवीजी कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उसके बाद से कार्यकाल छह-छह महीने के लिए लगातार बढ़ाया जाता रहा है। कंपनी का कार्यकाल 30 सितंबर 2024 को खत्म हो गया था। सूत्र बताते हैं कि नई कंपनी का चयन करने के लिए सितंबर 2022 में 690 करोड़ रुपए की निविदा निकाली गई थी। तब मामला कानूनी पचड़े में फंस गया। समय आगे बढ़ने के साथ अब यह राशि बढ़कर 1350 करोड़ रुपए हो गई है। जब बारी नया टेंडर जारी करने की आई, तो वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

वित्त विभाग की ओर से बार-बार क्वैरी करने के कारण समय और बढ़ता चला गया। पीएचक्यू के अधिकारियों का कहना है कि समय बढ़ने के साथ टेंडर में नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे वाहनों के संचालन का खर्च बढ़ गया है। बताते हैं कि 1350 करोड़ रुपए की राशि भी कम पड़ गई है। अब 1640 करोड़ रुपए का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि कब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, कब बैठक होगी और कब टेंडर जारी करने को मंजूरी मिलेगी। डायल-100 की गाड़ियां 15 दिनों से अवैध संचालित हो रही हैं। तत्कालीन सीएस वीरा राणा ने 27 सितंबर को हस्ताक्षर करने से इनकार किया था। नए टेंडर में दो हजार गाड़ियां संचालित करने का फैसला किया गया था। इसको लेकर टेंडर जारी होना है। टेंडर की शर्तों के अनुसार पहले चरण में 1500 वाहन आने थे और दूसरे चरण में 500 वाहन बुलाए जाने थे। शासन के स्तर पर यह क्वैरी की गई थी कि गाड़ियां कौन सी लगनी हैं और शुरुआती बजट कितना होगा। पीएचक्यू से जवाब भेजा गया, उसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी कारण नए वाहनों के संचालन के लिए अभी तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। लिहाजा पुरानी कंपनी का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

● **सुनील सिंह**

पूर्व सीएस ने नहीं किया हस्ताक्षर

माना जा रहा था कि कंपनी का कार्यकाल छह महीने के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पीएचक्यू से प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था। 30 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के महज तीन दिन पहले यानी 27 सितंबर को कंपनी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए फाइल तत्कालीन मुख्य सचिव वीरा राणा के पास पहुंची थी। तब मुख्य सचिव ने फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अब स्थिति यह है कि 30 सितंबर को कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कार्यकाल आगे बढ़ाने का नया आदेश जारी नहीं किया गया है। अब तक नया टेंडर भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए नई कंपनी के आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि पुरानी कंपनी काम बंद कर देगी। बहरहाल पुरानी कंपनी ने काम बंद नहीं किया है। वाहनों का संचालन नियमित तौर पर जारी है। चूंकि आदेश जारी नहीं हुए हैं, इसलिए वाहनों का संचालन अवैध है। ऐसे में समस्या यह आएगी कि कंपनी को भुगतान कैसे किया जाएगा।

बदलेंगी जिलों की हदें

मप्र में एक बार फिर से परिसीमन की तैयारी हो रही है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा। एसीएस रैंक के रिटायर्ड अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग की अनुशंसा के आधार पर जिलों का गठन होगा। सूत्रों का कहना है कि मप्र की जनसंख्या 7.80 करोड़ है। ऐसे में सरकार ने हाल ही में जिन नए जिलों का गठन किया है, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, प्रदेश में जिस तरह पिछले कुछ सालों से नए जिलों का गठन किया जा रहा है, उससे खर्च का बोझ निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जिलों की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिसीमन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए नए परिसीमन आयोग का गठन किया है। जिलों और संभागों का पुन: परीक्षण कर, हम आपकी भलाई के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की नींव रख रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर कोना प्रगति की ओर बढ़े। परिसीमन आयोग संभाग और जिलों का अध्ययन करेगा। एसीएस रैंक के रिटायर्ड अफसर मनोज श्रीवास्तव को आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जनता अपना सुझाव आयोग को दे सकती है। जिलों के सीमांकन से जनता की कठिनाइयां दूर होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मप्र का अपना क्षेत्रफल तो है लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। जिले तो बढ़ गए लेकिन जिलों की अपनी सीमाएं हैं, कई विसंगतियां हैं। कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। ऐसी कई विसंगतियों के लिए हमने नया परिसीमन आयोग बनाया है, जिसके माध्यम से आसपास के स्थानों को आसपास के जिलों से जोड़कर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहते हैं कि संभागों और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा। सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी कठिनाइयां हैं, जिन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोग के माध्यम से दूर किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अब कई जिलों और संभागों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी। आम जनता अपने सुझाव मनोज श्रीवास्तव को दे सकेगी। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी परिसीमन के मुद्दे पर कहते हैं कि यह सरकार का इंटरनल प्रोसेस है। हर जिले का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में लगातार कई स्थानों को जिला बनाए जाने की मांग उठती आ रही है। परिसीमन आयोग के बाद फिलहाल इन मांगों पर भी लगाम लग गई है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पहले जिलों और संभाग की नई सीमाएं तय होंगी और इसकी सिफारिश पर ही नए जिलों का गठन किया जाएगा। प्रदेश में सागर जिले में ही बीना या खुरई को जिला बनाने की मांग जोरशोर से उठती आई है। इसके अलावा गुना में चांचौडा, छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव, छतरपुर में लवकुशनगर, नागदा, मनावर को जिला बनाने की मांग उठती रही है।

मप्र में जिलों और संभागों का पुनर्गठन होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के संभागों और जिलों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी जिसके लिए परिसीमन आयोग गठित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा उनके बीना दौरे के ऐन पहले की। गौरतलब है कि सागर जिले की बीना तहसील को जिला घोषित किए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इतना ही नहीं, बीना सहित प्रदेश की करीब एक दर्जन तहसीलों को जिला बनाने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक प्रदेश के सभी संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग बना दिया है। तीन सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष मप्र के सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव होंगे। अन्य दो सदस्य बाद में नियुक्त किए जाएंगे।

प्रदेश में कई संभागों, जिलों की सीमाओं के आकार में खासा अंतर है। भौगोलिक दृष्टि से कई जिले बहुत छोटे हैं जबकि इंदौर जैसे कुछेक जिले आकार में बहुत बड़े हैं। राजनीतिक मांगों के बाद बनाए गए कुछ नए जिलों के कारण सीमाओं में कमीबेशी हो गई है। इससे न केवल प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं बल्कि आमजन भी परेशान हो रहे हैं। इन दिक्कतों को दूर करने की जिम्मेदारी परिसीमन आयोग को सौंपी गई है। यह आयोग राज्य के सभी संभागों, जिलों की सीमाओं का जायजा लेगा। जिलों, संभागों का निरीक्षण करके आमजन और प्रशासन की सहूलियत के नजरिए से उनकी सीमाओं का उचित निर्धारण भी करेगा। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार अंतिम फैसला लेगी।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

क्या है परिसीमन आयोग?

अब आपको बताते हैं कि परिसीमन होता क्या है। दरअसल किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण या पुनर्निर्धारण को ही परिसीमन कहा जाता है। यह विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं को दोबारा तैयार करने का प्रोसेस है। परिसीमन किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या चुनावी क्षेत्र के निर्धारण करने उसमें जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने और उसमें बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है। मप्र में अभी 55 जिले हैं जिनमें 3 जिले मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर पिछले साल बनाए गए। इधर प्रदेशभर में नए जिलों के गठन की मांग की जा रही है। सागर, खरगोन जैसे बड़े जिलों को तो कई टुकड़ों में बांटे जाने की मांग है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, छतरपुर, गुना और धार में भी तहसीलों को जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। प्रदेश में करीब एक दर्जन नए जिलों के लिए राजनीतिक कवायद चल रही है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद इनमें से कुछ तहसीलों को जिला बनाना तय है।

सुशासन के लिए होगी नई जमावट

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुशासन का जो मंत्र दिया है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव अनुराग जैन की है। मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के साथ ही अनुराग जैन जिस तरह ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं उससे तो साफ हो गया है कि प्रदेश में कर्तव्यनिष्ठ अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे में प्रदेश की नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी है। इस बदलाव में मुख्य सचिव अपनी पॉलिसी के तहत अफसरों की जमावट करेंगे। सूत्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कराना मुख्य सचिव की प्राथमिकता है। इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि मंत्रालय से लेकर फील्ड तक ऐसे अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, जो सरकार की मंशा के अनुसार काम कर सकें। पिछले एक वर्ष से उद्योगों की स्थायी पूंजी निवेश पर वित्तीय सहायता दी जाती थी, उन फाइलों को कई महीनों से अटकाकर रखा हुआ था, जबकि वित्तीय सहायता के नियम बने हुए हैं। किस-किस उद्योग को वित्तीय सहायता कितने वर्षों में देना है। साहब ने छुट्टी के दिन उन सारे उद्योगों की वित्तीय सहायता की फाइलों को निपटा दिया।

वहीं पर अपने अधीनस्थ अफसरों को निर्देशित किया कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में किसी भी स्थानांतरण की फाइल विधायक या मंत्री की अनुशंसा की हुई लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विधायक द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में शिकायत की गई है, तो अपने अमले को भेजकर चेक कराइए और विधायक की शिकायत सही पाई जाती है तो दंडित भी करें। परंतु फिजूल में स्थानांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यहां यह भी कहा कि ए+ स्थानांतरणों के लिए पहले अपनी रिपोर्ट संलग्न करें। ताकि कार्रवाई करने में आसानी हो सके।

गौरतलब है कि मुख्य सचिव महोदय को खनिज, परिवहन, आबकारी एवं नगरीय प्रशासन के कार्यों के लिए भी कोई कठोर पॉलिसी बनने जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों की इन विभागों से जुड़े हुए क्रियाकलापों की मॉनीटरिंग होती रहती है। जिससे सुशासन में पारदर्शिता आ सके। यानि प्रशासन में पूरी पारदर्शिता होगी। इसकी पहली झलक मुख्य सचिव के आने के बाद आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में देखने को मिली। ड्राइवर की औकात पूछने वाले जिस आईएएस अधिकारी किशोर कन्याल को हटाया गया था, उन्हें श्योपुर कलेक्टर बना दिया गया। वहीं, उनकी जगह पर श्योपुर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को निवाड़ी कलेक्टर बनाया गया, क्योंकि आने वाले समय में श्योपुर में उपचुनाव होना है। इसके मद्देनजर जांगिड़ को वहां से हटाकर निवाड़ी किया गया है। वहीं प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु जिन तीन युवा आईएएस अफसरों पर पत्थरबाजी करने के कारण पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई थी, उन्हें भी पदस्थ किया गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की उम्मीद पिछले कुछ महीने से लगाई जा रही है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अब जल्द ही तबादले की सूची जारी की जाएगी। इस प्रशासनिक फेरबदल में मंत्रालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी और जिला कलेक्टर प्रभावित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दिसंबर, 2003 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार रीसेट मोड में बनी हुई है। दिसंबर से अगस्त के बीच करीब 200 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जबकि लगभग 10 महीने में स्थानांतरित आईएएस अफसरों की कुल संख्या 300 से अधिक है। दिसंबर के बाद से बड़ी संख्या में तबादलों में वह अवधि भी शामिल है, जब मार्च और जून के बीच आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू रही और कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। यानी आईएएस अफसरों के तबादले दिसंबर से मार्च मध्य और जून से सितंबर के बीच किए गए।

पसंद के अफसरों को प्राथमिकता

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक स्थिरता लाने के लिए अफसरों की नई पदस्थापना की जाएगी। अफसरों की नई पदस्थापना में सीएस जैन की पसंद को भी तवज्जो मिलेगी। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कई अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के पास एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है। पिछले महीनों में कई अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने के बाद उनके विभाग का जिम्मा अतिरिक्त प्रभार के रूप में अलग-अलग अधिकारियों को सौंप दिया गया है। ऐसे ही एक दर्जन से ज्यादा कलेक्टरों को बदलने की तैयारी जुलाई-अगस्त से चल रही है, लेकिन अलग-अलग कारणों से सरकार ऐसा नहीं कर पाई। इसमें नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होना एक प्रमुख कारण था।

मास्टर प्लान की प्रत्याशा धारा-16 की अनुमति

भोपाल एवं इंदौर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। राज्य सरकार ने बकायदा पत्र लिखकर विभाग को सूचित कर दिया है, परंतु इस समय विभाग में धारा-16 से वारे-न्यारे हो रहे हैं। इसी सप्ताह धारा-16 के 40 आवेदनों पर विचार कर 3 दिनों में उन्हें निपटा दिया। और उक्त आवेदनकर्ताओं को धारा-16 में अनुमति जारी हो गई। इसी तरह मास्टर प्लान की प्रत्याशा में लगभग प्रदेश में 200 से 250 प्रकरणों पर सुनवाई कर धारा-16 में अनुमति दे दी गई। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि धारा-16 में नोट बरस रहे हैं। पहले तो धारा-16 के लिए आवेदन के उपरांत ठोक-बजाकर निर्णय दिया जाता था पर अब जो जितना लाए उतना ले जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवा तुर्क अफसरों ने कहीं-कहीं अपनी मनमर्जी से ये कार्य तो चालू नहीं कर दिया, क्योंकि एक वर्ष पूर्व अगर देखा जाए शिवराज की सरकार में धारा-16 के प्रकरणों लगभग आधा दर्जन प्रकरणों पर सुनवाई कर निर्णय दिया गया था। आखिर करके डायरेक्टर नगर तथा ग्राम निवेश को अपने आगे के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। और लगातार धारा-16 के प्रकरणों पर सुनवाई कर आदेश पारित कर दिए जावें। जबकि मप्र शासन के उपसचिव का पत्र 9 फरवरी 2024 को गौर करें तो उन्होंने नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियमों के अनुसार भोपाल विकास योजना 2031 (प्रारूप) आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश को कुछ निर्देशों के साथ वापस कर दिया। फिर भी धारा-16 से मास्टर प्लान आने से पूर्व मास्टर प्लान को बिगाड़ा जा रहा है।

नए डीजीपी के लिए जल्द जाएगा प्रस्ताव

मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद अब प्रदेश में पुलिस महानिदेशक की खोज शुरू हो गई है। जल्द ही इसके लिए नामों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसको देखते हुए उनके स्थान पर नए पुलिस महानिदेशक के लिए उन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम छह माह बाकी हों। इस आधार शैलेष सिंह, सुधीर कुमार शाही और विजय कटारिया दौड़ से बाहर हैं। 1988 बैच के अरविंद कुमार, कैलाश मकवाना, 1989 बैच के अजय कुमार शर्मा, गोविंद प्रताप सिंह, 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, आलोक रंजन और प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव के साथ ही 1991 बैच के ही योगेश मुद्गल अगर स्पेशल डीजी बनते हैं, उनका नाम भी प्रस्तावित किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करके सेवा अभिलेख में कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे- लॉ एंड ऑर्डर, जिला या जोन रेंज में, अपराध, अपराध जांच, सीआईडी, महिला अपराध, ईओडब्ल्यू, साइबर, रेलवे, लोकायुक्त, गुप्त वार्ता, विशेष शाखा, नक्सलवाद और भारत सरकार में इन तमाम एजेंसियों और रिसर्च आदि में कार्य करने के उपरांत ही इन नामों पर विचार किया जाता है। यह अवधि इन सभी में मिलाकर 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस पैनल को भारत सरकार को भेजा जाता है, वहां से तीन नामों का पैनल बनकर राज्य सरकार को वापस किया जाता है, फिर सरकार के पाले में गेंद होती है, कि इस वरीयता और योग्यता से नियुक्ति होती है।

अरविंद कुमार

कैलाश मकवाना

अजय कुमार शर्मा

योगेश देशमुख बने एडीजी इंटेलीजेंस

प्रदेश सरकार ने करीब दो सप्ताह से खाली पड़े एडीजी इंटेलीजेंस के पद पर 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी योगेश देशमुख की नियुक्ति कर दी है। 11 अक्टूबर की देर रात गृह विभाग ने योगेश देशमुख को एडीजी इंटेलीजेंस बनाने के आदेश जारी किए। इससे पहले, जयदीप प्रसाद इस पद पर कार्यरत थे, जिन्हें लोकायुक्त का प्रभारी डीजी बनाए जाने के बाद से यह पद रिक्त था। अभी तक योगेश देशमुख भोपाल में पुलिस मुख्यालय के सायबर सेल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत उन्हें अब एडीजी इंटेलीजेंस का पदभार सौंपा गया है। इससे पहले एडीजी इंटेलीजेंस का पद संभाल रहे जयदीप प्रसाद को हाल ही में लोकायुक्त का प्रभारी डीजी नियुक्त किया गया था। उनके इस स्थानांतरण के बाद से एडीजी इंटेलीजेंस का पद रिक्त था। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

जनवरी में इनका प्रमोशन

अगले साल यानि वर्ष 2025 में मप्र कैडर के आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन होगा। यह प्रमोशन जनवरी में होगा। जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद के आईपीएस अधिकारी स्पेशल डीजी बनेंगे। इसमें 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी स्पेशल डीजी बनाए जाएंगे। जिन अधिकारियों को स्पेशल डीजी बनाया जाएगा, उनमें पंकज कुमार श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, पवन कुमार श्रीवास्तव, मनीष शंकर शर्मा, जी अखेतो सेमा, डीसी सागर आदि का नाम शामिल है। इसी तरह 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजी बन जाएंगे। इसमें संतोष सिंह और एसपी सिंह का नाम शामिल है। वहीं 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी डीआईजी से आईजी बनेंगे। इनमें सचिन कुमार अतुलकर, रूचिका जैन, कुमार सौरभ, कृष्णा वेनी देसावतु आदि शामिल हैं। इसी तरह 2010-11 बैच के आईपीएस अधिकारी डीआईजी हो जाएंगे। इन अधिकारियों की पदस्थापना के साथ ही पीएचक्यू में भी सर्जरी होगी। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय में सर्जरी हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आने वाले समय में पीएचक्यू में पदस्थ अफसरों के कार्यों में बदलाव किया जाएगा। पीएचक्यू के साथ ही मैदानी पोस्टिंग में भी बदलाव करने की तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि सरकार जिलों में पदस्थ आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य आईपीएस अधिकारियों का तबादला करेगी।

आईपीएस की डीपीसी जल्द ही होगी

राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के लिए होने वाली डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक दीपावली के आसपास हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने एसपीएस को आईपीएस अवार्ड के लिए दावेदार अफसरों के नाम शार्टलिस्ट कर भेज दिए हैं। 4 पदों के लिए होने वाली डीपीसी बैठक के लिए एमपी से 12 अफसरों के नाम सिलेक्ट किए गए हैं।

● राजेन्द्र आगाल

तू डाल-डाल... मैं पात-पात

उपरोक्त कहावत की तरह मप्र की राजनीति में नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। सार्वजनिक मंचों पर नेता भले ही एक दिख रहे हैं, लेकिन उनके बीच की खाई काफी गहरी है। इसका नजारा अभी हाल ही में उस समय देखने को मिला, जब ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच टी-20 का मैच हुआ। महाराजा यानि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में हुए इस मैच में ऐरे-गैरे नत्थू खैरे, सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन ग्वालियर-चंबल अंचल के कद्दावर नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर क्षेत्रीय राजनीति गर्माने लगी। जब यह बात सार्वजनिक होने लगी तो सिंधिया ने उन्हें मैच देखने के लिए फोन कर आमंत्रित किया। तू डाल-डाल... मैं पात-पात की तर्ज पर तोमर ने भी अपने समर्थक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हवाला देकर सिंधिया से 60-70 पास मांग लिए। लेकिन सिंधिया ने उन्हें 10-20 पास ही भिजवाए, तो इस पर तोमर ने भी उन्हें करारा जवाब देते हुए उसे अस्वीकार कर दिया और मैच भी देखने नहीं गए।

बजट के लिए अफसरों की दिल्ली दौड़

केंद्र सरकार से अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए अब मंत्री अकेले दिल्ली नहीं जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए जो नई व्यवस्था की है उसके अनुसार अब मंत्रियों के साथ विभागीय अफसर भी जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 2024-25 बजट में मप्र को 97 हजार 906 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले वर्ष 2023-24 में मिले 86 हजार 792 करोड़ से 11 हजार 204 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। वहीं प्रदेश को भारत सरकार से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होना है। प्रदेश का वर्ष 2024-25 में 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक भारत सरकार से प्राप्त होने हैं। 95 हजार 753 करोड़ रुपए वर्षभर में केंद्रीय करों के हिस्से में मिलने हैं। इस बजट को लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के छह माह बीत चुके हैं। मप्र सरकार में आगामी बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं तो केंद्रीय मंत्रियों से लगातार भेंट कर ही रहे हैं, सभी मंत्रियों और अधिकारियों से भी कहा है कि वे स्वीकृत योजना का बजट जल्द प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों से सतत् संवाद करें। आवश्यकता के अनुसार दिल्ली भी जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे भारत सरकार के बजट में प्रविधानित राशि समय पर मिले ताकि उसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में हो जाए, इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क किया जाए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी अधिकारियों को केंद्रीय अधिकारियों से संवाद और संपर्क रखने के लिए कहा है।

प्रदेश सरकार पर भारी कर्ज है। वहीं सरकार हर साल कर्ज लेकर विकास कार्यों पर खर्च कर रही है। ऐसे में सरकार का फोकस इस बात पर है कि केंद्र से मिलने वाले बजट को समय पर लाया जाए। इसके लिए अब मंत्रियों के साथ विभागीय अफसर भी जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश को भारत सरकार से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होना है। प्रदेश का वर्ष 2024-25 में 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक भारत सरकार से प्राप्त होने हैं। 95 हजार 753 करोड़ रुपए वर्षभर में केंद्रीय करों के हिस्से में मिलने हैं। जबकि, 44 हजार 891 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता अनुदान रहेगा। विशेष केंद्रीय सहायता योजना में भी 10 हजार 910 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें से 4,318 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश को 10,500 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, जिनमें 9,750 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं। 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए रोपवे के लिए 50 करोड़ और पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रविधान है।

सेतु बंधन योजना में फ्लाई ओवर समेत अन्य परियोजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों में संचालित केंद्रीय योजनाओं के लिए भी राशि का प्रविधान है। इस वित्तीय वर्ष में 5 साल में केंद्र सरकार मप्र को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए 29 हजार 710 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसमें मप्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 हजार 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें लोक निर्माण विभाग को 3390 करोड़ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 7710 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें उज्जैन महाकाल के रोपवे, पांच रिंग रोड के लिए भी राशि शामिल है। बता दें, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे के लिए पहले ही एमओयू हो चुका है। इसके बनने से स्टेशन से मंदिर तक सड़क पर दबाव कम होने के साथ ही श्रद्धालुओं का समय भी बचेगा। रोपवे से 25 मिनट की जगह 7 मिनट में ही श्रद्धालु स्टेशन से मंदिर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रिंग रोड के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।

उधर, प्रदेश के वित्त विभाग ने वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जो अनुमानित राशि विभाग को बताई गई है, उसके अनुसार बजट 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। इसी हिसाब से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस कृषि, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहेगा। बजट प्रस्तुत होने से पहले भोपाल में 7-8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। इसमें देश-दुनिया के बड़े उद्योगपति जुटेंगे और प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग सवा दो लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव भी सरकार को मिल चुके हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

कर्मचारियों को मिलेगी सौगात

मप्र के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वित्त विभाग बड़ा तोहफा देने जा रही है। कर्मचारियों को अगले बजट यानी साल 2025-26 में 64 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पेंशनरों के लिए भी इसी हिसाब से महंगाई पर राहत देने की व्यवस्था हो रही है। सभी विभागों में वेतन-भत्ते के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को मंहगाई से राहत देने के लिए 56 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान रखा गया है, ताकि वे महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकें। फिलहाल, राज्य सरकार का मंहगाई भत्ता 46 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर चुकी है। मप्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की राशि रखने का आदेश दिया है। इससे 18 प्रतिशत तक का फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक वेतन में वृद्धि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की तरह ही प्रावधान रखा जाएगा। प्रदेश के कर्मचारी भी चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में फैसला ले लिया गया है और मुख्यमंत्री दीपावली के पहले इस आशय की घोषणा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की ही तरह प्रावधान रखने का तय किया जा रहा है।

सरकार की नाक के नीचे एमडी ड्रग्स का गोरखधंधा

राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा से ड्रग्स का काला कारोबार संचालित करने वाले मास्टरमाइंड हरीश आंजना और सान्याल बाने ने भोपाल के पहले पीथमपुर की फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने की तैयारी की थी। उन्होंने वहां फैक्ट्री तलाश भी की थी और ड्रग बनाने का कच्चा माल भी मंगवा लिया था, परंतु वे रसायन के जानकार नहीं थे, जिसके चलते ड्रग बनाने में नाकाम हो गए। इसके बाद उन्होंने रसायन के विशेषज्ञ अमित चतुर्वेदी को अपने गिरोह में शामिल किया और भोपाल को ड्रग बनाने के लिए चुना था। बता दें कि एनसीबी व गुजरात एटीएस ने ड्रग्स फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए 1814 करोड़ रुपए कीमत की खतरनाक एमडी ड्रग्स जब्त की है। साथ ही तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही भोपाल पुलिस ने गोदाम पर कार्रवाई करते हुए 300 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स का माल पकड़ा है। एनसीबी और पुलिस से पूछताछ में आरोपितों ने ड्रग तस्करी को लेकर कई खुलासे किए हैं। वे 15 अक्टूबर तक रिमांड पर रहे।

पुलिस के अनुसार मंदसौर का रहने वाला हरीश आंजना ड्रग्स के काले कारोबार का मास्टरमाइंड है। उसका पिता भी अफीम तस्करी से जुड़ा था और कई बार जेल गया था। हरीश जेल में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर शोएब लाला के संपर्क में आया था। उसके माध्यम से हरीश नासिक के सान्याल बाने से मिला। दोनों ने मिलकर पीथमपुर में ड्रग्स बनाने की योजना बनाई थी। बाद में उन्होंने अमित चतुर्वेदी को भी शामिल किया। अमित एमएससी है और रसायन का जानकार है। तीनों के अलग-अलग काम थे और उस काम के अनुसार ही लाभांश का वितरण होता था। इसमें सबसे अहम हरीश का काम था, क्योंकि वह माल को खपाता था। जबकि अमित व सान्याल ड्रग्स तैयार करते थे और कच्चे माल का प्रबंध करते थे। पूछताछ में आरोपितों ने ड्रग्स की दो खेप सप्लाई करना कबूल किया है। उन्होंने बताया कि वे मंदसौर के रास्ते महाराष्ट्र और गुजरात में ड्रग सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि पहली खेप इसी वर्ष मार्च में भेजी गई थी, जिसे कूलर में रखकर सप्लाई किया गया था। उसके कुछ दिनों बाद डबल डेकर वाहन में ड्रग्स को ऊपर रखकर तस्करी की गई। तीसरी खेप तैयार थी और उसे जल्द ही खपाया जाना था।

राजधानी भोपाल ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 1800 नहीं करीब चार हजार करोड़ की ड्रग्स थी। 2200 करोड़ के ड्रग्स बनाने की आखिरी प्रोसेस बची थी। वहीं ड्रग्स जाल के नए किरदार सामने आए हैं। ड्रग्स गैंग के तार राजस्थान के शोएब लाला से जुड़ा बताया जा रहा है। भोपाल ड्रग्स मामले में एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स 1800 नहीं बल्कि करीब 4 हजार करोड़ की थी। 2200 करोड़ के ड्रग्स बनाने की आखिरी प्रोसेस बची थी। 2200 करोड़ की ड्रग्स मशीन में थी। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के काम बंटे हुए थे। हरीश अंजाना के पास ड्रग्स सप्लाई का काम था। सान्याल बाने कच्चे माल से ड्रग्स बनाने का काम करता था। अमित चतुर्वेदी ड्रग्स बनाने के लिए कच्चा माल लाता था। आरोपी ज्यादातर माल विदेश में सप्लाई करते थे। ज्यादा कीमत के लिए विदेश में ड्रग्स बेचा जाता था। ड्रग्स मामले के तार राजस्थान से जुड़े बताए जा रहे हैं। गैंग का सरगना शोएब लाला बताया जा रहा है। प्रेमसुख पाटीदार नाम के शख्स की भी तलाश है। प्रेमसुख पाटीदार, हरीश आंजना के संपर्क में था। प्रेमसुख पाटीदार नाम का शख्स ड्रग्स सप्लाई में लिप्त बताया जा रहा है। ड्रग्स सप्लाई में हवाला नेटवर्क की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एजेंसियां हवाला नेटवर्क तलाशने में जुटी हुई हैं। भोपाल में 1800 करोड़ की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स गुजरात एटीएस और दिल्ली की एनसीबी की टीम ने पकड़ी। मप्र के अफसरों को इस फैक्ट्री के बारे में पता ही नहीं था। इस फैक्ट्री पर छापे की खबर भी गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी की पोस्ट से लगी। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे नशे के कारोबार का इंदौर और भोपाल जैसे शहरों का खुफिया तंत्र पता नहीं लगा पाया, जबकि फैक्ट्री में बनने वाली ड्रग के लिए कच्चा माल इंदौर और उज्जैन से आता था।

नशे के कारोबार के आरोपी अमित चतुर्वेदी का इंदौर के कई केमिकल व्यापारियों से संपर्क है। वह सीधे इंदौर से फैक्ट्री में कच्चा माल मंगवा लेता था। इसकी भी जानकारी संबंधित विभागों को नहीं लगी। इस बड़ी खेप के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले माह प्रदेश में 15 आईपीएस के तबादले हुए थे। जिसमें एडीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे जयदीप प्रसाद को लोकायुक्त संगठन का प्रभारी पुलिस महानिदेशक बनाया गया, लेकिन एडीजी इंटेलिजेंस की पोस्ट पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। जब मुखिया की कुर्सी ही खाली रहेगी तो फिर टीम कैसे फील्ड में मजबूत रह सकती है। प्रदेश के पूर्व डीजीपी एसके दास का इस बारे में कहना है कि पुलिस विभाग में यह पद काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लंबे समय तक इनकी कुर्सी खाली नहीं रखी जानी चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

● **अरविंद नारद**

पुलिस वाले जिसे मिश्री की डली समझते रहे, वो निकली एमडीएमए

मंदसौर जिले की पुलिस डोडाचूरा, अफीम व स्मैक को जब्त करने में तो सिद्धहस्त है पर कुछ ही वर्षों में चलन में आई एमडीएमए सिंथेटिक ड्रग की पहचान करने वाले एक्सपर्ट पुलिसकर्मी नहीं है। जिले में पुलिस के पास पर्याप्त जांच के लिए किट नहीं है। मिश्री की डली जैसी दिखने वाली एमडीएमए की प्रारंभिक पहचान भी हर कोई नहीं कर सकता है। यही कारण है कि मंदसौर में एमडी का नशा काफी तेजी से फैलता गया और पुलिस इसे पकड़ भी नहीं पाई। वहीं, पुलिस के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि भोपाल से आई गुजरात एटीएस की भनक हरीश का साथ देने वाले पुलिसकर्मियों को लग जाती, तो वह घर पर नहीं मिलता। जिले में कुछ पुलिसकर्मियों का सपोर्ट व उपमुख्यमंत्री का राजनीतिक वरदहस्त होने के कारण ही हरीश इस मुगालते में था कि अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए राजस्थान के सीमावर्ती गांवों अखेपुर व देवल्दी में पहुंचती है। देवल्दी का शोएब लाला व अखेपुर में रहने वाले कुछ लाला पठान ही एमडीएमए ड्रग को नेटवर्क के जरिए खपा रहे हैं। हरीश आंजना व प्रेमसुख पाटीदार भी शोएब लाला के संपर्क में आने के बाद इस नेटवर्क से जुड़ गए थे। धीरे-धीरे भोपाल के सान्याल और चतुर्वेदी से जुड़कर तस्करी के नेटवर्क के बड़े खिलाड़ी बन गए। जिले की पुलिस, नारकोटिक्स विंग में पदस्थ अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों की परेशानी यह है कि एमडीएमए ड्रग की पहचान नहीं है।

निगम-मंडलों में जल्द होंगी नियुक्तियां

मप्र में लंबे समय से राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे नेताओं को फिर निराशा हाथ लग सकती है। इस निराशा की वजह यह है कि भाजपा ने फिलहाल निगम मंडलों की नियुक्तियों को होल्ड कर दिया है। संभवत: संगठन चुनाव के बाद ही निगम-मंडल और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति होगी। यानी अब अगले वर्ष 2025 में ही भाजपा नेताओं को राजनीतिक कुर्सी का सुख मिल पाएगा। गौरतलब है कि वे प्रदेश में लंबे समय से निगम-मंडल, बोर्ड, आयोग और विकास प्राधिकरणों में ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 8 माह बाद नेताओं को उम्मीद जगी थी कि उन्हें निगम-मंडलों में नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह का संकेत मिल रहा है, उसके अनुसार भाजपा नेताओं को अभी और इंतजार करना होगा। भाजपा अब संगठन चुनाव के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद से निगम-मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में ताजपोशी का सपना पाले बैठे नेताओं को अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा।

सत्ता और संगठन ने निगम-मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में इस साल इन सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीतिक नियुक्तियां ना करने का फैसला किया है। यह फैसला भाजपा के दिल्ली में बैठे आला नेताओं से चर्चा करने के बाद लिया गया है। पिछले छह महीने से इन पदों के लिए सक्रिय दावेदारों को सत्ता और संगठन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब संगठन चुनाव के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा। यही वजह है कि पिछले दिनों सरकार ने मंत्रियों को निगम मंडलों का प्रभार देने का फैसला किया था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में जो नेता किन्हीं कारणों से टिकट से वंचित रह गए थे। वे लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही निगम-मंडल समेत अन्य उपक्रमों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनमें संगठन से जुड़े प्रदेश पदाधिकारी से लेकर पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल हैं। इन नेताओं को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद पार्टी उनके नामों पर विचार करेगी। चुनाव के बाद पार्टी ने इस पर विचार भी शुरू किया और संभाग प्रभारियों से चर्चा कर जिलों से नाम भी निकाले गए। कुछ बड़े नाम स्वभाविक रूप से संगठन की भी नजर में थे।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सत्ता और संगठन ने निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सूत्रों की मानें तो करीब दो दर्जन नामों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय संगठन के आला नेताओं से चर्चा भी की गई पर इसके बाद तय हुआ कि सबसे पहले पार्टी सदस्यता अभियान पर फोकस करेगी। इसके बाद संगठन चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद ही इन नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा। भाजपा का सदस्यता अभियान इन दिनों चल रहा है। पार्टी ने इसके लिए विधायकों से लेकर मेयर और अन्य नेताओं को टारगेट दिया है। मप्र में डेढ़ करोड़ सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य पार्टी ने लिया है। इस अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को समाप्त हुआ। दूसरा चरण 15 अक्टूबर तक चलेगा। सदस्यता अभियान से निपटने के बाद भाजपा संगठन चुनाव में लगेगी। इसमें सबसे पहले बूथ, फिर शक्ति केंद्र, मंडल और जिलों में चुनाव होंगे। इसके बाद प्रदेश संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। भाजपा ने यह भी तय किया है कि बूथ से लेकर मंडल तक में पदाधिकारी बनने के लिए कार्यकर्ता को कम से कम 100 सदस्य बनाना होंगे।

प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए लॉबिंग कर रहे नेताओं को अभी तीन माह इंतजार करना होगा। इसके लिए पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर चल रही कवायद आड़े आ रही है। पार्टी ने अभी सदस्यता अभियान की घोषणा भी नहीं की है। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव होंगे, और इस प्रक्रिया में करीब तीन से चार माह का समय लगना है। माना जा रहा है कि जिन नेताओं को संगठन चुनाव में जिले और प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी बनाया जाएगा, उन्हें निगम-मंडल में जगह नहीं मिलेगी। वह नेता जो विधानसभा और लोकसभा में टिकट के दावेदार थे लेकिन पार्टी ने उन्हें भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का कहकर उस समय शांत कर दिया था, उनके नामों की पार्टी ने सूची बनाई है, इन पर विचार किया जा रहा है। इसमें कई ऐसे नेता भी है जो दूसरे दल से भाजपा में आए थे। ऐसे नेता अब अपनी ताजपोशी को लेकर काफी चिंतित हैं। कुछ नेता जो संगठन में पदाधिकारी हैं, अब निगम मंडल में अपनी नियुक्ति की लेकर आशांवित हैं, उन्हें भी अभी इंतजार करना होगा।

● **कुमार विनोद**

परफार्मेंस के आधार पर होगी नियुक्ति

पार्टी ने यह भी तय किया है कि सदस्यता अभियान में किस नेता का कैसा परफार्मेंस रहा है यह उसके पद देने का आधार रहेगा। संगठन सूत्रों की मानें तो साधारण तौर पर नए साल तक निगम मंडलों की नियुक्ति पर विराम है, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए नाम अपवाद होंगे। इसक अलावा राज्य महिला आयोग, बाल आयोग समेत कुछ आयोगों में काम की गति को बढ़ाने के लिए इनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि इसमें भी बेहद जरूरी नियुक्तियां ही की जाएंगी। प्रदेश में खाली पड़े निगम-मंडल, बोर्ड, आयोग और विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति चाहने वाले नेताओं की लंबी कतार है। जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी है, वह भी निगम मंडलों में अपनी नियुक्ति चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में उनका प्रभाव बना रहें। हालांकि विधायकों को निगम मंडलों में जगह मिले इसकी संभावना कम ही है। हालांकि शिवराज सरकार में दो विधायकों को निगम मंडल की जिम्मेवारी दी गई थी। भाजपा में कांग्रेस से आए कई नेता जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पाटन के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, अभी हाल ही में अमरवाडा विधानसभा से भाजपा के टिकट पर जीतकर आए कमलेश शाह, लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में आए छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सबसे खास माने जाने वाले दीपक सक्सेना के अलावा कई ऐसे नेता हैं, जो लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा में आए थे। उन्हें अभी और इंतजार करना होगा।

रातापानी टाइगर रिजर्व को मिलेगी हरी झंडी

मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। इसकी वजह है देश में सर्वाधिक टाइगर अगर कहीं पर हैं तो वे मप्र में ही हैं। प्रदेश में लगातार तेजी से टाइगरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से उनके लिए जगह कम पड़ती दिख रही है जिसकी वजह से वे आवासीय इलाकों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। ऐसे में अब प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व की जरूरत महसूस की जाने लगी है। अच्छी बात यह है कि सरकार के प्रयासों से जल्द ही प्रदेश को दो नए टाइगर रिजर्व मिलने जा रहे हैं। इनके मिलने से प्रदेश में मौजूद सात टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर नौ हो जाएगी। दो नए टाइगर रिजर्व में शामिल रातापानी अभयारण्य को तो टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है, जिसकी सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकती है। राजधानी भोपाल से सटे रातापानी और सिंघौरी अभयारण्य को मिलाकर मप्र का आठवां टाइगर रिजर्व बनाने में आ रही तमाम अड़चनें दूर कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वन विभाग सहित अन्य विभाग प्रमुखों के साथ बैठक कर रातापानी अभयारण्य के संबंध में समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि जब केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है तो फिर राज्य सरकार के स्तर कहां और क्यों लेटलतीफी हो रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो एक माह के अंदर रातापानी टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की जाए। बैठक में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खनिज, जल संसाधन, उद्योग सहित इससे संबंधित विभाग प्रमुख बैठक में उपस्थित थे।

बता दें कि टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव वर्ष 2008 से लंबित है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मप्र सरकार से आग्रह कर चुके हैं। रातापानी को टाइगर रिजर्व रूप में अधिसूचित करने एनटीसीए कह चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जून में हुई राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा, इस अभयारण्य के वनमंडल औबेदुल्लागंज के अंतर्गत 31 ग्राम एवं सीहोर वनमंडल के छह ग्रामों तथा भोपाल वनमंडल के एक ग्राम की सहमति अभी तक नहीं मिल पाई है। इन कुल 38 ग्रामों को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए वन विभाग का अमले ने ग्राम के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर सहमति ली है। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी। वहीं, इससे पहले अभयारण्य में आने वाले अन्य 37 ग्रामों की सहमति ली जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि इन गांवों ने भी पहले ही अनुमति दे दी थी, लेकिन इसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई थी, इसलिए वीडियोग्राफी करके केंद्र सरकार को भेजा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने गांवों की सहमति लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके बाद अधिसूचना की कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एक माह की मोहलत मांगी है, ताकि वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने बताया कि एक माह में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1244.518 वर्ग किमी होगा। इसमें 763.812 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र होगा। इसमें कोई भी राजस्व गांव नहीं होगा। खेती जमीनें और रहवासी बस्तियां टाइगर रिजर्व से प्रभावित नहीं होंगी। कोर में सिर्फ 3 वन ग्राम हैं, जिनकी शिफ्टिंग प्रक्रियाधीन है। बफर क्षेत्र में 32 गांव हैं, जिनमें से 10 गांवों को छोड़कर लगभग सभी अपनी लिखित सहमति वन विभाग को दे चुके हैं। कोर क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा यानी 628.781 वर्ग किलोमीटर हिस्सा रायसेन जिले में आएगा। वहीं सीहोर जिले में सिर्फ 135 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही आएगा। बफर क्षेत्र में भोपाल जिले का सिर्फ 1.7 वर्ग किलोमीटर जंगल ही आएगा। इसलिए टाइगर रिजर्व बनने पर भोपाल में किसी भी तरह के प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू नहीं होंगे। रातापानी 80 बाघों का घर है। केंद्र 16 साल पहले इसे टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसके बावजूद वन विभाग नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा था।

● **लोकेश शर्मा**

यह होगा लाभ

रातापानी अभयारण्य के टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन बढ़ेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस अभयारण्य में वर्ष 2022 की गणना के अनुसार कुल 3 हजार 123 वन्यप्राणी हैं। इनमें 56 बाघ, 70 तेंदुए, 8 भेडिया, 321 चिंकारा, 1433 नीलगाय, 568 सांभर और 667 चीतल हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में केवल 3 वन ग्राम ही शामिल किए जाएंगे। कोर में कोई भी राजस्व ग्राम नहीं होगा। इनके पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत बजट उपलब्ध कराएगी और 40 प्रतिशत राज्य का अंश होगा। टाइगर रिजर्व के लिए अभयारण्य की सीमा के अंदर स्थित 823.065 वर्ग किमी वन क्षेत्र को रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। बता दें कि मप्र में आठवें टाइगर रिजर्व को बनाने का प्रस्ताव वर्ष 2008 से लंबित चल रहा है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मप्र सरकार से आग्रह कर चुके हैं। जानकारों के अनुसार रातापानी अभयारण्य के टाइगर रिजर्व बनने से मप्र में पर्यटन बढ़ेगा। यहां से सटे क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। भोपाल तक फ्लाइट कनेक्टिविटी होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। इसके नुकसान भी होंगे, जैसे कि अभयारण्य क्षेत्र में लघु वनोपज का संग्रहण नहीं किया जा सकेगा।

अपने करीब साढ़े नौ महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी नीति, नीयत और सक्रियता से नीति आयोग को भी आश्चर्य में डाल दिया है। क्योंकि 9 महीने के कम अंतराल में शहरी विकास, सस्ती ऊर्जा, कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास और साफ जल देने में मप्र ने अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। नीति आयोग के अनुसार मप्र असंभव को संभव कर रहा है।

मप्र में विकास की बहार...

मप्र ने आर्थिक विकास और गरीबी हटाने की योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ ही शहरी विकास, सस्ती ऊर्जा, कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास और साफ जल देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर देशभर में अपनी अलग छाप छोड़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नीति आयोग भी मप्र की विकास गति को देखकर खुश है। दरअसल, डॉ. मोहन यादव ने 10 महीने पहले जब मप्र के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी तो उन्होंने लीक से हटकर काम करने की राह पकड़ी। उन्होंने क्षेत्र विशेष की सीमाओं से निकलकर प्रदेश के हर क्षेत्र में एक समान विकास की जो रणनीति बनाई उसका परिणाम 10 महीने में ही दिखने लगा है। हाल ही में जारी की गई नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में मप्र शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा और साफ जल उपलब्ध कराने जैसे क्षेत्रों में बेहतर रहा है। ये रिपोर्ट देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही प्रगति के आधार पर जारी की गई है। वहीं प्रदेश अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन के मामले में औसत प्रदर्शन ही कर सका है।

साल 2020-21 में मप्र 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल था। जबकि 2023-24 की रिपोर्ट में अब प्रदेश फ्रंट रनर राज्य बन गया है। मप्र ने 100 में से 67 अंक हासिल किए हैं। रिपोर्ट की मानें तो मप्र शहरी-सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उत्पादन, न्यायिक संस्थानों की स्थापना, जनता को स्वच्छ ऊर्जा और साफ पीने का पानी देने में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसी तरह आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू करने में भी प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा है। गरीबी हटाने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में भी राज्य का प्रदर्शन अच्छा माना गया है। प्रदेश ने 1.36 करोड़ व्यक्तियों को बीते सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश में कुल पैदा होने वाले बच्चों में अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का प्रतिशत 98.48 हो चुका है। 9 से 11 महीने के आयु समूह में 93.19 प्रतिशत बच्चों का पूरी तरह टीकाकरण हो चुका है। इसी तरह महिला और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात 950 से बढ़कर अब 956 हो चुका है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मप्र अभी भी औसत दर्जे से नीचे है। इनमें भुखमरी हटाने के उपाय, अच्छी शिक्षा देने की योजनाओं का क्रियान्वयन, महिला पुरुषों में समानता लाने की योजनाएं शामिल हैं।

मप्र खेती किसानी में भी अपना झंडा गाढ़े हुए हैं। तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी मप्र अनाज उत्पादन में अव्वल बना हुआ है। मप्र ने सोयाबीन उत्पान में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मप्र 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मप्र का योगदान 41.92 प्रतिशत है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है। देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 40.01 प्रतिशत है जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है। देश के कुल सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96 प्रतिशत है। पिछले दो सालों में मप्र में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मप्र पिछड़ गया था। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र

छोटे कारीगरों को मिला संबल

मप्र में रोजगार की दिशा में सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। जहां सरकार प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर स्वरोजगार को भी संबल दे रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना छोटे कारीगरों के लिए संबल बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को योजना का शुभारंभ किया था। योजना में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले पारम्परिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी। योजना में 18 प्रकार के परम्परागत व्यवसायों जैसे बढ़ई, नाव-निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल-किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (मूर्तिकार व पत्थर तराशने वाले), पत्थर तोड़ने वाले, मोची (चर्मकार)-जूते बनाने वाले, राज-मिस्त्री, टोकरी-चटाई-झाड़ू निर्माता-कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता (पारम्परिक), नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले कारीगरों को शामिल किया गया है। इच्छुक आवेदकों को योजना में पंजीयन कराने के लिए पीएम विश्वकर्मा पोर्टल भी बनाया गया है।

5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 42.12 प्रतिशत का योगदान था, जबकि मप्र 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। देश के कुल सोया उत्पादन में योगदान 41.50 प्रतिशत था। इसके पहले 2021-22 में भी महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के सोयाबीन उत्पादन में 48.7 प्रतिशत का योगदान था जबकि मप्र 4.61 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। देश के कुल उत्पादन में इसका योगदान 35.78 प्रतिशत था। इसके एक साल पहले 2020-21 में मप्र 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर रहा था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 45.05 0 प्रतिशत का योगदान था। इसी साल महाराष्ट्र 4.6 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर था और राजस्थान तीसरे नंबर पर था। प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 1.7 प्रतिशत बढ़ा और क्षेत्रफल पिछले साल 5975 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 6679 हजार हेक्टेयर हो गया है। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। पिछले साल 2022-23 में सोयाबीन उत्पादन 6332 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 6675 हजार मैट्रिक टन हो गया। पिछले वर्षों में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्रफल में उतार-चढ़ाव होता रहा। सोयाबीन के क्षेत्रफल में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 14.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोयाबीन क्षेत्रफल 2018-19 में 5019 हजार हेक्टेयर था जो 2019-20 में बढ़कर 6194 हजार हेक्टेयर हो गया। इसी दौरान सोयाबीन का उत्पादन 2018-19 में 5809 हजार मिट्रिक टन था जो 2019-20 में कम होकर 3856 हजार मैट्रिक टन हो गया। सोया उत्पादन में 33.62 प्रतिशत की कमी आई।

मप्र सरकार की नीतियों के कारण मप्र पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक मप्र का रुख कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर विकसित होती आधारभूत संरचनाएं, नए गंतव्यों पर लग्जरी टेंट सिटीज व नए होटल्स, लगातार बढ़ती पर्यटन सुविधाएं भी इनबाउंड टूरिज्म बढ़ाने में मदद

करेगी। मप्र में हवाई संपर्क का विस्तार विकास के नए रास्ते खोल रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान बना रहा है। पर्यटक प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, यूनेस्को विश्व धरोहरों के साथ ही हर तरफ फैली हरियाली से खासे प्रभावित हो रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर ये लोग अपनी संस्थाओं के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को मप्र के वैभवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत एव विविध वन्यजीव संपदा से अवगत कराएंगे एवं उन्हें मप्र आने के लिए आमंत्रित करेंगे।

वहीं प्रकृति पर्यटन के क्षेत्र में मप्र को एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। ईको जंगल कैंप कठोतिया को आईसीआरटी इंडिया और सबकॉन्टिनेंट अवार्ड के नेचर पॉजिटिव श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार मप्र ईको पर्यटन विकास बोर्ड दिया गया। यह अवार्ड प्रतिवर्ष आईसीआरटी इंडिया के द्वारा भारत में नेचर एवं रिस्पांसिबल टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दिया जाता है। मप्र ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईको जंगल कैंप कठोतिया में स्थानीय समुदाय के माध्यम से विभिन्न ईको पर्यटन गतिविधियां जैसे कैम्पिंग, पक्षी दर्शन, गांव का भ्रमण, घने वन क्षेत्रों में प्राचीन चट्टानों आश्रयों, झरनों, पवित्र स्थलों तक ट्रेकिंग और साहसिक गतिविधियां जैसे रैपलिंग, नदी पार करना, संरक्षण शिक्षण गतिविधियां और अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित किए जाते हैं। आईसीआरटी इंडिया द्वारा समुदाय आधारित ईको पर्यटन मॉडल को भील जैसे आदिवासी स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षित करने, वन विभाग और वनवासियों के बीच सकारात्मक संबंध बनाने और प्रकृति को संरक्षित करने का एक अत्याधिक अनुकरणीय तरीका माना है। इस पुरस्कार से मप्र ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही समुदाय आधारित ईको पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स एवं मप्र टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से भोपाल में हुए आईएटीओ के 39वें वार्षिक अधिवेशन से प्रदेश में विदेशी व देशी पर्यटकों की संख्या निश्चित ही बढ़ेगी। आयोजन में रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मप्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में योगदान देंगे। आईएटीओ के उपाध्यक्ष रवि गोसाईं का कहना है कि संभाजीनगर (औरंगाबाद) में साल 2023 में हुए अधिवेशन का सीधा फायदा महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के रूप में दिखा है। यहां 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

डिजिटल साक्षरता पर दिया जा रहा जोर

मप्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में डिजिटल लिटरेसी को विकसित करने के उद्देश्य से आईसीटी (इन्फार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) लैब स्थापित की जा रही है। प्रदेश में अब तक 3390 आईसीटी लैब स्थापित की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में स्कूल में कम्प्यूटर लैब स्थापित की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से कम्प्यूटर लैब की स्थापना का कार्य विकेन्द्रीकृत तरीके से जिलों द्वारा किया जा रहा है। आईसीटी लैब की नियमित मॉनीटरिंग एवं मासिक समीक्षा गतिविधियों के लिए विमर्श पोर्टल में एक इंटीग्रेटेड मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। डिटिजल लिटरेसी से संबंधित कौशल आज के तकनीकी युग की आवश्यकता बन चुकी है। जिसमें भविष्य में विद्यार्थियों के लिए अच्छे करियर ऑप्शन हो सकें। इसको ध्यान में रखते हुए आईसीटी लैब के अध्यापन से संबंधित पाठ्यवस्तु का निर्धारण किया गया है। कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आईसीटी से संबंधित विषयवस्तु तैयार की गई है। आईसीटी लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को कम्प्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल साधनों का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी मिल रहा है, जिससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की आईसीटी के प्रति रूचि बढ़ी है।

संवरेगा पुराना वल्लभ भवन

भोपाल के राजधानी बनने के सात साल बाद यानी 1962 में अस्तित्व में आए वल्लभ भवन को अब मॉडर्न लुक मिलेगा। बिल्डिंग के मूल स्वरूप में बदलाव किए बिना यहां विजिटर्स और अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उसी तरह की आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी जैसी वल्लभ भवन की एनेक्सी में हैं। 100 करोड़ रुपए के इस रिनोवेशन प्लान में सिविल वर्क पर 11 करोड़ खर्च होंगे। इंटीरियर के लिए कुल बजट का 27 प्रतिशत यानी 27 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 14 करोड़ रुपए एयर कंडीशनर के लिए खर्च होंगे। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाते रहे पुराने टाइप राइटर, टेलीफोन, कुर्सी, टेबल और पेपर वेट जैसी चीजों का एक संग्रहालय भी बनेगा। वल्लभ भवन की रिनोवेशन की जरूरत तो लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन इस साल 9 मार्च को यहां लगी आग के बाद सरकार का ध्यान इस पर गया। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को वल्लभ भवन के रिनोवेशन का प्लान तैयार करने को कहा गया।

वल्लभ भवन (मंत्रालय) में आगजनी की घटना दोबारा न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर इसको सुरक्षित बनाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 71 करोड़ 35 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसमें कुल राशि का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वर्क पर खर्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वर्क में आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स (एएफसीआई) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और सर्किट ब्रेकर भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं भवन में नए सिरे से सिविल और इंटीरियर वर्क भी किया जाएगा। इसके साथ यहां लिफ्ट बदलने, अलार्म सिस्टम लगाने, सेंट्रल एसी सिस्टम तैयार करने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर हार्वेस्टिंग का काम भी किया जाएगा। पुराने वल्लभ भवन में लगे सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाएगी और कमांड एंड कंट्रोल रूम को अपग्रेड किया जाएगा। जिस फ्लोर पर आगजनी हुई है, उसका नए सिरे से निर्माण होगा। कॉमन एरिया का इंटीरियर भी बदला जाएगा। गौरतलब है कि वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग में आग लगने के बाद से ही उसको संवारने की प्लानिंग होने लगी थी। अब लोक निर्माण विभाग वल्लभ भवन बिल्डिंग के उस हिस्से का रिनोवेशन व उन्नयन कराने जा रही है, जहां आग लगने की घटना में 5वें फ्लोर का आधा से ज्यादा हिस्सा व अन्य फ्लोर का हिस्सा जलकर खाक हो गया था। इसके लिए 71 करोड़ 35 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ भोपाल परिक्षेत्र की सड़कों पर थीन व्हाइट टॉपिंग भी कराने का निर्णय लिया गया है। इस पर करीब 98 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 9 मार्च को वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग के पांचवें फ्लोर पर अचानक आग लगने की घटना हुई थी। इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। एक महीने बाद इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट भी आ गई। जांच में ज्यादा कुछ नहीं निकला, महज शार्ट सर्किट से आग लगने की जांच रिपोर्ट के बाद मामले में लीपापोती कर दी गई। किसी जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, जिसमें उससे सबक लिया जा सके। आग लगने की घटना के बाद से इसके रिनोवेशन का काम चल रहा है। अब तक इसमें करोड़ों रुपए का खर्च किया जा चुका है। काफी कुछ काम हो भी चुका है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की देखरेख में पूरा काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी ने फिर से इसके रिनोवेशन खासकर विद्युतीकरण, फायर फायटिंग कार्य, आंतरिक फिनीशिंग आदि कार्य के लिए टेंडर जारी किया है। कुल 71.35 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसमें और बढ़ोतरी संभावित है। चूंकि पीडब्ल्यूडी ने पहले ही टेंडर में ही लिख दिया है कि टेंडर में कई तरह की शर्तें दी गई है। रिनोवेशन व साज-सज्जा की जिम्मेदारी भोपाल संमाग-दो को दी गई है। टेंडर डालने की समयसीमा 18 अक्टूबर तय की गई है। इस बिल्डिंग में प्रदेश सरकार के 54 में से 19 विभागों के दफ्तर हैं, 1000 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी बैठते हैं। नए भवन में 10 मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, साथ ही मुख्य सचिव के ऑफिस का कुछ हिस्सा होगा। आज यह स्थिति है कि इसमें जगह-जगह सीपेज हो रहा है। सारे वॉशरूम खराब हैं। प्रदेश के प्रशासनिक मुख्यालय में आग बुझाने के लिए केवल फायर एक्सटिंग्युशर लगे हुए हैं। बिल्डिंग के लुक का ध्यान रखे बिना सामने की तरफ से ड्रेनेज पाइप लगा दिए गए हैं। यहां मंत्रियों और अफसरों से मिलने आने वाले विजिटर के बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। वल्लभ भवन के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। अफसरों, कर्मचारियों और विजिटर को आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर है। फायर और बिजली की पूरी व्यवस्था को बदला जा रहा है। बड़ी संख्या में एसी लगेंगे। अफसरों के पास लैपटॉप, कम्प्यूटर और दूसरे उपकरण हैं। इस हिसाब से ही सुविधाएं जुटेंगी। रिनोवेशन के बाद 10 मंत्री यहां बैठ सकेंगे। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय का भी कुछ हिस्सा यहां होगा। 150 सीटर एक मीटिंग हॉल होगा। 50-50 सीटर के चार मीटिंग हॉल होंगे। वीसी हॉल, बैंक, लायब्रेरी, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, झूला घर, कैंटिन, बीएसएनएल ऑफिस और रिकॉर्ड रूम भी यहां होगा।

● **विकास दुबे**

सड़कों पर होगा थीन व्हाइट टॉपिंग

पीडब्ल्यूडी भोपाल संभाग की सड़कों पर थीन व्हाइट टॉपिंग कराने जा रही है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि इससे सड़कें मजबूत होगी, बारिश आदि के दौरान जल्दी खराब भी नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी इस पर 98 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च करेगी। इससे आधा दर्जन सड़कों का काम हो सकेगा। इन सड़कों पर थीन व्हाइट टॉपिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ठेकेदारों को स्पष्ट किया गया है कि इससे संबंधित कार्य वेबसाइट में दिए गए विवरण के अनुसार होंगे। इसमें और भी बढ़ोतरी संभावित है, हालांकि इसकी जानकारी वेबसाइट पर ही दी जाएगी। विभाग का दावा है कि इस तकनीक में करीब 20 साल तक सड़कें खराब नहीं होंगी और सरकार का हर साल के मेंटेनेंस का खर्चा भी बचेगा। इस बार प्रदेश में बारिश की वजह से ज्यादा सड़कें खराब हुई थीं। विभाग भोपाल जैसे ऐसे शहरों को चिह्नित कर रहा है, जहां कि सड़कें पानी की वजह से खराब होती हैं और उसमें गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन, यह सड़कें धंसती नहीं हैं। व्हाइट टॉपिंग का उपयोग ऐसी ही सड़कों पर किया जाना है।

खामियाजा भुगत रहे पेंशनर्स...

मप्र के अफसरों की लापरवाही और छत्तीसगढ़ सरकार की भर्राशाही के कारण मप्र के 5 लाख पेंशनर्स का करोड़ों रुपए की चपत लगी है। जानकारी के अनुसार मप्र सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उधर से जवाब आने में 8 महीने लग गए। इस कारण डीआर न बढ़ने से मप्र पेंशनर्स को 8 महीने तक हर माह 400 से लेकर 4000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है।

जानकारों का कहना है कि मप्र में लगभग 5 लाख पेंशनर्स को आठ महीनों की महंगाई राहत (डीआर) राशि न मिलने के पीछे मप्र के अफसरों की लापरवाही बड़ी वजह है। वित्त विभाग के अफसरों ने मप्र पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-49 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर दी। इसलिए मप्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की सहमति का बहाना बनाकर पहले तो पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत राशि नहीं दी। जब दी भी तो आठ महीने की राशि काटकर दी। हाल ही में पेंशनर संगठन ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखी है कि अधिनियम में यह प्रावधान ही नहीं कि पेंशनरों की डीआर राशि बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ से सहमति ली जाए। इसलिए इस पर स्थिति स्पष्ट की जाए।

प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 46 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है, जबकि पेंशनरों को डीआर राशि का लाभ 1 मार्च 2024 से दिया जा रहा है। इससे उन्हें आठ महीने का नुकसान हो गया। वहीं, केंद्र सरकार के पेंशनर्स की बात करें तो उन्हें 50 फीसदी डीआर राशि मिल रही है। यानी, इस हिसाब से भी मप्र के पेंशनर्स चार फीसदी नुकसान में हैं। पेंशनर्स की डीआर राशि हर छह महीने में बढ़ना चाहिए। यानी, जनवरी और जुलाई में बढ़ाना चाहिए। दो साल में एक ही बार बढ़ी। पिछले साल जनवरी 2023 में चार फीसदी बढ़ाकर 38 से 42 की गई थी। इसके बाद इस साल मार्च 2024 में बढ़ाई। राज्य सरकार 18 साल से यही बताती रही है कि यहां के पेंशनर्स को डीआर राशि देने के लिए मप्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों के बीच सहमति जरूरी है। इसके पीछे मप्र पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-49 का हवाला दिया जाता रहा है। हालांकि इस धारा में पेंशन देनदारियों के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार का भी कहना है कि पेंशन संबंधित मामलों में राज्यों के बीच सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद मप्र सरकार छत्तीसगढ़ की सहमति मिलने के इंतजार में पेंशनरों को समय पर डीआर राशि का भुगतान नहीं करती है। हालिया मामला भी कुछ ऐसा है।

प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2023 से कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स की चार प्रतिशत डीआर राशि बढ़ाने का फैसला किया था। सरकार ने इस तारीख से कर्मचारियों को तो डीए दे दिया, लेकिन पेंशनर्स की डीआर राशि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी। छत्तीसगढ़ ने डीआर राशि 1 जुलाई 2023 के बजाय 1 मार्च 2024 से देने पर सहमति दी। इसे मप्र में लागू भी कर दिया गया। इस तरह पेंशनर्स को आठ महीने का डीआर नहीं मिल पाया है। इसे लेकर पेंशनर्स बार-बार प्रदेश सरकार के सामने मांग रख रहे हैं, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो रहा है। अब एक बार फिर राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से गुहार लगाई है कि गलत परंपरा खत्म करते हुए पेंशनर्स को उनका हक दिया जाए। 18 साल से सहमति लेने के नाम पर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, वो बंद करना चाहिए।

पेंशनरों ने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मांग की है कि महंगाई राहत राशि के भुगतान में राज्यों की परस्पर सहमति की प्रक्रिया को तुरंत समाप्त किया जाए और भविष्य के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए जाएं। जो महंगाई राहत राशि 1 जुलाई 2023 से स्वीकृत है, उसका भुगतान जल्द किया जाए। पेंशनरों का यह भी कहना है कि छठे और सातवें वेतनमान के एरियर की राशि भी अब तक बकाया है, जबकि हाईकोर्ट जबलपुर के आदेशानुसार यह भुगतान छह महीने में किया जाना था। पेंशनरों की मांग है कि सरकार एकमुश्त भुगतान करे। अगर वित्तीय कठिनाई है तो सितंबर में एक किश्त दी जाए और बाकी राशि का भुगतान तीन किश्तों में करें। इसके अलावा पेंशनरों ने राज्य पेंशनर्स कल्याण मंडल के गठन की भी मांग की है ताकि उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण समय पर हो सके।

● **प्रवीण सक्सेना**

नहीं सुलझाया जा रहा पेंच

पेंशनर्स का कहना है कि मप्र और छत्तीसगढ़ में जो पेंच फंसा है उसे सुलझाया नहीं जा रहा है। उनका कहना है कि पुनर्गठित होने वाले दूसरे राज्यों में इस तरह रजामंदी नहीं ली जाती है। मप्र के साथ ही उप्र और बिहार का पुनर्गठन भी वर्ष 2000 में हुआ था। तब उप्र से अलग होकर उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। इन राज्यों में पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए राज्यों में आपसी सहमति भी नहीं ली जाती है। उप्र सरकार ने उत्तराखंड की सहमति के बिना ही 1 जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई राहत राशि देना शुरू कर दिया। वर्ष 2006 में मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंशनरों को महंगाई राहत राशि देने का निर्णय लिया था। हालांकि वित्त विभाग के तत्कालीन सचिव एपी श्रीवास्तव ने 21 सितंबर 2006 को अर्थ शासकीय पत्र जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति आवश्यक बताई। तब से यह परंपरा शुरू हो गई। हालांकि 13 नवंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर धारा-49 की व्याख्या को लेकर स्पष्ट किया था कि महंगाई राहत राशि के भुगतान के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति की आवश्यकता नहीं है। मप्र सरकार इस पत्र को नजरअंदाज कर रही है। इसे लेकर पिछले महीने पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से वित्त विभाग के 2006 के अर्थ शासकीय पत्र को निरस्त करने की मांग की है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय मीडिया प्रभारी भगवतीप्रसाद पंडित का कहना है कि प्रदेश के पेंशनर महंगाई राहत और एरियर की राशि के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। धारा-49 की गलत व्याख्या और वित्त विभाग के त्रुटिपूर्ण निर्णयों के चलते पेंशनरों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है।

सात वेतनमान... पूरी नहीं आस

सरकारी कर्मचारियों के लिए हर वेतन आयोग एक नई उम्मीद लेकर आता है, और इस बार 8वां वेतन आयोग चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। बढ़ती महंगाई और जीवन की लागत के चलते केंद्रीय कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके तहत वेतन में भारी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। दरअसल, सुविधाओं के लिए गठित वेतन आयोगों पर राजकीय कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं। सरकारी सेवकों ने कहा कि 1960 से अभी तक सात कमीशन बनाए गए हैं। उनके द्वारा की गई सभी सिफारिशों को कभी सरकार लागू नहीं कर पाई है। जिससे बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। अभी भी नुकसान झेलने का यह सिलसिला बरकरार है। मप्र की बात करें तो यहां अभी सातवां वेतनमान लागू नहीं हुआ है।

शासकीय कर्मचारियों की शिकायतें अक्सर यह होती हैं कि वेतन बढ़ोतरी उनकी जीवन की जरूरतों के मुताबिक नहीं हो रही है। महंगाई दर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के चलते, वर्तमान वेतन से उनका खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार और वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव की सिफारिश की है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत, वेतन में 15 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।

भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, तब से लेकर अब तक सात आयोग बने और कर्मचारियों के लिए सिफारिशें की गईं। हालांकि, पिछले आयोगों के दौरान कर्मचारियों की कुछ नाराजगी भी रही है। वहीं मप्र में 60 के दशक में सबसे पहले ताराचंद वेतनमान लागू हुआ था। उस समय मप्र के मुख्यमंत्री स्व. कैलाशनाथ काटजू हुआ करते थे। फिर पीसी शेट्टी, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में वेतन आयोग गठित किए गए। कर्मचारियों की मानें तो वेतन आयोगों ने जितनी रिकमंडेशन की हैं, उन सभी को कभी सरकार लागू नहीं कर पाई है। हर आयोग की 30 से लेकर 35 मांगों की अनुशंसाओं पर सरकार ने कभी तीन तो कभी चार मांगों पर ही मंत्री परिषद की बैठक में हरी झंडी दी। समय-समय पर आयोगों की अनुशांसाओं को लेकर बड़े आंदोलन भी किए गए। सरकारों से लंबे दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन वेतन आयोग की मांगों से संदर्भित सिफारिशों पर कभी भी गंभीरता के साथ गौर नहीं किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि शुरूआती दौर से कर्मचारियों को भत्ता और बोनस दिया जाता रहा है। वर्ष 1990 से अनेक भत्ते बंद किए हैं। लगातार मांग करने के बाद भी इन्हें शुरू नहीं किया गया है। त्यौहार भत्ता, अनाज अग्रिम, साइकिल जैसे भत्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दिवाली जैसे त्यौहार पर सरकार बोनस दिया करती थी, वह भी बंद पड़ा है। जिस गृह भाड़ा भत्ते का सरकार भुगतान करती है। वह भी भीषण महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है।

केंद्र में वर्ष 2006 में छठवां वेतनमान लागू हुआ था, जबकि प्रदेश में यह कमीशन 2008 लाया गया। तब कर्मचारी यह डिमांड उठाते रहे कि केंद्रीय तिथि से छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलना चाहिए। दो साल के अंतर की खाई को पाटा जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि यह संभव नहीं हो सका। इसमें वेतन विसंगतियां दूर करने, ग्रेड-पे की त्रुटियां सुधारने, क्रमोन्नति, समयमान का निर्धारित अवधि में लाभ सहित अन्य अनुशंसाएं थीं। वहीं अभी सातवें वेतनमान को लागू करने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी का कहना है कि शुरूआती तारचंद्र से लेकर अभी तक जितने वेतन आयोग गठित किए गए हैं, उनके द्वारा जो सिफारिशें लागू की गईं, उन सभी का लाभ कभी भी कर्मचारियों को नहीं दिया गया। जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश संरक्षक मप्र कर्मचारी कांग्रेस वीरेंद्र खोंगल का कहना है कि वेतन आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों को लाभ देने की कभी भी सरकार की मंशा नहीं रही है। यही वजह है कि समस्याएं बढ़ती गईं और सरकारी सेवक बिना लाभ लिए सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

8वें वेतन आयोग से उम्मीदें

मप्र में भले ही अभी सातवां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, लेकिन अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है, तो कर्मचारियों को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। जानकारी के मुताबिक, यह वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, बेसिक सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि 8वें वेतन आयोग के तहत अन्य भत्तों में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। इसके तहत महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में भी वृद्धि की जा सकती है, जिससे पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक बड़ा मुद्दा है, और अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है, तो इससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बेसिक सैलरी में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे महंगाई के बढ़ते प्रभाव को झेलने में मदद मिलेगी। अब सबकी नजरें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर हैं, जिससे इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के जरिए उनके वेतन में बड़ा सुधार होगा और वे बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले पाएंगे।

किसान सशक्त, निर्यातकों की आय बढ़ेगी

केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। निर्यातकों ने इस फैसले का स्वागत किया। घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता और कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने जुलाई 2023 में निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। जानकारों का कहना है कि गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का भारत का साहसिक निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर है। इस रणनीतिक कदम से निर्यातकों की आय बढ़ेगी। साथ ही किसान भी सशक्त होंगे क्योंकि उन्हें आगामी खरीफ फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। भारत सरकार के इस निर्णय से मप्र के किसान और निर्यातकों के आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय को कृषि निर्यात में सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश और मप्र के चावल उत्पादकों को भरपूर राहत मिलेगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, पारबाइल्ड और ब्राउन चावल पर निर्यात शुल्क को 20 से घटाकर 10 प्रतिशत किया है। गैर बासमती चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटने से मप्र से इस श्रेणी का चावल विदेश जाने का असर यहां के किसानों की आय को बढ़ाएगा। प्रदेश से निर्यात भी बढ़ेगा। मप्र में धान का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। धान उत्पादन क्षेत्रों में जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी शामिल हैं। मंडला और डिंडौरी के जनजातीय क्षेत्रों का सुगंधित चावल और बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त है, जिससे यहां के चावल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोकप्रियता मिली है। प्रदेश से चीन, अमेरिका, यूएई और यूरोप के बाजारों में चावल निर्यात किया जाता है। धान का क्षेत्र बढ़ने के साथ ही चावल उद्योग भी तेजी से बढ़ा है। पिछले वर्षों में 200 से अधिक नई चावल मिलों की स्थापना हुई है। बता दें कि पिछले 10 वर्ष में प्रदेश से 12,706 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात हुआ। वर्ष 2024 में 3,634 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात किया गया है, जो सर्वाधिक रहा है।

भारत ने 2023 में चावल निर्यात पर लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए हैं। बेहतर मानसून के कारण फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकारी गोदामों में भरपूर भंडार है। रोक से पहले भारत की दुनिया के चावल निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी। वह 140 से अधिक देशों को चावल निर्यात करता है। यह कुल 5.54 करोड़ टन में से 2.22 करोड़ टन था। भारत सरकार ने अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरत को पूरा करने और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी। सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया। साथ ही इस पर 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया। इसे निर्यात शुल्क से भी छूट दे दी है। घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई, 2023 से रोक लगा दी गई थी।

भारत का निर्यात दुनिया के अगले चार सबसे बड़े निर्यातकों के संयुक्त निर्यात से भी ज्यादा था। इनमें थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका शमिल हैं। भारत से गैर-बासमती चावल खरीदने वाले मुख्य देशों में बेनिन, बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, जिबूती, गिनी, आइवरी कोस्ट, केन्या और नेपाल शामिल हैं। ईरान, इराक और सऊदी अरब मुख्य रूप से भारत से बासमती चावल खरीदते हैं। 2023 में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत का चावल निर्यात 20 प्रतिशत घटकर 1.78 करोड़ टन रह गया था। 2024 के पहले सात महीनों में भी निर्यात पिछले साल की तुलना में एक-चौथाई कम रहा। भारत के निर्यात कम करने से एशियाई और अफ्रीकी खरीदारों को थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार से चावल खरीदना पड़ रहा था। मांग बढ़ने और सीमित आपूर्ति के कारण इन देशों में निर्यात कीमतें पिछले 15 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बताया कि गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूर्ण रूप से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या नहीं) के लिए निर्यात नीति को प्रतिबंधित से मुक्त में संशोधित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू रहेगा। यह 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के एमईपी (न्यूनतम निर्यात मूल्य) के अधीन है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है कि जब देश में सरकारी गोदामों में चावल का पर्याप्त भंडार है। खुदरा कीमतें भी नियंत्रण में हैं। सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है, जबकि उसना चावल पर शुल्क घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

● **बृजेश साहू**

ब्राउन राइस और धान पर निर्यात शुल्क भी घटाया

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग ने कहा कि उसने ब्राउन राइस और धान पर निर्यात शुल्क भी घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। चावल की इन किस्मों के साथ गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात शुल्क अब तक 20 फीसदी था। अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 27 सितंबर, 2024 से प्रभावी हो गई हैं। इसी महीने सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त कर दिया था। देश ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान 18.9 करोड़ डॉलर मूल्य का गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में यह 85.25 करोड़ डॉलर था। प्रतिबंध के बावजूद सरकार मालदीव, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अफ्रीकी देशों जैसे मित्र देशों को निर्यात की अनुमति दे रही थी। चावल की इस किस्म की भारत में व्यापक खपत है। वैश्विक बाजारों में भी इसकी मांग है। विशेष रूप से उन देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं।

जंगलों पर लगातार बढ़ रहा दबाव

क्या आप जानते हैं कि पिछले तीन दशकों में करीब 42 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि का अन्य उपयोग के लिए डायवर्जन किया गया है। मतलब कि जिन क्षेत्रों पर कभी जंगल मौजूद थे, उनका उपयोग अब कृषि, खनन, शहरीकरण जैसे दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने अपनी नई रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स 2024 में किया है। हालांकि यदि इन तीन दशकों में वन विनाश की दर को देखें तो उसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। गौरतलब है कि जहां 1990 से 2000 के बीच सालाना 1.58 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से जंगलों को काटा जा रहा था, वहीं विनाश की यह दर 2015 से 2020 के बीच घटकर सालाना 1.02 करोड़ हेक्टयर रह गई है।

इस गिरावट के बावजूद अभी भी बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जा रहा है। 2015 से 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो जहां अफ्रीका में सालाना 44.1 लाख हेक्टेयर में फैले जंगलों को साफ किया गया। वहीं दक्षिण अमेरिका में यह आंकड़ा 29.5 लाख जबकि एशिया में यह आंकड़ा 22.4 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष दर्ज किया गया। 2020 में किए रिमोट सेंसिंग सर्वे ने भी पुष्टि की है कि वैश्विक स्तर पर वन विनाश की दर में गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। देखा जाए तो समय के साथ वन क्षेत्र में बदलाव दो मुख्य कारणों से होता है, पहला वनों के किए जा रहे विनाश और दूसरा उन क्षेत्रों में वनों का विस्तार है, जहां पहले वन क्षेत्र की जगह दूसरी गतिविधियां की जाती थी। वैश्विक स्तर पर देखें तो 2010 से 2020 के बीच सालाना वन क्षेत्र में 47 लाख हेक्टेयर की दर से शुद्ध गिरावट आई है। मतलब कि यह जंगल अपने बढ़ने की दर से कहीं ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहे हैं। हालांकि वन क्षेत्र में आती गिरावट की दर पहले जितनी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 1990 से 2000 के बीच वन क्षेत्र को सालाना 78 लाख हेक्टेयर की दर से नुकसान हो रहा था, वो 2000 से 2010 के बीच घटकर 52 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष रह गया। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के करीब 31 फीसदी भूभाग यानी करीब 410 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल मौजूद हैं। पिछले दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं, जिन्होंने वन विनाश को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि इन देशों में भारत भी शामिल है। रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि जहां 2010 से 2020 के बीच चीन के वन क्षेत्र में सालाना 19,37,000 हेक्टेयर की दर से इजाफा हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां इस दौरान वन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4,46,000 हेक्टेयर की दर से बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2,66,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष के साथ भारत तीसरे और 1,49,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष के साथ चिली चौथे स्थान पर है। हैरानी की बात है कि सालाना 1,08,000 हेक्टेयर के शुद्ध इजाफे के साथ अमेरिका इन देशों में सातवें स्थान पर है।

इंडोनेशिया से जुड़े आंकड़ों को देखें तो वहां 2020-2021 की तुलना में 2021-2022 के दौरान वनों के हो रहे विनाश में 8.4 फीसदी की उल्लेखनीय कमी आई है। 1990 में पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय द्वारा इस पर नजर रखे जाने के बाद से यह इंडोनेशिया में दर्ज की गई वन विनाश की सबसे कम दर है। ऐसा ही कुछ ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहां 2022 की तुलना में वन विनाश में 50 फीसदी की गिरावट आई है। बता दें कि अमेजन देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 60 फीसदी हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जंगलों को केवल इंसानों द्वारा काटे जाने का ही खतरा नहीं है। जैसे-जैसे जलवायु में आते बदलाव दुनियाभर में हावी होते जा रहे हैं, उनका प्रभाव जंगलों पर भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। बढ़ते तापमान की वजह से जहां जंगलों में आग लगने का खतरे बढ़ रहा है। साथ ही बदलती जलवायु के साथ जंगल कीटों जैसे तनावों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक जंगल की आग पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और गंभीर रूप लेती जा रही है। साथ ही इस तरह की घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। यहां तक कि उन क्षेत्रों में जहां दावाग्नि का खतरा पहले न के बराबर था, वहां भी यह खतरा अब पैर पसारने लगा है। यदि 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर जंगलों में लगी आग की वजह से 6,687 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ था। उत्तरी वन क्षेत्रों के जंगलों में लगने वाली आग जहां इस उत्सर्जन में 10 फीसदी का योगदान देती थी, वहीं 2021 में यह उत्सर्जन नए स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान देखें तो वैश्विक स्तर पर जंगलों में लगी आग से जितना उत्सर्जन हुआ था, उसमें उत्तर के जंगलों की हिस्सेदारी बढ़कर एक चौथाई पर पहुंच गई। ऐसा मुख्य रूप से लंबे समय तक चले सूखे और आग लगने की गंभीर घटनाओं के कारण हुआ था।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

कमजोर तबके के 70 फीसदी लोग जंगल पर निर्भर

आपको जानकर हैरानी होगी कि कमजोर तबके के करीब 70 फीसदी लोग अपने भोजन, दवा, ऊर्जा और आय के लिए जंगली प्रजातियों पर निर्भर हैं। अनुमान है कि 2020 से 2050 के बीच राउंडवुड की वैश्विक मांग 49 फीसदी तक बढ़ सकती है। यदि भारत से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो लकड़ी को छोड़ पेड़ों से मिलने वाले अन्य उत्पादों पर करीब 27.5 करोड़ लोगों का जीवन निर्भर है। इन उत्पादों से स्थानीय समुदायों और मूल निवासियों को 40 फीसदी तक आय प्राप्त होती है। ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत् विकास की दिशा में प्रगति के लिए वन क्षेत्र में नवाचार आवश्यक है। इनमें उपग्रहों, ड्रोन, रडार और लिडार जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से जंगलों की निगरानी और सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनके विश्लेषण के लिए कृत्रिम बुद्धिमता जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। इसी तरह निर्माण क्षेत्र में लकड़ी की जगह दूसरे बेहतर विकल्पों का उपयोग करना शामिल है। इसी तरह स्थानीय समाधानों और नीतियों के विकास में महिलाओं, युवाओं और स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी तरह नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय परिस्थितियों, दृष्टिकोणों, ज्ञान, आवश्यकताओं और अधिकारों पर विचार करना जरूरी है।

सरकारी भर्तियों में मनमानी का खेल

हाल ही में यूपीएससी में सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री को लेकर जमकर हंगामा हुआ और आखिरकार केंद्र सरकार को पिछले दरवाजे से अधिकारियों की भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। इसमें मामला था- आरक्षण के हिसाब से लेटरल एंट्री न देने का। हालांकि माना यह भी जाता है कि लेटरल एंट्री के जरिये देश के योग्य लोगों को ही चुना जाता है, जिसमें कुछ नहीं देखा जाता, न जात-पात, न धर्म और न अपना-पराया।

सन् 1950 से पिछली केंद्र सरकारों ने भी लेटरल एंट्री के जरिये ऐसी भर्तियां की हैं, जिसके जरिये कई काबिल लोग इस देश को मिले। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिन्हें बाद में राजनीति ने देश के सर्वोच्च पद पर भी बैठाया। इसके अलावा आईजी पटेल, वी. कृष्णमूर्ति, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और आरवी शाही के अलावा कई बड़ी विद्वान हस्तियों को ऐसे ही चुना और सरकार में लाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ऐसे लोगों को ही लेटरल एंट्री के द्वारा केंद्र सरकार अधिकारी बना रही है? या इस पिछले दरवाजे का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपने मतलब के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रही है। क्योंकि अगर हम कुछ पदों पर ध्यान दें, तो देखेंगे कि उन पदों पर बैठे लोग केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद यह बात बुरी लगे, लेकिन यह सच है। क्योंकि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इन सबने जो काम पिछले 10.5 वर्षों में किया है, उसमें केंद्र सरकार की मंशा साफ झलकती है। हालांकि पहले भी सरकार के हिसाब से अधिकारी काम करते थे, लेकिन इस कदर खुलेआम नहीं।

दरअसल, पहले मीडिया का डर सरकारों को रहता था, जो अब खत्म हो चुका है। इसके लिए आज जितनी सरकारें जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा आजकल के पत्रकार और मीडिया हाउस जिम्मेदार हैं, जिन्हें पत्रकारिता अब एक सेवा नहीं, बल्कि पेशा नजर आता है। बहरहाल, केंद्र की मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उस विज्ञापन पर रोक लगा दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लेटरल एंट्री के जरिये यूपीएससी ने 17 अगस्त को मंत्रालयों के लिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां करने के लिए निकाला था। विपक्ष ने हंगामा किया कि इस लेटरल एंट्री में आरक्षण का ख्याल नहीं रखा गया। इस लेटरल एंट्री के खिलाफ देशभर में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों ने प्रदर्शन भी किए। उप्र में दो साल पहले 6,800 शिक्षकों की भर्ती में भी आरक्षण पूरा न देने को लेकर एक विरोध पहले ही खिंचा आ रहा था। लेटरल एंट्री के विज्ञापन ने आरक्षण लेने वाले वर्गों के इस गुस्से में आग में घी का काम किया और 21 अगस्त को सभी ने मिलकर भारत बंद किया। लेकिन इस भारत बंद के दौरान कुछ राज्यों में आगजनी, तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, लेटरल एंट्री के तहत केंद्र सरकार कुछ पदों पर सभी क्षेत्रों से कुछ काबिल लोगों की बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए सीधी भर्ती करती है।

इस भर्ती के तहत किसी क्षेत्र में किसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति को केंद्र सरकार सीधे नियुक्ति पत्र देकर बड़े आधिकारिक पद पर काम करने का सुनहरा मौका देती है, जिससे उस पद पर बैठकर वह व्यक्ति देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि केंद्र की सरकारें अपने मतलब के लोगों की भर्ती लेटरल एंट्री के जरिये करके खुद के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर इसके और हर साल बड़ी संख्या में लेटरल एंट्री के जरिये अपने चहेतों को भर्ती करने के कई आरोप लगे हैं। इसी प्रकार से मोदी सरकार पर अपने चहेते अधिकारियों को प्रमोशन देने, उन्हें खास महकमे देने के साथ-साथ कई-कई बार जबरन एक्सटेंशन देने के भी आरोप लगे हैं। और किसी ने कोई आवाज भी नहीं उठाई। लेकिन इस बार जैसे ही लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी हुआ, विपक्ष के नेताओं ने इसे आरक्षण का मुद्दा बनाते हुए प्रतिबंधित करने की मांग कर दी। इस डायरेक्ट भर्ती को लेकर विपक्षी नेताओं ने खुलकर विरोध किया। दरअसल, यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है, जो तीन मुश्किल चरणों के जरिये ऐसे युवाओं का चुनाव करती है, जिनमें देश को विकास की राह पर चलाने और देश-विदेश नीति को समझने की क्षमता होती है।

● **कुमार राजेंद्र**

बेरोजगारी दर काफी नीचे

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक, देश में साल 2020 में बेरोजगारी दर 7.11 फीसदी और साल 2021 में 7.9 फीसदी थी। लेकिन सरकार खुद कह रही है कि वह 100 में सिर्फ 40 लोगों को ही नौकरी दे पा रही है। इस प्रकार तो बेरोजगारी दर 60 फीसदी हुई। फिर बेरोजगारी के आंकड़े 7-8 फीसदी के बीच में क्यों अटके हुए हैं? इसमें तो गड़बड़ी साफ दिख रही है। लेकिन लेटरल एंट्री में कोई कमी नहीं आई। प्राइवेट नौकरियां भी घट रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि महज एक साल में टाइटन और रिलायंस समेत पांच बड़ी कंपनियों ने अपने 52,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अगर मीडिया क्षेत्र की बात करें, तो हर मीडिया हाउस इन दिनों 10-10 कर्मचारियों का काम एक या दो कर्मचारी से ले रहा है और तनख्वाह की बात की जाए, तो वो कई मीडिया हाउस में तो चपरासी से लेकर शुरुआती पद के लेवल की भी नहीं है। कोरोना की पहली लहर में साल 2020 में करीब 1.45 करोड़ लोगों को कंपनियों ने नौकरी से हटा दिया था। इसी प्रकार से कोरोना की दूसरी में करीब 52,00,000 लोगों की और कोरोना की तीसरी लहर में करीब 18,00,000 लोगों की नौकरी छिन गई। और ये केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं। लेकिन नौकरियां मिलीं कितनी? यह इस बात से जाहिर होता है कि आज जब कहीं किसी एक पद पर भर्ती निकलती है, तो लाखों बेरोजगार उसके लिए अप्लाई करते हैं। सरकार अगर सरकारी पद बढ़ाने में असमर्थ है, तो कम-से-कम उन पदों को जरूर भरे, जो खाली पड़े हैं। और सिर्फ लेटरल एंट्री, रिश्वत और सोर्स के जरिये सरकारी पदों पर भर्तियों का खेल भी रोके, जिससे किसी भी वर्ग या जाति के युवा को ईमानदारी से उसका हक मिल सके और बार-बार आरक्षण का मसला ही न उठे।

हरियाणा, जम्मू-कश्मीर का जनादेश

अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जनता

लोकसभा चुनाव के ठीक चार महीने बाद हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि वादों और लोकलुभावन घोषणाओं पर निर्भर रहना पार्टियों को भारी पड़ेगा। क्योंकि अब जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता भावनाओं में बहने वाली नहीं है। समय रहते जो पार्टी जनता के मनोभाव को समझते हुए मैदानी रणनीति पर काम करेगी, वही सिंहासन पर बैठ पाएगी। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर का जनादेश जल्द होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली चुनाव के लिए भी आईने का काम करेगा।

● राजेंद्र आगाल

लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से मिली कड़ी चुनौती के बाद भाजपा ने जिस तरह हरियाणा में हैट्रिक लगाई है और जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन किया है, उससे 4 महीने में 3 राज्यों महाराष्ट्र-झारखंड, दिल्ली में विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों की 28 सीटें पर उपचुनाव में उसको बल मिलेगा। अगर हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणामों का आंकलन किया जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि मतदाता राजनीतिक पार्टियों के वादों और लोकलुभावन घोषणाओं में फंसने वाला नहीं है। जनता अब अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। इसलिए पार्टियों के सामने जनता के मूड को भांपने और उसके अनुसार रणनीति बनाकर काम करने की चुनौती है। आगामी समय में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां जो पार्टी इस पर फोकस करके रणनीति बनाएगी और उसे अमलीजामा पहनाएगी, उसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए भाजपा ने अभी से आगामी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने तथा जाति जनगणना का जो नरेटिव कुछ राज्यों में जबर्दस्त ढंग से काम कर गया था, वो इन विधानसभा चुनाव में फेल रहा। इन नतीजों का कांग्रेस के लिए सबक यह है कि अगर राज्यों में किसी एक नेता पर आंख मूंद कर भरोसा कर कमान उसके हाथ में देने और बाकी की उपेक्षा की जाए तो खेल बिगड़ जाता है। नतीजों ने यह भी साबित किया कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने किसान, जवान और पहलवान का जो नरेटिव सेट किया था, वह सतही था। राज्य में ओबीसी जातियों का यह डर भाजपा के पक्ष में काम कर गया कि यदि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो जाटों की दबंगई फिर शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो दलित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ बड़े पैमाने पर चले गए थे, वो इस बार बंट गए और फायदा भाजपा को मिला। यही स्थिति जाट वोटों की भी रही। इसके विपरीत कांग्रेस की कोई सुस्पष्ट रणनीति नहीं दिखी, सिवाय इस भरोसे के कि जनता इस बार उसे जिताने के लिए तैयार बैठी है। दूसरे राज्य के प्रभावशाली और मुखर जाट समुदाय की नाराजी को जनता की नाराजी मान लेना भी गलती थी। यह हम इसके पहले मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं, जहां पार्टी ने क्रमशः कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर असंदिग्ध भरोसा किया और हाथ आती सत्ता फिसल गई। इन परिणामों का कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के लिए बड़ा सबक यह है कि जब तक वो संगठन को ऊपर से नीचे तक नहीं कसेंगे, उसमें लडाकू तेवर पैदा नहीं करेंगे, तब तक छुटपुट सफलताओं से ज्यादा हासिल कुछ नहीं होगा। मोदी और भाजपा को हिलाना इतना आसान नहीं है। लोकसभा में भाजपा द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाला दांव विधानसभा चुनावों में इसलिए नहीं चल पाया, क्योंकि वो नरेटिव एक आशंका पर ज्यादा आधारित था। हकीकत में वैसा कुछ हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भविष्यवाणी को भी हकीकत में बदल दिया कि हरियाणा में कांग्रेस का हश्र मप्र जैसा ही होगा, वैसा हुआ भी। दूसरा, लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति में कई बदलाव किए, जिसमें टिकटों के बंटवारे से लेकर बाहरी नेताओं का समावेश और वोटों के प्रति जाट ध्रुवीकरण शामिल है।

मतदाता को समझना टेढ़ी खीर

हरियाणा, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखकर निदा फाजली का यह शेर बड़ा मौजूं सा लगता है कि हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी, जिस को भी देखना हो कई बार देखना। यानि जनता के दिल में क्या है? यह जानना-समझना टेढ़ी खीर है। जनता के किसी फैसले के पीछे क्या वजह होती हैं? यह जानना भी आसान नहीं है। नतीजे कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। आतंक और डर के आगे जम्मू-कश्मीर में लोगों ने बढ़-चढ़कर वोटिंग की। जबरदस्त मतदान ने साबित किया कि जम्हूरियत पर जनता का कितना भरोसा है। वहीं, हरियाणा में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए एकतरफा जीत हासिल करेगी। सभी एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे थे। लेकिन जनता ने यहां भाजपा की हैट्रिक बनवा दी। हरियाणा के नतीजों ने चौंकाया, वहीं जम्मू-कश्मीर के परिणाम लगभग अनुमान के मुताबिक ही रहे। हरियाणा चुनाव 5 मुद्दों के इर्द-गिर्द घूम रहा था, पहला भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी, दूसरा- किसानों का गुस्सा, केंद्र सरकार की उपेक्षा, तीसरा- पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अलोकप्रियता, चौथा- खिलाड़ियों के खिलाफ अन्याय पर रोष और पांचवा अग्निवीर योजना पर आक्रोश। अब जो परिणाम आया है उससे साफ है कि भले ही प्रचार में ये मुद्दे हावी रहे हों लेकिन परिणाम की वजह कोई दूसरे ही फैक्टर बन गए।

एक-एक पग बढ़ाकर आगे बढ़ी भाजपा

हरियाणा में भाजपा के लिए गुडलक सफर 2014 में ही शुरू हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी और शानदार स्ट्राइक लगाते हुए 7 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा की सुनामी देखी गई और पार्टी ने 47 सीटें जीतीं। 2009 के मुकाबले भाजपा की सीटें 43 बढ़ गई और आंकड़ा 4 से बढ़कर 47 पर पहुंच गया। पार्टी का वोट शेयर 33.2 हो गया। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का स्ट्राइक रेट 100 प्रतिशत रहा। भाजपा ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी को 58.02 फीसदी वोट हासिल हुए। लेकिन 2009 विधानसभा चुनाव में पार्टी को एंटी इनकंबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ा। भाजपा इस चुनाव में 40 सीटें जीत पाईं। हालांकि मतों का प्रतिशत बढ़कर 36.49 प्रतिशत हो गया। मनोहरलाल खट्टर ने एक बार फिर से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला का साथ लेकर सरकार बनाई। इस चुनाव में चौटाला ने 10 सीटें जीतीं थीं। यहां यह भी बताना जरूरी है जो भाजपा देवीलाल की पार्टी के साथ कभी जूनियर सहयोगी रहा करती थी अब वो सीनियर की भूमिका में आ गई थी। और देवीलाल के खानदान से जुड़े दुष्यंत चौटाला भाजपा के सहयोगी बनकर सरकार में शामिल हो गए। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव इतिहास रचने वाला साबित हुआ। भाजपा ने इस चुनाव में अपना बेस्टएवर परफॉर्मेंस दिया और 48 सीटें जीतीं। इस चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 39.94 प्रतिशत रहा। ये स्थिति तब रही जब मात्र 3 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां जोरदार झटका लगा था और पार्टी 10 में से 5 सीटें ही जीत सकी थी। साथ ही वोट प्रतिशत भी 2019 के 58.02 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 47.61 प्रतिशत हो गया था।

कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस भारी

ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस को जिस तरह से भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का फीडबैक मिला उसे लेकर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं पार्टी पर भारी पड़ गया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जाट भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर उन्हें वोट करेंगे। जाटों की राज्य में आबादी लगभग 25 प्रतिशत है। लगभग 40 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ हुए

धारा-370 हटाने का दांव भी फेल

धारा-370 हटाने की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जरूर है, लेकिन उसे भी पता है कि यह अब व्यावहारिक नहीं है। लिहाजा उसका जोर पूर्ण राज्य के दर्जे पर ही ज्यादा रहेगा। वैसे भी केंद्र की मदद के बगैर जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाना नामुमकिन है। हालांकि वहां भाजपा के सरकार न बना पाने से यह संदेश दुनिया में जरूर गया है कि राज्य के लोग अभी भी धारा-370 हटाने से खुश नहीं हैं और इसके अलग-अलग कारण हैं। अलबत्ता सकारात्मक संदेश यह है कि आंतकवाद से प्रभावित इस राज्य में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अहम बात यह है कि जो तत्व कभी भारतीय संविधान और चुनावों को ही नकारते थे, वो मजबूरी में ही सही पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लौट रहे हैं। एक बात साफ है कि राज्य में जो संवैधानिक बदलाव किए गए हैं, उसका राजनीतिक और सामाजिक असर भी हमें जल्द दिखाई देगा। इस बात की संभावना कम है कि जम्मू-कश्मीर की अवाम आए दिन आंतकी हमलों, पत्थरबाजी और बंद के दौर में लौटना चाहेगी।

अन्याय पर रोष, पिछली दो सरकारों में जाटों की उपेक्षा का दंश... जैसी वजहों से जाट भाजपा के खिलाफ थे। उनके इस गुस्से को कांग्रेस अपने पक्ष में मानकर चल रही थी। इन सभी बातों से कांग्रेस को लगा कि जाटों का एकमुश्त वोट उन्हें ही जाने वाला है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि भाजपा ने पिछली दो सरकारें इन्हीं जाटों के खिलाफ गैर जाट जातियों को एकजुट करके बनाई थीं। इस बार भी यही हुआ। जैसे ही जाटों की एकजुटता के बारे में गैर जाट जातियों को अहसास हुआ वे काउंटर पोलराइज हो गईं। जबकि इस बार भी जाट वोट बांटने के लिए जेजेपी, इनेलो जैसी पार्टियां भी मैदान में थीं। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की अलोकप्रियता को भी भाजपा ने भांप लिया था। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की गई। गुजरात में यह प्रयोग भाजपा कर चुकी थी। जब पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रुपाणी के खिलाफ चल रहा लोगों का गुस्सा खत्म करने की कोशिश हुई थी। परिणाम बताते हैं यह दांव भी भाजपा के पक्ष में काम कर गया। सैनी ने ना सिर्फ खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी फैक्टर को कम किया बल्कि वे पिछड़ी जाति के वोट को भाजपा के पक्ष में लाने में सफल रहे।

भाजपा ने यह भी सावधानी रखी कि पूरे इलेक्शन में कहीं भी खट्टर दिखाई न दें। उन्हें पूरे कैंपेन से दूर रखा गया। सैनी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू कीं जिन्हें केंद्र सरकार की गरीब कल्याण और किसानों को फायदा पहुंचाने की योजनाओं की बहुत मदद मिली। ऐसा मानने में भी कोई गुरेज नहीं है कि डायरेक्ट बेनेफिट वाली इन योजनाओं ने हरियाणा की भाजपा सरकार की बहुत मदद की। चुनाव के बाद से लगातार भाजपा सैलजा के बहाने दलित उपेक्षा की बात कर रही थी। सैलजा की दलित आत्मसम्मान का मुद्दा बना रही थी। सैलजा भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर भाजपा के कैंपेन को अघोषित तौर पर मदद ही कर रही थीं। हालांकि वोटिंग के पहले जरूर उन्होंने कुछ बयान पार्टी के फेवर में दिए। लेकिन कांग्रेस वक्त पर सैलजा को साधने में कामयाब नहीं हो पाई। इसी तरह ऐसा माना जा सकता है कि इनेलो, जेजेपी और बसपा, आजाद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के गठबंधन ने भी दलितों के वोट काटे।

वोटों का बंटवारा

खास बात यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने ऐसी कोई बड़ी रेवड़ी भी नहीं बांटी, जैसे कि मप्र में बांटी थी। भाजपा की रणनीति साफ थी कि प्रभावशाली जाट वोटों का बंटवारा करो और एंटी जाट वोटों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करो। वही होता दिख भी रहा है। पार्टी ने न केवल अपना वोट बैंक बचाया बल्कि उस जाट लैंड में भी सेंध लगा दी, जहां से कांग्रेस बंपर समर्थन की उम्मीद लगाए हुए थी। हरियाणा के यादव बहुल अहीरवाल अंचल में भाजपा की भारी जीत के पीछे भाजपा द्वारा मप्र में एक यादव डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन, अग्निवीर जैसे मुद्दे जोर-शोर से उठाए, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वोटर इन मुद्दों पर अपनी राय लोकसभा चुनाव में पहले ही व्यक्त कर चुका था। अति आत्मविश्वास भी कांग्रेस को ले डूबा। हालांकि यह कहना कठिन है कि अगर वो दूसरी जाट पार्टियों और आप के साथ गठबंधन करती तो नतीजे बदल सकते थे। लेकिन चुनाव के दौरान दलित नेता कुमारी सैलजा की नाराजी कांग्रेस को डुबो गई। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सैलजा को मनाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सत्ता पाने से ही मुख्यमंत्री पद की लड़ाई का जनता में गलत संदेश गया। वैसे यह लड़ाई भाजपा में भी दिखी। वहां अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी थी, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यह तय है कि मुख्यमंत्री का ताज नायब सिंह सैनी को मिलेगा। यानी मप्र की तर्ज पर भाजपा हरियाणा में फिर ओबीसी कार्ड ही खेलेगी।

उधर जम्मू-कश्मीर में भाजपा का सरकार बनाने का सपना दूर की कौड़ी ही था। वहां चुनाव जीतते ही सत्ता में आ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के नेता फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि यह जनादेश राज्य से धारा-370 व 35ए हटाने और भाजपा के खिलाफ है। इससे स्पष्ट हो गया कि जम्मू-कश्मीर में आगे भी टकराव की राजनीति होने वाली है। इस मामले में कांग्रेस दुविधा में रहेगी, क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने के मुद्दे पर चुप है, लेकिन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की हामी है। दरअसल भाजपा प्रदेश में शांति, अमन, पर्यटन को बढ़ावा जैसे मुद्दों पर घाटी में भी समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मुसलमानों में भाजपा के प्रति जो नाराजी है, वह खत्म नहीं हुई है। अलबत्ता 2014 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में भाजपा की सीटें और वोट दोनों बढ़े हैं। लेकिन भाजपा के साथ कभी सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का सफाया और भाजपा ने घाटी में निर्दलियों के समर्थन से सरकार बना सकने की संभावना पर नतीजों ने पानी फेर दिया है। अच्छी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं ने अलगाववादी निर्दलीयों और अन्य पार्टियों को चुनने की जगह नेकां-

कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दिया। जिससे सरकार के पांच साल तक चलने की उम्मीद ज्यादा है। इन नतीजों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर फिर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। जम्मू-कश्मीर में तो नतीजे सर्वे के हिसाब से आए हैं, लेकिन हरियाणा में तमाम सर्वे फेल हुए हैं। राजनेताओं को भी समझ आ गया है कि सर्वे के आधार पर मन में लड्डू भले फूट रहे हों, लेकिन हकीकत में पूरे नतीजे आने के बाद ही लड्डू खाना और बांटना चाहिए।

अब आगे की तैयारी

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों की अगली चुनौती महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो उप्र में 10, राजस्थान में 6, पंजाब में 5, बिहार में 4, मप्र में 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें से पंजाब छोड़कर सभी जगह भाजपा सत्ता में है। लिहाजा एंटी इनकंबेंसी फैक्टर से लड़ने के साथ कैंडिडेट का लोकल कनेक्ट ही चुनाव नतीजे तय करेगा। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकंबेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिलीं। इनमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थीं। 2014 में यह आंकड़ा 42 था। यानी आधे से भी कम। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपथी है।

झारखंड का रण

झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ तीन सीटें अभी भाजपा के पास हैं। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवरदास को भी हार का सामना करना पड़ा। जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि, जमानत मिलने के बाद वे बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में मुख्यमंत्री का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपई भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथी रहे चंपई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। वहीं इन नतीजों ने झारखंड में भाजपा को आत्मविश्वास दिया है। झारखंड में वापसी की राह देख रही भाजपा को एजेएसयू के साथ सीटों का बंटवारा करना है। ऐसे में इन नतीजों के बाद भाजपा ज्यादा से ज्यादा तोल-मोल करने की स्थिति में होगी। हरियाणा की जीत से गदगद प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया झारखंड में भी भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

दिल्ली दूर नहीं

चुनाव लिस्ट में अगला नाम दिल्ली का है, जहां विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। शराब नीति घोटाले में 13 सितंबर को जमानत के बाद उन्होंने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। यहां आप के मजबूत किले को भेदना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि पिछले दो चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से आप और भाजपा के बीच एलजी के जरिए तकरार होती रहती है। भाजपा आप पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हावी है। शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत कई नेता जेल में रहे। भाजपा इसी मुद्दे को भुनाना चाहती है। साथ ही एंटी इनकंबेंसी भी

स्थापना के साथ ही हरियाणा में कामयाबी का स्वाद

1982 में भाजपा की स्थापना के बाद ही 1987 में भाजपा ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को अच्छी कामयाबी मिली थी। पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसके 16 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये भाजपा का तगड़ा शो था। लोकदल और कांग्रेस के प्रभाव के बावजूद भाजपा का 16 सीटें जीतना बड़ी बात थी। पार्टी का वोट प्रतिशत 10.08 प्रतिशत था। इसी चुनाव में भाजपा की दिग्गज नेत्री रहीं सुषमा स्वराज अंबाला कैंट से विधायक चुनी गई थीं। सुषमा हरियाणा कैंट से भाजपा की शुरुआती विधायकों में रही हैं। लेकिन 1991 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद हताशाजनक रहा। भाजपा 89 सीटों पर लड़ी लेकिन मात्र 2 सीटें ही जीत पाई। ये मंडल-कमंडल और गठबंधन सरकारों का दौर था। 1996 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फोकस्ड एप्रोच अपनाया और उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ी जहां पार्टी मजबूत थी। पार्टी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से 11 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। भाजपा का वोट शेयर 8.9 प्रतिशत रहा। हरियाणा में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए एकतरफा जीत हासिल करेगी। सभी एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे थे। लेकिन जनता यहां भाजपा की हैट्रिक बनवाते हुए नजर आ रही है। 2014 से पहले हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय और इंडियन नेशनल लोकदल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन भ्रष्टाचार, किसान असंतोष और कुशासन जैसे मुद्दों के कारण मतदाताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था। आईएनएलडी के अलावा बंसीलाल की अगुवाई में हरियाणा विकास पार्टी का भी यहां बोलबाला रहा।

एक फैक्टर रहेगा। दिल्ली में भी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने को हैं। गौरतलब है कि यहां लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी थी। लेकिन यहां के चुनाव में इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद ये गठबंधन टूट सा गया था। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार आम आदमी पार्टी के फिसड्डी प्रदर्शन के बाद दिल्ली में गठबंधन की आस भी शून्य हो गई। हरियाणा नतीजों के बाद आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने साफ कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रियंका कक्कर ने कहा कि कांग्रेस के हार की वजह अति आत्मविश्वास है। इन्होंने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। जबकि इन्हीं दलों ने उप्र और दिल्ली में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दी थी।

चुनाव परिणामों का असर

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर का न सिर्फ स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स पर हुआ है। बल्कि इससे कांग्रेस-भाजपा की गठबंधन करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद अनिच्छा से ही सही इंडिया ब्लॉक के घटक दलों को कांग्रेस के प्रति सम्मान दिखाना पड़ा था। राहुल गांधी की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों में ही वृद्धि हुई थी। लेकिन इन नतीजों ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोगियों को राहुल से सवाल पूछने का मौका दे दिया है। वहीं इन नतीजों ने सहयोगियों के साथ भाजपा की तोल-मोल की शक्ति बढ़ा दी है। अब इसे आने वाले चुनावी राज्यों के संदर्भ में समझते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। चुनाव नतीजे आते ही भाजपा के कट्टर आलोचक रहे संजय राउत की प्रतिक्रिया गौर करने लायक रही। संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। भाजपा ने बेहतरीन चुनाव लड़ा।

भाजपा ने हारी हुई बाजी जीत ली। कांग्रेस की ओर साफ इशारा करते हुए संजय राउत ने कहा कि हम कश्मीर इसलिए जीते क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने मिलकर चुनाव लड़ा। हरियाणा हारे क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो खुद ही ताकतवर हैं और जीत जाएंगे। संजय राउत की बातों का मतलब साफ है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने लिए अधिक से अधिक सीटें मांगेंगी और कांग्रेस को उनसे जबरदस्त मोलभाव करना पड़ेगा। शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो इस ओर इशारा भी कर दिया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे। आने वाले राज्यों के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़े। प्रियंका ने मांग की कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा चुनाव से पहले होनी चाहिए। संजय राउत की बात को दोहराते हुए प्रियंका ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने ही ये लड़ाई लड़ी थी, वहां पर गठबंधन बन नहीं पाया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनौती और दांव दोनों ही अधिक है। यहां पर पार्टी को एनसीपी के साथ भी सीटें शेयर करनी है। शरद पवार की एनसीपी भी राज्य में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है।

इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों को याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही नंबर वन पार्टी थी और ये बात सहयोगियों को याद रखनी चाहिए। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, महाराष्ट्र में, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले स्थान पर थी और गठबंधन धर्म यह है कि हम मुद्दों पर आपस में चर्चा करें, मीडिया के माध्यम से नहीं। आगे उन्होंने कहा, हम महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, गठबंधन को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने सहयोगियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस यहां सहयोगियों के सामने तीन महीने पहले का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है लेकिन उसकी सहयोगी पार्टियां ताजा-ताजा रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस को दिखा रही हैं। जहां उसका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा है जैसी की अपेक्षा उससे की जा रही थी। लिहाजा कुछ ही दिन बाद जब कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बैठेगी तो जबरदस्त रस्साकशी तय है।

उमर अब्दुल्ला को मिला कांटों भरा ताज

उमर अब्दुल्ला पहले भी जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब और अब की परिस्थितियों में जमीन-आसमान का फर्क है। पहले जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लद्दाख वाला हिस्सा भी अब उससे अलग हो चुका है। बदले हालात में उमर अब्दुल्ला के सामने नई तरह की चुनौतियां पेश आएंगी, और उनसे राजनीतिक तरीके से ही डील करना होगा, लेकिन हर हाल में जम्मू-कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं का पूरा ख्याल रखना होगा। हर हाल में जम्मू-कश्मीर के लोगों के मन में निराशा का भाव आने से बचाना होगा, और किसी भी सूरत में लोगों को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि चुनाव से पहले और बाद की परिस्थितियों में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वरना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार का हाल भी पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती जैसा होते देर नहीं लगेगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि लोगों का जो गुस्सा पीडीपी के प्रति देखा जा रहा है, भाजपा के प्रति वैसा बिलकुल नहीं है। भाजपा भले ही बहुमत और सत्ता से दूर रह गई हो, लेकिन 2014 के मुकाबले सीटों के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उमर अब्दुल्ला की राजनीति ने धारा-370 हटाए जाने के बाद चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से लेकर दो-दो सीटों से चुनाव जीतने तक, एक लंबा सफर तय किया है। ऐसे में, ये तो है कि लोगों ने अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा जताया, और पीडीपी को नकार दिया है। पीडीपी को भाजपा के साथ सरकार बनाने की कीमत चुकानी पड़ी है। अच्छी बात ये है कि अब्दुल्ला परिवार ने जनभावनाओं को समझा, और वक्त की जरूरत के हिसाब से रणनीति भी बदली। इंजीनियर राशिद से हार जाने के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, उसी के तहत आने वाली विधानसभा से फिर से मैदान में उतरे, और जीते भी। शायद यही वजह है कि जनता ने पूरे मैंडेट के साथ सत्ता सौंप दी है।

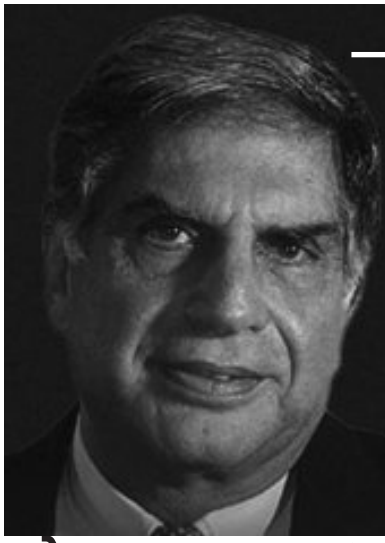

देश के रतन ने दुनिया को कहा... टाटा

रतन टाटा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन रतन टाटा ने औद्योगिक जगत के साथ ही भारतीयों को जो संस्कार दिया है, वह अजर-अमर रहेगा। रतन टाटा भले ही ख़ास व्यक्ति थे, लेकिन आम जनता से उनका लगाव था।

लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन्हें उठाएं और उनसे स्मारक बनाएं... रतन टाटा ने यह बात कही भी और इसे जिया भी। बचपन में माता-पिता का तलाक हुआ। दादी के हाथों परवरिश हुई। प्यार तो हुआ पर वो परवान न चढ़ा। त्याग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन जो कहा उसे करके दिखाया। विरोधियों को जवाब दिया और देश के दिग्गज कारोबारी बनकर इतिहास में अमर हो गए।

86 वर्ष के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जैसे ही अंतिम सांस ली, पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी चौंकाती है। सबक देती है। और विरोधियों को जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे (मुंबई) में नवल और सूनू टाटा के घर उनका जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में माता-पिता अलग हो गए। तलाक के बाद पिता ने स्विस महिला सिमोन दुनोयर से शादी की और मां ने सर जमसेतजी जीजीभॉय के साथ घर बसा लिया, लेकिन रतन की परवरिश की उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से हुई। कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल पहुंचे। हायर स्टडी के लिए अमेरिका पहुंचे और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 7 साल अमेरिका में रहे। पढ़ाई के बाद लॉस एंजिलिस में नौकरी की। यहीं प्यार भी हुआ। इसका किस्सा खुद उन्होंने साझा किया था। रतन टाटा का कहना था कि जब वो अमेरिका में थे उनकी शादी हो ही गई होती लेकिन दादी ने उन्हें फोन करके बुलाया और उसी दौर में भारत-चीन की 1962 जंग शुरू हुई। मैं भारत में रह गया और उसकी वहां शादी हो गई।

भारत लौटने के बाद 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। अप्रेंटिस के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीके से वो बुलंदियां छूने लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर एसके नानावटी के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका नाम बंबई तक पहुंचा दिया और जेआरडी टाटा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। उनका कहना था, एक ही चीज दुनिया में इंसान को नाकाम बना सकती है, वो है जोखिम न उठाने की आदत। रतन टाटा का कहना था, सबसे बड़ा जोखिम, जोखिम को न उठाना है। जेआरडी टाटा ने उन्हें कमजोर कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसी उम्मीद थी वो कर दिखाया। तीन साल के अंदर वो कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगीं। साल 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बनाया गया। जेआरडी जब 75 साल के हुए चर्चा शुरू हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लिस्ट में कई नाम थे। खुद रतन टाटा को भी लगता था कि उत्तराधिकारी की कुर्सी के दो ही दावेदार हैं- पालखीवाला और रूसी मोदी। लेकिन जेआरडी टाटा की नजर रतन पर थी। 86 साल की उम्र में जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 1991 में रतन को उत्तराधिकारी बनाया।

रतन टाटा का कहना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं... उन्होंने ऐसा ही किया। एक ऐसा वक्त भी था जब कारोबार जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। साल 2000 में उन्होंने अपने से दोगुने बड़े ब्रिटिश ग्रुप टेटली का अधिग्रहण किया। तब उनके फैसले पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। दूसरी बार सवाल तब उठे जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा, लेकिन इस बार भी रतन टाटा ने सबको प्रभावित किया।

सफलता की राह में रतन टाटा का सामना विवादों से भी हुआ। साल 2010 में विवाद तब पैदा हुआ जब लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी टेलिफोनिक बातचीत लीक हुई। उस टेप में नीरा की नेताओं, टॉप बिजनेसमैन और पत्रकारों से बातचीत शामिल थी। साल 2020 में टाटा समूह के ज्वैलरी ब्रांड तनिष्क का एक विज्ञापन जारी हुआ जिसको लेकर दक्षिणपंथियों ने सवाल उठाए और ट्रोल किया गया। इसके बाद विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। 2016 में एक और विवाद उठा जब रतन टाटा ने 24 अक्टूबर, 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को एक घंटे से भी कम समय के नोटिस पीरियड पर बर्खास्त कर दिया।

● **विपिन कंधारी**

धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना

रतन टाटा का मानना था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए क्योंकि ये सफलता की आधारशिला हैं। उन्होंने इसका उदाहरण भी पेश किया। नैनो से पहले उन्होंने 1998 में टाटा मोटर्स की इंडिका को भारतीय बाजार में उतारा। यह भारत में डिजाइन हुई पहली कार थी। इसे सफलता नहीं मिली तो फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया। बातचीत के दौरान फोर्ड ने रतन टाटा पर ताना मारा कि अगर वो उनकी इंडिका खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा अहसान करेगी। इस बात से रतन टाटा और पूरी टीम नाराज हुई। डील कैंसिल कर दी गई। 10 साल बाद हालात बदले। फोर्ड अपने बुरे दौर में पहुंची। उन्होंने जगुआर और लैंडरोवर बेचने का फैसला लिया। रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों ब्रांड का अधिग्रहण किया। हालांकि, इस अधिग्रहण पर कारोबार क्षेत्र के विश्लेषकों ने सवाल उठाए और कहा, यह डील टाटा ग्रुप के लिए बोझ साबित होगी। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का इस समूह की तरक्की में विशेष योगदान रहा, इसने कंपनी को पिछड़ने नहीं दिया। तमाम चुनौतियों, विवाद और उपलब्धियों के बीच टाटा समूह उन कारोबारी ग्रुप में शामिल रहा जिन पर भारतीयों का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। फिर चाहें कोविड के दौर में 1500 करोड़ रुपए की राशि से की गई मदद हो या फिर मरीजों के लिए अपने लग्जरी होटल का इस्तेमाल करने देना।

असंतोष बढ़ने के साथ ही अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं? वे एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए उनके पास दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या है।

मोदी के मन में क्या?

पिछले कुछ हफ्तों में मोदी सरकार को प्रेस द्वारा मिली खराब कवरेज के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम आंकना हमेशा एक गलती है। वे अभी भी भारत में सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं और सबसे चतुर लोगों में से एक हैं। वे आमतौर पर अपने विरोधियों से कम से कम तीन कदम आगे रहते हैं (ठीक है, शायद पिछले कुछ महीनों में नहीं) और उनके हर फैसले से राजनेता और टिप्पणीकार हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उनका अगला कदम क्या होगा। एक बात पर गौर करना थोड़ा आसान है, खासकर पिछले आम चुनाव के बाद, वो यह कि प्रधानमंत्री के समर्थक उनके प्रदर्शन पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार की अन्य शाखाओं- उदाहरण के लिए न्यायपालिका के साथ उनके रिश्ते हम सभी के लिए खुले तौर पर देखने लायक हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी के सभी समर्थकों में से मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा निराश है। यह सच है कि मध्यम वर्ग के काफी लोगों ने भाजपा को उसके हिंदुत्व के एजेंडे के कारण वोट दिया, लेकिन यह कहना गलत है कि हर मोदी समर्थक गुप्त (या यहां तक कि खुले तौर पर) सांप्रदायिक है। शिक्षित मध्यम वर्ग के कई लोगों ने भाजपा का समर्थन किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह विकास को बढ़ावा देगा और उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जिन्होंने भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की कोशिश की है, जिसके बारे में मोदी अक्सर बात करते हैं।

नरेंद्र मोदी से मध्यम वर्ग का मोहभंग पिछले आम चुनाव अभियान के दौरान शुरू हुआ। कभी-कभी मोदी ने कुछ ऐसा कहा जो उन्हें पसंद आया, लेकिन सभी बड़े भाषण, जो कैंपेन की दिशा निर्धारित करते थे और जिन्हें सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सबसे अधिक कवर किया गया था, वे हमलावर भाषण थे। प्रधानमंत्री के कैंपेन का मुख्य विषय नकारात्मक था। भाजपा ने बार-बार कहा कि कांग्रेस अब महत्वहीन पार्टी बन गई है, लेकिन लगता है कि यह संदेश प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा। उनके कई भाषण कांग्रेस पर सीधे हमले थे, जिसमें उनके घोषणापत्र के वादों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। इन हमलों में सांप्रदायिकता का भी समावेश था। कांग्रेस न केवल हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनने जा रही थी और गरीब किसानों की भैंसें जब्त करने जा रही थी, बल्कि ये सब मुसलमानों को देने जा रही थी।

अतीत में ऐसा समय भी आया था जब इस संदेश का असर हो सकता था, लेकिन यह चुनाव उनमें से एक नहीं था। शिक्षित मध्यम वर्ग, जो अच्छे दिनों की उम्मीद कर रहा था, भैंस छीनने की चर्चा और सांप्रदायिकता के खुलेआम फैलाए गए प्रोपेगेंडा से निराश हो गया। आप शायद यह तर्क दे सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए राजनेताओं को भावनात्मक बातें कहने की जरूरत होती है, लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं, तो वे ऐसी नीतियों को लागू करते हैं जो उनके मूल वोटर को खुश करती हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन उस मामले में, मोदी भाजपा-समर्थक मध्यम वर्ग को अपना मूल वोटर नहीं मानते। बजट, जो इस वर्ग को आश्वस्त करने और प्रोत्साहित करने का एक अवसर होना चाहिए था, ने उन्हें लगभग कुछ भी नहीं दिया। इसके बजाय, कर प्रस्तावों ने मध्यम वर्ग की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और जब दंडात्मक कर प्रस्ताव को वापस लेने की बात आई, तो जनता के विरोध के बाद, यह इतना आधा-अधूरा और इतना खराब था कि इसने मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तब से, सरकार ने ऐसा व्यवहार करना जारी रखा है जैसे कि मध्यम वर्ग इसके लिए कोई महत्व नहीं रखता; केवल उसके अमीर दोस्त ही मायने रखते हैं। पूरे सोशल मीडिया पर, इस खुलासे को लेकर व्यापक गुस्सा है कि करदाताओं का एक छोटा सा हिस्सा (हमारी आबादी का लगभग 2 प्रतिशत) पूरे कॉर्पोरेट क्षेत्र की तुलना में अधिक आयकर का भुगतान करता है।

मध्यम वर्ग की मदद करके भाजपा के लिए कांग्रेस के इस आरोप का मुकाबला करना काफी आसान होता कि सरकार कुलीन वर्गों की जेब में है, लेकिन किसी कारण से, इसने जानबूझकर इस धारणा को बढ़ावा देने का विकल्प चुना है कि यह एक ऐसी सरकार है जो ईमानदार करदाताओं के लिए कर आतंकवाद (एक ऐसा शब्द जिसका

बजट और अन्य गलत अनुमान

एक अनुभवी राजनेता के तौर पर प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि सत्ता में दस साल के बाद, हर सरकार को सत्ता विरोधी भावना का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि उसके वफादार भी आमतौर पर उसका समर्थन करने से थक जाते हैं। इस नकारात्मक भावना को संभालने का एकमात्र तरीका अपने समर्थक आधार पर वापस लौटना और उसे आश्वस्त करना है, उनके बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उनकी शिकायतों और निराशाओं के प्रति संवेदनशील दिखना। किसी कारण से प्रधानमंत्री ऐसा करने में इच्छुक नहीं दिखते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके शासनकाल के शुरुआती वादों में से बहुत कुछ अभी भी अधूरा है। रुपया डॉलर के मुकाबले 40 रुपए पर नहीं है, जैसा कि उनके समर्पित श्री श्री रविशंकर ने हमें ईमानदारी से आश्वासन दिया था। मुद्रास्फीति ने वास्तविक मध्यम वर्ग की आय को खत्म कर दिया है और यह स्पष्ट नहीं है कि करदाताओं को उनके करों के बदले में क्या मिल रहा है। जिन शानदार ट्रेनों का वादा किया गया था, वे कभी भी अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं और मौजूदा ट्रेनें नियमित रूप से पटरी से उतर जाती हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, जिससे लोग मारे जाते हैं, जबकि सरकार की शिक्षा नीति मुख्य रूप से पाठ्यपुस्तकों को फिर से लिखने पर केंद्रित है ताकि बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में झूठ बताया जा सके, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और तथाकथित कोचिंग सेंटरों की लापरवाही के कारण युवा मर जाते हैं। मध्यम वर्ग को प्रभावित करने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण दूरसंचार नवाचार स्पैम फोन कॉल में वृद्धि है, जो इस स्तर तक पहुंच गया है कि कम से कम लोग अज्ञात नंबरों से कॉल का जवाब देते हैं।

इस्तेमाल कुछ भाजपा समर्थक भी करते हैं) को बनाकर रखती है जबकि अपने अमीर साथियों को हजारों करोड़ रुपए कमाने देती है। जब आप मध्यम वर्ग को नकारात्मकता और सांप्रदायिक घृणा के अलावा कुछ नहीं देते हैं, तो उसके बाद जो मोहभंग होता है, वह आपके बाकी कामकाज को और भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। लोग पूछते हैं, रेलगाड़ियां पटरी से क्यों उतरती रहती हैं? नई सड़कें और पुल क्यों टूट रहे हैं? महंगी नई मूर्तियां क्यों गिर रही हैं? हमारे पड़ोस में हमारे इतने कम दोस्त क्यों हैं?

वे यह भी देखते हैं कि आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे करते हैं। यह कोई नई घटना नहीं है। सरकार ने कई वर्षों से विरोधियों को धमकाने और गिरफ्तार करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब, लोग पहले से कहीं अधिक ध्यान दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका अपवाद नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अदालत में उन लोगों को जमानत देने से इनकार करने के बारे में टिप्पणियां, जिनके खिलाफ प्राथमिक सबूत पूर्व अभियुक्तों (जिन्हें अब उनकी गवाही के बदले में माफ कर दिया गया है) के बयान हैं, विपक्ष के उत्पीड़न के भाजपा के मूल पर चोट करती है। जिन न्यायाधीशों ने बिना किसी आलोचना के सरकारी लाइन को स्वीकार कर लिया है, उन्हें अब अधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जब सरकार लोगों को बिना किसी मुकदमे की परवाह किए लंबे समय तक जेल में रखने की शक्ति खो देती है, तो यह विपक्ष को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने और जेल जाने की धमकियों के डर से मुक्त कर देती है।

शुरुआती दिनों में जब सबकुछ ठीक चल रहा था, मध्यम वर्ग इस आधार पर राजनेताओं को गिरफ्तार होने देने से संतुष्ट था क्योंकि उसका मानना था कि सभी राजनेता वैसे भी खराब हैं। लेकिन अब, यह स्पष्ट सवाल पूछ रहा है। क्या भाजपा में कोई खराब नहीं है? यह कैसा शासन है, जब आपने जिन लोगों को कभी बेईमान बताया था, उनके पाप धुल गए हैं और भाजपा में शामिल होते ही सभी मामले वापस ले लिए गए हैं? असंतोष बढ़ने के साथ ही, महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं? वे एक चतुर और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए उनके पास दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या है। फिलहाल, एकमात्र रणनीति यही दिखाई दे रही है कि हमला करो, हमला करो और हमला करो। भाजपा आईटी सेल अब प्रधानमंत्री के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके पोस्ट का लहजा एक समान रूप से आरोप लगाने वाला और नकारात्मक है। पार्टी के कीबोर्ड योद्धा अभी भी अर्ध-शिक्षित और गाली-गलौज करने वाले बने हुए हैं। जब विरोध प्रदर्शन होते हैं (उदाहरण के लिए कोलकाता में चौंकाने वाले आरजी-कर बलात्कार के खिलाफ), तो रणनीति पुलिस को उकसाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना है। क्या यह सब वाकई जरूरी है? क्या यह मदद करता भी है? क्यों न इस देश के ईमानदार वेतनभोगी लोगों की बात सुनी जाए, जिनमें से कई ने मोदी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मोदी उन पर और उनके मूल्यों पर विश्वास करते हैं? उनकी चिंताओं को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? उन्हें असहनीय कर बोझ से कुछ राहत क्यों नहीं दी जाती? अगर आप कुलीन वर्ग के प्रति इतने उदार हो सकते हैं, तो कम से कम मध्यम वर्ग को कुछ टुकड़ों का हकदार होना चाहिए।

कोई भी सरकार किसी एक रणनीति के आधार पर अपना भविष्य नहीं बनाती। इस तरह, अगर चीजें प्लान-ए के अनुसार नहीं भी होती हैं, तो कम से कम एक प्लान-बी तो होता ही है और आशावादी रूप से प्लान-सी और इसी तरह आगे भी बढ़ता रहता है। मोदी सरकार इस नियम का अपवाद हो सकती है। जब वो पिछले आम चुनाव में गई थी, तो उसे इतना यकीन था कि वह अधिक बहुमत के साथ वापस आएगी कि उसके पास केवल एक प्लान-ए था और वह थी मोदी क्रांति को जारी रखना और भारत को बदलना। जैसा कि हम अब जानते हैं, भाजपा ने अपनी संभावनाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया और प्रधानमंत्री ने जिस 400-पार का दावा किया, वो कभी नहीं हुई। यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी भाजपा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब पूरा विपक्ष जश्न मना रहा था, भाजपा ने प्लान-बी बनाने की कोशिश की। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों के समर्थन का भरोसा पाकर, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है, कि सबकुछ पहले जैसा ही चल रहा है। दक्षिण एशियाई नेता शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचे। समर्थकों ने मोदी...मोदी...मोदी... के नारे लगाए। निरंतरता पर जोर देने के लिए शीर्ष कैबिनेट पदों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया।

● इंद्र कुमार

भाजपा का भ्रम

अगर इस समय सहयोगी दलों या इंडिया ब्लॉक से कोई खतरा नहीं है, तो मोदी सरकार के यू-टर्न की क्या वजह है? इसका कारण यह है कि पार्टी को अभी भी पूरा पता नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान क्यों हुआ। आम धारणा यह है कि 400 पार के नारे की वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बारे में भाजपा के इरादे पर संदेह करने लगे। हालांकि, हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। जैसा कि कई भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अभी भी पार्टी के सहयोगियों से पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या गलत हुआ। जाहिर है, कोई भी उनकी लोकप्रियता के ग्राफ के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन कई लोगों ने 400 पार के नारे पर सवाल उठाए हैं। अगर इस नारे की वजह से उप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भाजपा को नुकसान हुआ, तो इसका असर मप्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और अन्य जगहों पर क्यों नहीं हुआ? सच्चाई यह भी है कि भाजपा ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की, जहां अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी करीब 40 प्रतिशत है। यहां मुद्दा यह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रासंगिक सवालों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक चुनावों में क्यों ठंडे पड़ गए? पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह घोषणा करने की सलाह किसने दी कि भाजपा आज इतनी सक्षम हो गई है कि उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है? बाहरी लोगों को भाजपा में शामिल करने का मानदंड क्या है- बिहार के हिस्ट्रीशीटर सुनील पांडे इसका ताजा उदाहरण हैं? बाहरी लोगों को टिकट देने के लिए कौन जिम्मेदार था और किस विचार से? पार्टी की आंतरिक सर्वेक्षण एजेंसियों के लिए कौन जवाबदेह है, जिन्होंने जीतने योग्य उम्मीदवारों के बारे में भ्रामक रिपोर्ट दी? पार्टी के टिकटों के मनमाने वितरण के लिए कौन जिम्मेदार था?

देश में पिछले एक दशक से राजनीति का नया रूप देखने को मिल रहा है। इसके तहत पार्टियों के नेताओं में गरीब और दलित के यहां भोजन करने की परंपरा पनपी है। आजादी के 77 साल बाद भी देश में गरीबों और दलितों की जो स्थिति है, उसको देखते हुए यह साफ हो जाता है कि उनके यहां नेताओं का भोजन करना केवल चुनावी स्टंट है। दरअसल, नेता ऐसा तभी करते हैं जब चुनाव सिर पर होता है। चुनाव जीतने के बाद कोई भी इनके दुख-दर्द को समझने और दूर करने की कोशिश नहीं करता है।

गरीबों के घर दावत का चलन

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र का चुनावी नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। उन्होंने कोल्हापुर में एक दलित परिवार के साथ खाना पकाने और खाने का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा- दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम सनदे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बंटाने का मौका दिया। हमने मिलकर हरभरयाची भाजी बनाई। इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमने बात की। यह तस्वीर हर बार हमें उस समय दिखाई देती है, जब चुनाव आते हैं। चुनाव आते ही नेताओं का गरीब और दलित प्रेम उमड़ पड़ता है।

यह संभावना काफी है कि नेताओं के करीबी दायरे में दलित समुदाय के कई प्रोफेशनल हों। देशभर में ज्यादातर राज्य सरकारों में दलित अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस वाले, स्वास्थ्यकर्मी और राज्य के दूसरे विभागों के कर्मचारी होते हैं। अगर ग्रामीण दलित वोट हासिल करने का लक्ष्य है तो दलित सरपंच और जमीनी स्तर के नेता होते हैं, जो सुमदाय के सरोकारों को ढंग से बता सकते हैं। फिर भी फोटो खिंचवाने की बारी आती है तो हमारे नेता और उनकी मीडिया टीमें सबसे कमजोर और वंचित दलित परिवारों में पहुंचती हैं और उनके परिवार पर एहसान का वह बोझ लाद देते हैं, जिसे उन्होंने कभी मांगा ही नहीं होता है। कैसे इस झूठी उदारता, कमजोरी और अपमान की छवि को दलित वोटर स्वीकार कर पाते हैं?

दलितों की छवि का ऑनलाइन सर्च दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने ला देती है। असहायता, अपमान और अछूत होने की छवियां; क्षत-विक्षत, उत्पीड़न की शिकार और अपमानित शवों की छवियां; मानव जीवन से गरिमा छीन लेने और जाति व्यवस्था को जबरन सर्वोच्च ठहराने की छवियां ही देखने को मिलेंगी। दलित जुड़ाव के नाम पर हमारे चालबाज नेताओं की तस्वीर खिंचाना भी इसी दायरे में आता है। आज के दौर और दिन भी ऊंची जातियों में ढेरों लोग दलितों को समान मनुष्य नहीं मानते। उनके संकुचित नजरिए में दलित उनके सामने टेबल पर नहीं बैठ सकते, सम्मानित तरीके से खाना नहीं खा सकते या रोजाना की बातचीत में उनसे बराबरी की बात नहीं कर सकते। ऊंची जातियों का नजरिया उम्मीद करता है कि दलित जमीन पर बैठें, वे आएं तो खड़े हो जाएं, जब पूछा जाए तभी बोलें, जो कहा जाए वही करें, और जो दिया जाए वह चुपचाप ले लें। इसी वजह से जब भी दलित आकांक्षित समाज व्यवस्था को चुनौती देने की जुर्रत करते हैं, ऊंची जातियां अपने नियम-कायदों को लागू करने के लिए हिंसा पर उतर आती हैं। इन सामाजिक सच्चाईयों के

विश्वास जीतने का तरीका

गांव-देहात में खाना और चाय-पानी आपसी रिश्तों को बढ़ाते हैं। अक्सर ही नेता गांव व कस्बों में जाकर किसी के घर खाना खाते हैं। एक तो इससे उस वर्ग विशेष का सम्मान बढ़ता है। दूसरा उस नेता के जननेता होने का संदेश भी जाता है। मतलब जो जनता के बीच रहता है। ध्यान रहे कि गांवों में लड़ाई-झगड़ा होने पर लोगों का हुक्का-पानी भी बंद किया जाता है। मतलब ना तो उनके घर कोई खाने जाएगा, ना ही बुलाएगा। जाति तोड़ने के लिए भी रोटी-बेटी का नारा दिया गया था। गांव देहात में एक-दूसरे के घर खाना-खाना अनिवार्य है, प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए। आज भी गांवों में शादियों में जब तक कोई कई बार न बुलाए, लोग खाने नहीं जाते। राजनीतिक पार्टियां गांवों की इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं।

मद्देनजर, ऊंची जाति के उदार नेताओं की किसी कमजोर दलित परिवार के घर खाना खाने की तस्वीरें इरादतन लगती हैं। वह तस्वीर सत्ता और ताकत का इजहार करती हैं, जो ऊंची जातियों की विशाल बहुसंख्या को स्वीकार्य हैं। ये लोग अपनी ऊंची जाति की पूंजी पर ही जिंदगी जीते हैं।

किसी ऊंची जाति के आदमी की दलित आदमी से मेल-जोल की फोटो जाति विशेषधिकार को खतरे में डालती, वह जाति व्यवस्था को नीचा नहीं दिखाती, इससे जाति नहीं टूटती। उग्र जातिवादियों के लिए ये तस्वीरें जाति की सर्वोच्चता कायम रहने का संकेत हैं और उदार जातिवादियों को ये रक्षक होने का एहसास दिलाती हैं, जिससे उनकी नैतिक सर्वोच्चता कायम रहती है। दलितों के लिए, इसका इरादा यह याद दिलाने का होता है कि जाति में बंटे समाज में उनकी जगह क्या है, यानी वे सामाजिक पिरामिड के सबसे नीचे हैं, ऊंची जातियों की सेवा के लिए हैं और उनका वजूद ऊंची जातियों के एहसान पर आधारित है।

बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे प्रसिद्ध छवि नीले रंग के पहनावे में एक हाथ में भारतीय संविधान और दूसरे हाथ को आगे उठाए हुए है। उनकी यही छवि अनगिनत मूर्तियों में दोहराई गई है, जो देशभर में, संसद से सड़कों तक की शोभा बढ़ाती है। आज, दलित फिल्मकार, कलाकार, लेखक और एक्टिविस्ट हैं, जो ऐसी छवि बनाते हैं कि दलित अब असहाय नहीं, बल्कि ऊपर उठता समुदाय है। देश के कई हिस्सों में खास तरह से कपड़े पहनने से भी दलितों की हत्या हो सकती है, ऐसे में दलित नौजवान अपने हक-हुकूक को हासिल करने का जज्बा दिखा रहे हैं। तो, फिर हमारे नेता क्यों दलित जुड़ाव के नाम पर वही अभिनय करते हैं? हर चुनाव के दौर में एक जैसी ही तस्वीरों की कल्पना, प्रचार और बार-बार दोहराया क्यों जाता है? कहने का मतलब यह नहीं है कि गरीब और वंचितों को हाई प्रोफाइल तस्वीरों में आने का हक नहीं है, लेकिन उनके साथ उस गरिमा से तो जुड़िए, जिसके वे हकदार हैं। दलित जुड़ाव सिर्फ एकतरफा नहीं होना चाहिए। राज्य विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों से बात कीजिए कि कैसे सरकार उनके अकादमिक करियर में मदद कर सकती है; दलित लड़कियों और महिलाओं से बात कीजिए कि कैसे जीवन में हर मोड़ पर उनके सामने खतरे और चुनौतियां होती हैं; दलित किसानों से वादा किए गए जमीन के पट्टों के बारे में बात कीजिए; सरकारी और निजी क्षेत्र में दलित पेशेवरों से उनके मौकों के बारे में बात कीजिए। दलित समुदाय को बराबरी के आधार पर जोड़िए सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं।

चुनाव आते ही राजनीति में नए-नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। अभी से नहीं, वर्षों से। कोई नेता किसी गरीब के घर जाकर भोजन करता है। कोई राजनेता किसी दलित के कंधे पर हाथ रख कर सर्वधर्म, सम भाव का दिखावा करता है। नेताओं और हमारे समाज में असल में यह सम भाव कब आएगा? आएगा भी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा वातावरण, बाजार ही कुछ ऐसा है जिसमें गरीब और ज्यादा गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है। सरकारों की नीतियों की पोलें और प्रशासन की कुव्यवस्था गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचने ही नहीं देती। जिन तक लाभ पहुंचता है, वे इसका बेजा फायदा उठाते रहते हैं, जबकि अधिसंख्य लोग इसी वजह से वंचित रह जाते हैं। ऊंच-नीच और भेदभाव की भावना ने समाज के कई तबकों तक न तो शिक्षा का उजाला पहुंचने दिया और न ही सुख सुविधाओं की रोशनी। कहते हैं हर रात की कोई न कोई सुबह जरूर होती है, लेकिन हैरत इस बात की है कि गरीबी की रात की सुबह हो ही नहीं पा रही!

आजादी के इतने सालों बाद भी उनकी रातें काली चीलों की तरह उड़ रही हैं। सुख-सुविधाओं का उन्होंने आज तक मुंह नहीं देखा। गरीबी उनके बच्चों को स्कूल का मुंह तक देखने नहीं देती। आखिर हमारी राजनीति और राजनेता सही मायने में इस बारे में कब सोचेंगे? कब इस बारे में कारगर नीतियां बनाकर उन्हें ईमानदारी से लागू करने या करवाने की इच्छाशक्ति दिखाएंगे? हर पांच साल में हर गरीब इस आस में वोट देता है कि इस बार की सरकार तो जरूर उसका कल्याण करेगी, लेकिन वो दिन, वो समय पिछले 77 साल में नहीं आ सका। दरअसल, राजनीति का उद्देश्य ही बदल चुका है। नेताओं का ध्यान जन कल्याण की बजाय वोट कबाड़ने तक ही केंद्रित होकर रह गया है। वे जनता को वोट मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझते। वे पांच साल में सिर्फ चुनाव के वक्त नजर आते हैं। यह व्यवस्था, यह ढर्रा बदलना चाहिए। सम भाव तभी आ सकता है।

एक समय वह भी था जब देश की राजनीति में ग्रामीण, किसान और पिछड़ा वर्ग से नेता निकला करते थे। इनमें से कई नेताओं ने गांव-देहात में अचानक पहुंचकर सरप्राइज करने की नीति अपनाई। जैसे हरियाणा में चौधरी देवीलाल, राजस्थान में नाथूराम मिग्गा और बिहार में लालू प्रसाद यादव। चौधरी देवीलाल के बारे में कहा जाता है कि वो खेत में फसल काट रहे किसान के पास भी पहुंच जाते थे और वहीं बैठकर बात करने लगते। अगर किसी चौपाल पर कुछ बुजुर्ग हुक्का पीते दिख जाते तो वहीं गाड़ी रोककर हुक्का पीने लगते। ऐसा ही लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो मजदूर के घर से भी मांग कर दाल भात खा लेते। राजस्थान के नाथूराम मिग्गा के बारे में भी ऐसे ही रोचक किस्से हैं। लेकिन देवीलाल के समकालीन राव बिरेंद्र, भजनलाल या बंसीलाल ऐसा नहीं करते थे। लालू के समकालीन नेता भी इस तरह गरीबों के घर खाना नहीं खाने जाते थे। सोशियोलॉजिस्ट व प्रोफेसर डॉ. रणबीर सिंह का कहना है कि इस तकनीक के जरिए ये बात स्थापित की जाती है कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूं।

● रजनीकांत पारे

मुद्दा ये है कि क्या इससे लोग प्रभावित होते हैं

आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अव्वल तो देश में कोई किसान नेता ही नहीं है। दिल्ली जैसे महानगर से जाकर कोई नेता किसी गरीब किसान के घर खाना खा रहा है तो जनता नेता की चालाकी समझ जाती है। दूसरा सिर्फ चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें आना आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। कुछ लोगों का मानना है कि अब ऐसे कोई वोट बैंक नहीं बढ़ा सकता। जनता समझदार हो चुकी है। इस तरह किसी पिछड़ा वर्ग या किसी किसान के घर भोजन करना आर्टिफिशियल लगता है। यही वजह है कि आज गरीबों के घर खाना खाते हुए जो तस्वीरें आती हैं, उनसे किसी की सहृदयता या प्रेम का भाव नहीं टपकता, बल्कि इन तस्वीरों का मजाक बनाया जाने लगा है। वजह है सिर्फ कृत्रिमता।

इनके दर्द की दवा नहीं...

छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस कारण नक्सलियों की कमर टूट गई है। नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं। यह देख-सुन कर वे लोग राहत की सांस ले रहे हैं जिनके परिवार नक्सली हमले में उजड़ गए हैं। लेकिन नक्सलियों ने उन्हें जो दर्द दिया है उसकी कोई दवा नहीं है। वे लोग अब भी सालों पुराने मंजर को याद कर सिहर जाते हैं।

20 मार्च, 2019 को मेला देखने के लिए 27 वर्षीय राजाराम अवलम गाड़ी में अपने परिवार के 9 सदस्यों को लेकर घर से निकले थे। इनमें उनकी पत्नी निकिता, मंगली और गुट्टाराम अवलम भी थे। बीजापुर जिले के कडेर गांव के रहने वाले राजाराम ने बताया कि रास्ते में एक जगह नक्सलियों ने आईईडी लगा रखी थी। अचानक जोर का धमाका हुआ और उनकी गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि गाड़ी के एक तरफ के पहिए के नीचे धमाका हुआ, इसलिए गाड़ी हवा में उछलकर पलट गई। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। निकिता की आंख के पास कांच का टुकड़ा धंस गया, सिर में गंभीर चोट लगी। आज भी उन्हें सिर में दबाव-सा महसूस होता है। मंगली की कमर, बाएं कंधे और दाएं पैर के घुटने में चोट आई। आज भी वे बिना सहारा लिए काम नहीं कर पातीं। शरीर में दर्द रहता है, जिसके लिए दवाएं खाती हैं। राजाराम का बायां हाथ टूट गया, जिसमें रॉड लगवानी पड़ी। इस हादसे में उनके ऊपर के सारे दांत भी टूट गए। आज स्थिति यह है कि राजाराम अवलम न तो गाड़ी चला सकते हैं, न ही खेती कर सकते हैं। गुट्टाराम कहते हैं कि पीठ में गंभीर चोट के बाद वे मेहनत का कोई काम नहीं कर पाते हैं। उस हादसे ने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदतर बना दिया।

जिला बीजापुर के नीलाकांकेर की रहने वाली 50 वर्षीया काका रामबाई तेंदूपत्ता इकट्ठा करके अपने परिवार की जीविका चलाती थीं। हाल ही में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल होकर दिव्यांग हो गईं। तेंदूपत्ता बस्तर क्षेत्र के वनवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक वनोपज है। काका रामबाई जैसी महिलाएं तेंदूपत्ता संग्रह करके अपनी आजीविका चलाती हैं। वर्ष में नियत समय पर जब महिलाएं तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जंगल जाती हैं, प्रदेश सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप बोनस प्रदान करती है। इसी बोनस के लिए रामबाई अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ उसूर गई थीं। लौटते समय अनजाने में उन्होंने अपना पैर नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए आईईडी पर रख दिया। पैर हटाते ही धमाका हुआ। इस हादसे में रामबाई के पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी बाईं आंख पूरी तरह खराब हो गई। दाईं आंख से भी न के बराबर दिखाई देता है। काका रामबाई के लिए यह दुर्घटना न केवल शारीरिक नुकसान लेकर आई है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी इसने बुरी तरह प्रभावित किया है। अब रामबाई जीवनभर दूसरों पर निर्भर हो गई हैं। नक्सलियों के आतंक ने उनकी रोजी-रोटी छीन ली। इस कारण उनका परिवार अब गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया है।

छबिलाल मरकाम 43 वर्ष के हैं। वह बस्तर जिले के गांव छिंदखडक के रहने वाले हैं। 16 जून 2018 की शाम छबिलाल के पिता का निधन हो गया था। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वह अपने भाई मदन कुमार और अपने चाचा के साथ घर पर लौटे थे। परिवार में शोक का माहौल था। उसी रात उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। छबिलाल के नाम से आवाज दी गई। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो वहां पर हथियारबंद नक्सली खड़े हुए थे। उन्होंने छबिलाल से उसका नाम पूछा। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया नक्सलियों ने उन्हें बाहर खींच लिया। उनके साथ बुरी तरह मारपीट करनी शुरू कर दी। परिवार के सभी लोग बाहर निकल आए। नक्सलियों ने सभी पर हथियार तान दिए।

परिवार के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो नक्सलियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। वर्दीधारी नक्सलियों ने छबिलाल को बुरी तरह पीटा। वे अधमरा होने तक उन्हें बंदूकों के बट और लात घूंसों से मारते रहे। वहां से जाते समय नक्सलियों ने छबिलाल को दो गोलियां मारीं। एक गोली उनकी कनपटी को छूकर निकल गई, दूसरी उनके पैर में लगी। लंबे उपचार के बाद किसी तरह उनकी जान तो बच गई लेकिन एक कान से सुनने की क्षमता चली गई। 31 वर्षीय तुलाराम बड़गांव, जिला नारायणपुर के रहने वाले हैं। 27 मई, 2002 की आधी रात के बाद का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में था। अचानक रात को ताबड़तोड़ फायरिंग करने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाज सुनकर गांव वाले सहम गए। पता चला कि नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही है। पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया था।

● रायपुर से टीपी सिंह

आंखों की रोशनी हुई कम

60 वर्षीय कन्हेर बेलसरिया जिला नारायणपुर के सोनुपर के रहने वाले हैं। घटना 6 अप्रैल, 2004 की है। सुरक्षा बलों का एक दस्ता नक्सलियों की तलाश में निकला हुआ था। लौटते समय नारायणपुर पहुंचने से पहले सोनपुर के पास ही नक्सलियों ने पुलिस पर बम और गोलियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस ने वापस जवाब दिया तो नक्सली जंगल की तरफ भाग निकले। इस बीच कन्हेर वहां से गुजर रहे थे। तभी सड़क किनारे माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी पर उनका पैर पड़ गया। यह आईईडी नक्सलियों ने पुलिस के जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाई थी। आईईडी के धमाके में कन्हेर बेलसरिया सहित पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्हेर के सीने, बाएं हाथ और आंखों में चोट लगी। उनका बायां हाथ सदा के लिए बेकार हो गया। आंखों से दिखाई देना बहुत कम हो गया। महीनों उनका उपचार चला जिसमें परिवार पर कर्ज भी हो गया। इस घटना को हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तब से अभी तक कन्हेर अपने घरवालों पर ही निर्भर है। अपनी इसी तकलीफ को बयां करने के लिए वह दिल्ली पहुंचे थे।

सामाजिक न्याय से सत्ता...

हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार थमने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासी तपिश गरमा गई है। भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए राज्य में सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है तो कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन अपनी वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में पुरजोर तरीके से चुनावी अभियान चलाने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फोकस अब महाराष्ट्र पर है। राहुल गांधी 4 और 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में रहे। जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने सामाजिक न्याय के एजेंडे को सेट करने का दांव चला।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। यही वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से निपटने के बाद कांग्रेस ने अब महाराष्ट्र पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। राहुल ने अपने दो दिवसीय दौरे से कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए आरक्षण की धरती कोल्हापुर को चुना। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन को दोबारा से पाने की कवायद में है, जिसके तहत ही पार्टी ने कोल्हापुर से अभियान शुरू करने की योजना बनाई। राहुल गांधी ने कोल्हापुर के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कर सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र की अस्मिता और सियासत में छत्रपति शिवाजी हमेशा से एक बेहद अहम प्रतीक रहे हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग स्थित इलाके में लगी छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरकर टूटने से महाराष्ट्र की सियासी तपिश बढ़ गई थी। कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने इस घटना को लेकर शिंदे के अगुवाई वाली सरकार पर जमकर हमला बोला था और भाजपा को कठघरे में खड़ा किया था। शिवाजी की मूर्ति के गिरने से जुड़ा मामला इतना बढ़ गया था, जिसके चलते भाजपा और शिंदे सरकार बैकफुट पर आ गई थी। ऐसे में शिंदे सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने सिर्फ दुख ही जाहिर नहीं किया बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। ऐसे में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव अभियान का आगाज शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के साथ किया, जिसके सियासी मायने को साफतौर पर समझा जा सकता है। इस तरह कांग्रेस शिवाजी महाराज के बहाने महाराष्ट्र में खिसके अपने सियासी आधार को दोबारा से पाने की कोशिश में है।

राहुल गांधी ने कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया तो अगले दिन संविधान बचाओ सम्मेलन में शिरकत कर सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार दी। राहुल गांधी लगातार आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में राहुल ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने के लिए कोल्हापुर को चुना है, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज ने यहीं से सामाजिक न्याय की आवाज उठाते हुए सबसे पहले आरक्षण का अलख जगाया था। स्थानीय लोग सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में छत्रपति शाहू महाराज को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1902 में निचली जातियों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के मौजूदा सांसद छत्रपति शाहू हैं, जो कांग्रेस से जीते हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने में जुटे हैं। इसके लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को बढ़ाने की बात वो लगातार दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र का सियासी गेम ही पलट दिया था। कांग्रेस ने अपनी जीत के इस मंत्र को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाने की स्ट्रैटेजी बनाई है। दलित और ओबीसी जातियों को साधने के लिए राहुल कोल्हापुर से महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को भी उठा सकते हैं।

लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी जंग फतह करने के बाद से कांग्रेस के हौंसले बुलंद हैं। राज्य में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ही जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को विदर्भ और मराठावाड़ा इलाके में ज्यादा सीटें मिली हैं। कांग्रेस 2024 विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और जातिगत समीकरण साधने की कवायद में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा जाति के लोगों की आबादी है। राज्य में करीब 30 फीसदी मराठा समुदाय की आबादी है तो दलित-मुस्लिम की संख्या 11-11 फीसदी के करीब है। ओबीसी की आबादी करीब 40 फीसदी है, जो अलग-अलग जातियों में बंटी हुई है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 6 से 8 फीसदी के बीच है। विदर्भ में दलित तो मराठावाड़ा में मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में हैं।

● **बिन्दु माथुर**

मराठा बनाम गैर-मराठा का समीकरण

प्रदेश की सियासत में मराठा बनाम गैरमराठा का सियासी समीकरण सेट किया जाता रहा है। गैर-मराठा जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान जातियां आती हैं। भाजपा और संयुक्त शिवसेना का गढ़ गैर-मराठा जाति के लोगों के बीच रहा है। भाजपा ओबीसी के जरिए महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने में जुटी थी, लेकिन 2014 के बाद से मराठा वोटों को भी साधने का दांव चल रही है। ऐसे में ओबीसी वोटों में बिखराव हुआ है। कांग्रेस दलित, मराठा और मुस्लिम वोटों के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सियासत करती रही है। शरद पवार की राजनीति पूरी तरह मराठा समुदाय के इर्द-गिर्द सिमटी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, मराठा और मुस्लिम वोटर एकजुट होकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ रहे हैं, लेकिन ओबीसी में बिखराव हुआ। भाजपा को इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने इस फॉर्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें खुद और 17 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीतकर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। इसीलिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से धार देने के लिए उतर रहे हैं ताकि दलित, मराठा और ओबीसी को साधकर रखा जा सके।

योजनाओं ने बदली महिलाओं की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे था। आंकड़े दिखा रहे थे कि राज्य में बेटियां कम हो रही थीं। तब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वंशालिका, टाबरां रो ब्याव, लाडो, आठवां फेरा जैसी एक के बाद एक कई मुहिम शुरू की गई। पहले से भी कुछ काम चल रहे थे। बच्चियों का जन्म हो, वे बची रहें और उनकी सुरक्षा हो और उनका आर्थिक-सामाजिक विकास हो, यह बड़ी चिंता थी। 5 वर्ष में मुहिम के नतीजे दिखने लगे। खासतौर से लाइव बर्थ के आंकड़ों में वृद्धि ने आशा की किरण जगाई।

2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नाम से सरकारी अभियान शुरू हुआ, तब तक प्रदेश में जमीनी स्तर पर बहुत काम हो चुका था। परिणाम अच्छे आए तो प्रदेश की प्रशंसा भी होने लगी। इसी तरह, कोख में बेटियों को बचाने के लिए लाडो अभियान की कहानी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर के सरपंच संवाद में कहने का मौका मिला और इसी नाम से राजस्थान में एक योजना शुरू हुई। लेकिन कुछ नेताओं ने अच्छी समझ बनाने की बजाय ओछी राजनीति शुरू की तो उनका प्रतिकार भी हुआ। जब मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मंच से घूंघट हटाओ की बात की, तब सवाल उठा कि हिजाब के लिए भी यह बात कहते। उनके ही दौर में प्रदेश महिला अपराध में देश में अव्वल हो गया। ये वही लोग थे, जिनके साथियों पर और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर 1992 के अजमेर सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेल कांड के आरोप थे। इनमें अजमेर दरगाह का खादिम परिवार भी शामिल था। इस जलालत के कारण कई बेटियों ने आत्महत्या कर ली। पॉक्सो अदालत ने 32 साल बाद 6 अपराधियों को सजा सुनाई, मगर इस बारे में कोई आश्वस्त नहीं कि वे कब तक सलाखों के पीछे रहेंगे। राजनीति, अपराधी, पुलिस और जांच एजेंसियां, सबने बेटियों का भरोसा तोड़ा है। कुछ जुझारू पत्रकारों ने जान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।

हमारे सामने कई और विरोधाभास हैं। बीते कुछ वर्षों के दौरान कानून कड़े तो हुए हैं, लेकिन न्याय मिलना अब भी आसान नहीं है। अपराध बढ़े ही नहीं हैं, बल्कि और जघन्य हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुष्कर्म के मामले में 94 प्रतिशत लोग जानकार या करीबी होते हैं। 31 प्रतिशत अपराध तो घरों में होने वाली हिंसा के हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि खुदा की खिदमत करने वाले लोग भी ऐसे अपराधों में शामिल होते हैं। राजस्थान के 1992 के सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेल कांड में यह बात हमें देखने को मिली। देश में दहेज के लिए कानून 1961 का है, लेकिन दहेज प्रताड़ना आज भी कलंक के तौर पर मौजूद है। महिला सशक्तिकरण की रट लगाने वालों का इतिहास बोध जागेगा तो उन्हें बाहरी सोच को आयात नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास मीरा जैसे कई प्रतिमान हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं। हमारे यहां महिलाएं अपना पथ खुद चुनती हैं और हर संघर्ष के बीच उस पर टिकी रहती हैं। लीक पर चलने से मना कर देती हैं। साहित्य रचती हैं, संबंधों का सम्मान बढ़ाती हैं। वही अहंकारी समाज उन्हें पूजता है, उसके आगे नतमस्तक होता है। आज दक्षता बढ़ाने पर, प्रशिक्षण पर तो काम होना ही चाहिए। लेकिन अपनी उस जिम्मेदारी से तब तक मुक्त नहीं हो सकते, जब तक हर महिला अपराध से मुक्त हो जाए। आज राजस्थान विधानसभा में चुने 22 प्रतिशत विधायक गंभीर अपराध वाले हैं, तो ये मुद्दे सदन में कैसे गूंजेंगे? अजमेर कांड के समय भी विधानसभा में खामोशी रही। इसलिए इस अपराध से सत्ता-प्रतिपक्ष किसी को मुक्त नहीं किया जा सकता। भगिनी निवेदिता का कहना था कि भारतीय समस्याओं का समाधान भारतीय विचार से ही उपजेगा। इस पर चिंतन करना होगा कि हमारे अपने समाज के भीतर क्या विकार हैं और महिला अपराधों से निपटने के लिए हमारी समग्र सोच क्या बनी है? बेटियों के साथ अपराध चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, सिहरन होती है। जिस पर बीतती है, उसे जीवनभर पीड़ा सहनी पड़ती है। समाज की सोच बदलने और न्याय की प्रक्रिया दोनों त्वरित होनी चाहिए।

महिला सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा सिंह का कहना है कि देश मे भले ही महिला-पुरुष के बीच समानता की बात की जाती हो, लेकिन आज भी पितृसत्ता सोच ने महिलाओं को दहलीज लांघने पर पाबंदी लगा रखी है। घर हो या ऑफिस महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है। हर बार कमजोर दिखाने और समझाने की कोशिश होती है, जबकि महिला किसी तरह से पुरुषों से पीछे नहीं हैं। देश को चलाने वाली प्रधानमंत्री की बात हो या आज की मौजूदा राष्ट्रपति की, अंतरिक्ष पर जाने वाली महिला की बात हो या फिर हर सड़क पर गाड़ियां दौड़ाती महिला हो। जहां पर भी महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने अपने आप को बेहतर साबित किया है। राजस्थान में महिलाओं की समानता की बात हो रही है, लेकिन आंकड़े बड़े डराने वाले हैं। लैंगिक समानता को लेकर उठ रहे सवालों पर दलित महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सुमन देवठिया कहती हैं कि सामाजिक और लैंगिक असमानता जब तक समाज में है तब तक समानता नहीं हो सकती है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

हाईकोर्ट में 33 में सिर्फ 3 जज

न्याय का नाम आते ही देवी का चेहरा सामने आता है, लेकिन जज की कुर्सी पर छोटी अदालतों में ही महिलाएं नजर आती हैं। अधीनस्थ जजों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की बराबरी के करीब है, लेकिन 33 हाईकोर्ट न्यायाधीशों में 3 ही महिला हैं। हाईकोर्ट से नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में प्रदेश में एक ही महिला है। हाईकोर्ट और विधि विभाग में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत महिलाएं भी कम हैं। न्यायपालिका में महिलाओं के कम आने का एक बड़ा कारण यह बताया जाता रहा है कि कुछ साल पहले तक वकालत में महिलाएं कम थीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रदेश में महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ी है और 2016 के बाद से 50 प्रतिशत से अधिक पदों पर महिलाओं का ही चयन हो रहा है। हालांकि न्यायिक अधिकारियों में महिलाओं के बढ़ने का सिलसिला 2013 में ही शुरू हो गया था। प्रदेश में 1300 से अधिक न्यायिक अधिकारी हैं, जिनमें से 618 महिलाएं हैं। इससे करीब 46 प्रतिशत पदों पर महिलाएं पहुंच गई हैं।

उपचुनाव में हार का डर

कुछ दिनों से उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का रोना प्रदेश की जनता से रो रहे हैं एवं बार-बार यह कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने भाषण में तो यह तक कह दिया कि हिंदू बटेंगे, तो कटेंगे। ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी सत्ता बचाकर रखने के लिए हिंदू-मुस्लिम करने के सिवाय अब कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है। उनके शासन में हिंदुओं के प्रति स्पष्ट भेदभाव भी दिखता है। पिछड़ा एवं दलित वर्ग के लोग ही उप्र में सबसे अधिक संख्या वाले मतदाता हैं; मगर चुनाव के अवसर के अतिरिक्त इनके साथ भेदभाव ही होता है। अब पुनः जब सत्ता पर आंच आ रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं को एकजुट करने की चिंता सता रही है। हालांकि अभी उप्र में भाजपा के हाथ में 2027 तक सत्ता है। मगर भाजपा के प्रति मतदाताओं का रोष दिखने लगा है। एकता की बात करें, तो भाजपा में ही एकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही कई मंत्री उनके धुर-विरोधी हैं। अपनी पार्टी में ही मतभेद एवं मनभेद के अतिरिक्त एक-दूसरे पर अविश्वास करने वाले भाजपा नेताओं के उप्र में अगुवा बने योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकता को लेकर चिंतित इसलिए भी हैं, क्योंकि अब मतदाता ही उनकी सत्ता बचा सकते हैं।

राजनीति के जानकार एवं अनेक बार छोटे चुनाव लड़ चुके प्रदीप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं की चिंता से अधिक अपनी सत्ता की चिंता है। लोकसभा चुनाव में उप्र से भाजपा बुरी तरह पिछड़ गई है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को भविष्य का डर है। अब विधानसभा के उपचुनावों में जीत के आसार नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। इसी डर के चलते योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को बिना मतलब का डर बार-बार दिखा रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार डराने के पीछे उनका अपना डर है। भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही हिंदुओं को सचेत किया था कि वो एकजुट रहें। इसके उपरांत भी हिंदू बंट रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा, तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो सकती है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र यह स्पष्ट नहीं कर सके कि बांग्लादेश की स्थिति से उनका क्या तात्पर्य है? बांग्लादेश में सत्ता पलट का खेल हो गया एवं वहां स्थितियां अलग थीं। यह पूछने पर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदुओं को क्या लाभ हुआ है? देवेंद्र इतना ही बोलते रहे, हिंदू आज खुलकर जी रहे हैं एवं सुरक्षित हैं। पहले हिंदुओं को डरकर रहना पड़ता था। भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र के इस उत्तर का भी कोई औचित्य समझ नहीं आता।

वास्तव में लोकसभा चुनाव के नतीजों का डर भाजपा में दिखने लगा है। विश्लेषक कहते हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में स्थिति को लेकर भाजपा की आंतरिक पड़ताल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेचैन किए हुए है। विश्लेषक कहते हैं कि उप्र में भाजपा एवं योगी आदित्यनाथ सरकार कई मोर्चों पर विफल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ न विकास के नाम पर रामराज्य की कल्पना को साकार कर सके एवं न प्रदेश की व्यवस्था में सुधार ला सके। केवल विज्ञापनों एवं भाषणों में ही रामराज्य आया है एवं व्यवस्था में सुधार हुआ है। धरातल पर तो स्थिति कुछ और है। लगता है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 29 सीटों की हानि होने से योगी आदित्यनाथ थर्राए हुए हैं। ऊपर से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनके पद पर वक्र-दृष्टि गढ़ाए बैठे हैं। सत्ता के लिए भाजपा नेताओं में व्याप्त यह मनमुटाव योगी आदित्यनाथ को जनता के रोष से अधिक हानि पहुंचा रहा है। लगता है उपचुनाव में भाजपा के हार का डर भी चुनाव नहीं होने दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगभग सात वर्ष के शासन में सरकार की कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के शासन के इन सात वर्षों में कई पत्रकारों की हत्या हुई, कई पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने आपराधिक मुकदमे दायर किए एवं कई पत्रकारों को जेल भेजा गया। हालात ये रहे कि सच लिखने वाले पत्रकारों को धमकियां मिलती रहीं। मगर अब स्थिति यह आ पहुंची है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया संचालकों को साधने का प्रयास करना पड़ रहा है। सुनने में आया है कि लोकसभा चुनाव में मनचाहे परिणाम न आने के कारणों पर भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण में पता चला है कि लोकसभा चुनाव में हार का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया पर भाजपा के विरुद्ध चली मुहिम भी थी। विपक्ष को इसका बड़ा लाभ हुआ। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोशल मीडिया नीति को मंत्रिमंडल में पारित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अर्थात् संचालकों को हर महीने दो लाख रुपए से लेकर आठ लाख रुपए तक सरकार दे सकती है। विश्लेषक कहते हैं कि यह राशि सोशल मीडिया पर योगी सरकार की प्रशंसा के हिसाब से वितरित हो सकती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

नाम बदलने में मुख्यमंत्री योगी का कोई मुकाबला नहीं

उप्र के मुख्यमंत्री योगी जगहों एवं रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने में पूरे देश में प्रथम हो गए हैं। विकास हो अथवा न हो; मगर जगहों के नाम बदलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं भूलते। प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने के बाद अब 27 अगस्त को 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की आधिकारिक घोषणा की गई है। ये सभी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के हैं। इन स्टेशनों को अब संतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना जाएगा। प्रशासन ने जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम मां कालिकन धाम, फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम, अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम मां अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज हाल्ट स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान, निहालगढ़ स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन रखा है। मगर इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव ने तंज किया है कि भाजपा सरकार से आग्रह है कि केवल रेलवे स्टेशनों के नाम ही न बदलें, हालात भी बदलें। जब नाम बदलने से फुरसत मिल जाए, तो रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी कुछ विचार करें। सोशल मीडिया को पैसा देने को लेकर भी योगी को विपक्ष ने घेरा है।

कब तक टिकेंगे प्रशांत किशोर

चुनावी रणनीति से सक्रिय राजनीति में आने वाले प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक 12 महीने पहले बिहार में अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। पार्टी का नाम जन सुराज रखा गया है और दलित समुदाय के मनोज भारती इसके कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। गांधी मॉडल पर गठित जन सुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि, प्रशांत के लिए यह राह आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रशांत तभी बिहार की सियासत में टिकेंगे, जब वो राज्य के 3 सियासी मिथक को तोड़ पाएंगे। वरना जन सुराज का हाल भी उन्हीं 10 पार्टियों की तरह होगा, जो पिछले 24 साल में गठित होकर बिहार की सत्ता में अपने आस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।

बिहार में पिछले 24 साल में 10 पार्टियां गठित हुईं। इनमें से एक भी पार्टी राज्य की सत्ता में नहीं आ पाई। कुछ पार्टी जरूर सफल हुईं, लेकिन सिर्फ एक इलाके में। नवगठित कई पार्टियां धीरे-धीरे खत्म भी हो गईं। साल 2000 से अब तक बिहार में जिन पार्टियों का गठन हुआ है, उनमें लोजपा, राजद (लोकतांत्रिक), राष्ट्रीय समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हम (सेक्युलर), जन अधिकार पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, प्लुरल्स पार्टी, राष्ट्रीय शोसित समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नाम प्रमुख हैं। राजद (लोकतांत्रिक) लोजपा, हम (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता केंद्र में मंत्री बनने में कामयाब रहे। बाकी पार्टी न तो बिहार और न ही केंद्र में कमाल कर पाईं। इन 24 साल में जहां 10 पार्टियां गठित हुईं, वहीं उनमें से 4 पार्टियां ऐसी भी रहीं, जो खत्म हो गईं। जिन पार्टियों का आस्तित्व खत्म हो गया, उनमें राजद (लोकतांत्रिक), जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नाम शामिल हैं। इन आंकड़ों को अगर आधार माना जाए तो बिहार में नई पार्टियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो प्रशांत किशोर के पक्ष में नहीं है।

प्रशांत किशोर की छवि भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 10 साल में प्रशांत किशोर 8 पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। 2011 से 2014 तक उन्होंने भाजपा के साथ काम किया। इसके बाद वे कुछ सालों के लिए जेडीयू के साथ जुड़ गए। पीके इसके बाद कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उन्होंने उप्र और पंजाब में कांग्रेस के लिए काम भी किया। पीके 2019 में शिवसेना (उद्धव) और जगनमोहन की पार्टी के लिए रणनीति बनाते नजर आए। 2020 में वे अरविंद केजरीवाल के साथ आ गए। 2021 में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम करते नजर आए। इसी साल उन्होंने एमके स्टालिन के लिए भी रणनीति बनाने का काम किया। 2021 में प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति से खुद को अलग कर लिया। प्रशांत 2022 में कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में आए। उस वक्त उनके कांग्रेस में जाने की भी खबर थी, लेकिन आखिरी वक्त पर पीके की जॉइनिंग टल गई। पीके इसके बाद बिहार आ गए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा पीके की इसी छवि को मुद्दा बना रहे हैं। मनीष वर्मा के मुताबिक पीके की कोई विचारधारा नहीं है।

जन सुराज पार्टी का ऐलान करने के साथ प्रशांत किशोर बिहार चुनाव को पूरी ट्रिपल-एस के मुद्दे पर लड़ने का प्लान बनाया है। ट्रिपल-एस यानी शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में शराब बंदी का फैसला किया था। इसके बाद बिहार में घर-घर बिजली के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और अब बिहार में जमीनों का सर्वे का आदेश दिया गया। शराबबंदी से लेकर सर्वे और स्मार्ट मीटर तक का मुद्दा अब नीतीश सरकार के गले की फांस बन गया है। प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि शराबबंदी को तो उनकी सरकार आते ही समाप्त कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर को लेकर आरजेडी ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है और अब प्रशांत किशोर भी इसे लेकर अपनी सियासी बिसात बिछाना चाहते हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे बिहार के गांव-गांव और घर-घर के मुद्दे बन रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए सियासी टेंशन बन गए हैं। इस सेंटिमेंट को प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की रणनीति बना रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने दो साल पहले बिहार में जबसे अपनी यात्रा शुरू की थी, वो तबसे शिक्षा की ही बात करते रहे हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। राज्य की 20 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। पीके यह जानते हैं कि बदलाव का एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। इसी आधार पर उन्होंने शिक्षा को जन सुराज के कोर एजेंडे में रखा है। इसके लिए वो शराबबंदी को खत्म करने का भी वादा कर रहे हैं।

● **विनोद बक्सरी**

जमीन सर्वे को विपक्ष ने बनाया हथियार

नीतीश सरकार ने ही बिहार में जमीन सर्वे कराने का फैसला किया। इसी साल 20 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी। आजादी के बाद पहली बार बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। कई पीढ़ियां इस बीच गुजर चुकी हैं, लेकिन बाढ़ और अन्य कारणों से अधिकतर लोगों के पास खतियान ही नहीं है। जमीन के कागजात को सरकार ने कम्प्यूटरीकृत कराए हैं, उनमें कई तरह की खामियां मिल रही हैं। यह काम जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने रोक कर तीन महीने की मोहलत तो दे दी है, लेकिन लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बिहार में कहीं कैथी लिपि में खतियान है तो कहीं परिमार्जन और अद्यतन मालगुजारी की रसीद पाने के लिए लोग कर्मचारी के पास दौड़ रहे हैं। इस तरह लोगों के पास जमीन कब्जे में तो है, लेकिन उसकी सही माप लोगों के पास नहीं है। इसलिए सरकारी अमीन और लेखपाल के पास लोग भाग रहे हैं। जमीन सर्वे के चलते बिहार के लोग जो बाहर रहे हैं, वो प्रदेश में लौटे हैं। प्रशांत किशोर ने अब बिहार में होने वाले जमीन सर्वे को पूरी तरह से मुद्दा बनाने के संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर इस बात को बताने में लगे हैं कि नीतीश कुमार जनता का ध्यान भटकाने के लिए सर्वे कानून को लाए हैं। उन्होंने कहा कि जबसे जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है, तब से बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

महाशक्तियों के खेल में बांग्लादेश

बांग्लादेश की फौज के मुखिया जनरल वकारुज्जमां ने 5 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा था, अब सेना देश में एक अंतरिम सरकार का गठन करेगी। इस संदर्भ में उन्होंने कार्यवाहक सरकार बनाने में राष्ट्रपति से परामर्श लेने की अपनी योजना का ऐलान किया था। इसके तीन दिन के भीतर 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस ने देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की शपथ ले ली।

पिछले महीने बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटे पर जो प्रदर्शन शुरू हुए थे, वे बहुत तेजी से एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गए। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दें। इस सिलसिले में हुई हिंसा में अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस हिंसा की सबसे ज्यादा मार हिंदू आबादी पर पड़ी है, जिसकी संख्या 8 प्रतिशत तक सिमट कर रह गई है। पहले भी बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल के शिकार अल्पसंख्यक हिंदू होते रहे हैं। जानमाल के नुकसान के अलावा जो सबसे चौंकाने वाला दृश्य देखने में आया, वह शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा के ऊपर चढ़े प्रदर्शनकारियों का था। बांग्लादेश की मुक्ति के नायक की प्रतिमा पर वे हथौड़े चला रहे थे। यह इत्तेफाक नहीं है कि शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या बांग्लादेशी फौज के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने 15 अगस्त, 1975 में की थी। उनके ज्यादातर परिवार का सफाया कर दिया गया था, सिवाय दो बेटियों के, जिनमें एक शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के 1971 में मुक्ति होने तक करीब तीस लाख लोग फौजी दमन में मारे गए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याहया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत बंगालियों के राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचला था। पाकिस्तान की सरकार के खास निशाने पर शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग और हिंदू थे। इस नीति के तहत जनता का इस्लामीकरण किया जाना था। मारे गए हिंदुओं की संख्या 12 लाख से 24 लाख के बीच थी। शर्मिला बोस अपनी पुस्तक अनालिसिस ऑफ सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971 में लिखती हैं कि सरकार, फौज और बहुसंख्य आबादी के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत समर्थक और गद्दार के रूप में देखा जाता था। इसलिए गृहयुद्ध के दौरान वे खासतौर से बहुत नाजुक स्थिति में थे।

पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में चले नस्ली सफाये में 15 लाख से ज्यादा मकानों को नष्ट किया गया, तीन करोड़ लोग देश के भीतर ही विस्थापित हो गए और एक करोड़ भाग कर भारत चले आए। भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की आमद इतनी ज्यादा रही कि जून 1971 तक सरहद पर बनाए गए 509 शरणार्थी शिविर भी कम पड़ने लगे थे। इस वजह से देश के आठ राज्यों में भारतीय सेना को बड़े-बड़े शिविर लगाने पड़े, जिनका संचालन पूर्व सैनिकों के जिम्मे था। अगस्त 1971 में पाकिस्तान ने शरणार्थियों की एक जिलेवार सूची भारत को सौंपी। इसमें पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर भागे लोगों की केवल एक-चौथाई संख्या दर्ज थी। ज्यादातर विश्लेषकों के मुताबिक उस सूची में केवल मुसलमान शरणार्थी दर्ज थे, जिसका सीधा मतलब निकलता था कि हिंदू शरणार्थियों को अब वापस जाने की अनुमति नहीं होगी।

भूराजनीति के बड़े फलक पर देखें, तो उस वक्त जो कुछ हुआ उसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों का खेल था। दरअसल, 1969 तक पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका के लिए पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित कर दिया था। उसने चीन के साथ संवाद के गोपनीय चैनल अमेरिका को मुहैया करवाए थे। निक्सन-किसिंजर के नेतृत्व वाली अमेरिकी सत्ता मानती थी कि चीन और रूस के बीच के तनाव का दोहन अमेरिकी हित में किया जा सकता है। चीन के आकार और बढ़ती अहमियत के मद्देनजर अमेरिका उसके साथ संबंध कायम करके तीसरी दुनिया में रूस की संलग्नता को साधने की कोशिश में था ताकि वियतनाम से उसकी इज्जतदार वापसी हो सके। इसी चक्कर में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ा। इसके दो तात्कालिक प्रभाव हुए थे। पहला, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पिछली जॉनसन सरकार में अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति के संबंध में पाकिस्तान के ऊपर लगाए प्रतिबंध की समीक्षा करने का आदेश दे दिया, तो दूसरा आदेश यह दिया कि याहया खान पर ज्यादा दबाव न डाला जाए। अमेरिका का यह सोचना था कि अगर कोई संकट पैदा हुआ, तो वह पाकिस्तान के कुकृत्य से मुंह फेर लेगा। अमेरिकी रणनीति का लाभ उसे यह मिला कि पाकिस्तान की मार्फत हेनरी किसिंजर की चीन यात्रा जुलाई 1971 में हुई, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ उसके टकराव की सूरत में वह दखल नहीं देगा, भले ही चीन ऐसा करता हो।

● **टीपी सिंह**

चीन का बढ़ रहा हस्तक्षेप

चीन ने अपने तईं सतर्कतापूर्ण नीति अपनाई। उसकी नजर कई चीजों पर एक साथ थी। पहला, पाकिस्तान का टूटना चीन के फायदे वाली बात नहीं थी क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान मुक्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से भारत की ओर झुकेगा। दूसरा, चीन को अपना समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के ऊपर अपना प्रभाव भी कायम रखना था। इन दलों ने दिसंबर 1970 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और अब बंगालियों पर पाकिस्तानी फौज के दमन की सूरत में उनका बचा-खुचा प्रभाव भी मिट जाना था। पाकिस्तानी फौज के रास्ते से चीन की सहमति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को सहयोग जारी रखना उसकी जरूरत थी। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ रहे थे। 1963 में पाकिस्तान ने रणनीतिक रूप से अहम लद्दाख की शक्सगाम घाटी की 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन कथित रूप से चीन को सौंप दी थी। जॉनसन सरकार में पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान की निर्भरता सैन्य-आर्थिक मामलों में चीन पर बढ़ गई थी। वह रूस के साथ भी संभावनाएं तलाश रहा था।

शांति के आसार नहीं

गाजा पट्टी के रास्ते इजरायल में घुसकर हमास के लड़ाकों का कत्लेआम मचाना, 1200 लोगों की हत्या करना और करीब 250 लोगों को बंधक बनाने की घटना को एक साल हो गया है। ये सब पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। जवाब में इजरायल ने जंग का ऐलान कर दिया और कसम खाई की जब तक हमास का खात्मा नहीं होता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इजरायल और हमास की इस जंग में अब तक 42 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजरायल का दावा है कि इस जंग में उसने हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराया है। उसने गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने का दावा भी किया है। इस एक साल में जंग सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रही। बल्कि ईरान, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया तक भी इसकी आग पहुंची। लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ कई हफ्तों से इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरान और इजरायल के बीच भी तनाव चरम पर है। ईरान की तरफ से इस साल दो बार इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया गया है।

इजरायली सेना ने बताया कि एक साल में गाजा पट्टी में हमास के 40 हजार से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। वहीं, हमास की 4,700 सुरंगों और 1,000 रॉकेट लॉन्चर साइट को तबाह कर दिया गया। जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजरायल पर गाजा से 13,200 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा के अलावा 12,400 रॉकेट लेबनान से, 400 ईरान से, 180 यमन से और 60 रॉकेट सीरिया से दागे गए हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में एक साल में गाजा पट्टी में 42,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमास के लड़ाकों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर 1,200 नागरिकों की हत्या कर दी थी। 250 लोगों को बंधक भी बना लिया था। अब भी 100 से ज्यादा बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान में 800 से ज्यादा आतंकियों को मारा जा चुका है। लेबनान में 6 हजार से ज्यादा जमीनी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। एक साल में इजरायल ने वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी से 5 हजार से ज्यादा संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। इजरायली सेना ने बताया कि इस जंग में अब तक 726 सैनिकों की मौत हुई है। 380 सैनिक 7 अक्टूबर को मारे गए थे, जबकि उसके बाद 346 सैनिकों की मौत गाजा में लड़ते हुए हो गई। इनके अलावा 4,756 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। दुर्घटनाओं में घायल 56 सैनिकों की मौत भी हुई है। इजरायल ने बताया कि एक साल में 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया गया है। इनमें 82 प्रतिशत पुरुष और 18 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 20 से 29 साल है।

गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का शासन है और 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद इजरायल की बदले की कार्रवाई में यहां बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। गाजा में बुनियादी ढांचे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी, गाजा युद्ध अनसुलझा है और पूरे क्षेत्र में युद्ध की संभावना अधिक बनती जा रही है। अपने कई शीर्ष नेताओं और कमांडरों के मारे जाने से हमास सक्रिय है। कतर स्थित हमास के सदस्य खलील अल-हया ने एक वीडियो संदेश जारी करके 7 अक्टूबर, 2023 के हमले को महान कार्य बताया है। अल-हया ने 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर जारी अपने संदेश में कहा, पूरा फिलिस्तीन, विशेष रूप से गाजा और हमारे फिलिस्तीनी नागरिक दुश्मन के खिलाफ अपने प्रतिरोध के साथ एक नया इतिहास लिख रहे हैं। हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2024 को किए गए हमले की पहली बरसी आने तक इजरायल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। अब उसका फोकस गाजा से लेबनान में शिफ्ट हो गया है। लेबनान के अलग-अलग हिस्सों में हिज्बुल्लाह को निशाना बनाते हुए इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई और वायुसेना के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली कार्रवाई शुरू होने के बाद से अब तक लेबनान में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें आधे से ज्यादा हिज्बुल्लाह के लड़ाके हैं। बेरूत में जमीनी कार्रवाई के दौरान हिज्बुल्लाह के साथ सीधी मुठभेड़ में इजरायल के भी कुछ सैनिक शहीद हुए हैं। पिछले 1 साल में 45000 से अधिक मौतों के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि क्षेत्र में हिंसा का यह दौर कभी खत्म होने वाला है।

इजरायली रक्षा बलों ने 5 अक्टूबर, 2024 को गाजा शहर के बगल में स्थित जबालिया में हमास लड़ाकों को खत्म करने के इरादे से एक और अभियान शुरू किया। इजरायल ने कहा कि हमास जबालिया में फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। यह संभव है कि इजरायल के खिलाफ उसके दुश्मनों द्वारा एक और आतंकवादी हमला या सैन्य अभियान इलाके में संघर्ष की स्थिति को और भी भयावह बना सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमले के दौरान जिन 250 लोगों को बंधक बनाया था, उनमें से 101 बंधकों का अब भी पता नहीं चल सका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में इन बंधकों का जिक्र किया था। उन्होंने यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि इजरायल आखिरी बंधक का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। गाजा में इजरायल का उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमताओं और शासन को नष्ट करना और बंधकों को छुड़ाना है।

● **कुमार विनोद**

अपने युद्ध को अंजाम तक पहुंचा पाएगा इजरायल?

लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे इजरायल का लक्ष्य अपने उन 60,000 से अधिक नागरिकों को सीमा के पास अपने घरों में लौटने के लिए सुरक्षित महसूस कराना है, जिन्हें हिज्बुल्लाह के रॉकेट हमलों की जद में आने का डर सताता है। पिछले एक साल में इजरायल अपने दुश्मनों पर नकेल कसने में कामयाब रहा है, लेकिन अपने युद्धों को अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं रहा है। इजरायली सैन्य अधिकारी भी यह स्वीकार करते हैं कि हमास और हिज्बुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने और उनकी सैन्य क्षमताओं को कुंद करने के बावजूद, ये दोनों मिलिशिया समूह फिलिस्तीन और लेबनान में एक ताकत बने रहेंगे। इस संघर्ष में ईरान की एंट्री से स्थिति और बिगड़ सकती है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यही समझ में आता है कि इजरायल को निकट भविष्य में भी युद्धों और संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा।

संसद में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी कब...?

भले ही देश-दुनिया में महिलाओं की समानता को लेकर कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हों लेकिन सच यही है कि अभी भी महिलाएं, पुरुषों के बराबर दर्जा पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इसकी एक झलक सत्ता के गलियारों में भी देखी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि संसद में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी किसी सपने से कम नहीं। यदि मौजूदा रफ्तार से देखें तो इस सपने को 2063 तक साकार करना संभव नहीं होगा।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए काम कर रहे संगठन यूएन वीमेन और यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता की खाई अभी भी बहुत गहरी है, जिसे भरना आसान नहीं है। प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स: द जेंडर स्नेपशॉट 2024 नामक इस रिपोर्ट में बाल विवाह को भी लेकर चिंताजनक खुलासा किया है, जिसके मुताबिक बाल विवाह की कुप्रथा को दुनिया से दूर करने में सात दशकों से अधिक का समय बीत जाएगा। गौरतलब है कि आज भी हर पांच में से एक बच्ची का विवाह बालिग होने से पहले हो रहा है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि दुनिया लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति कर रही है। अब, संसद में हर चार सीटों में से एक पर महिला सांसद काबिज है, जो 10 साल पहले की तुलना में बड़े सुधार का इशारा है।

इसी तरह आज 10 फीसदी से भी कम महिलाएं और बच्चियां बेहद गरीबी के भंवर जाल में फंसी हुई हैं, जो कि कोरोना महामारी के बाद एक बड़ा सुधार है। गौरतलब है कि महामारी के दौर में यह खाई कहीं ज्यादा गहरा गई थी। वहीं पहली जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट के बाद से, पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को भरने के लिए दुनियाभर में 56 नए कानून पारित किए गए हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा हासिल करने में अभी भी लंबा सफर तय करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस दिशा में प्रगति तो हुई है, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। ऐसे में इन हालातों में महिलाओं और बच्चियों को गरीबी के गर्त से बाहर निकालने के लिए अभी 137 वर्षों का इंतजार करना होगा। वहीं बाल विवाह के उन्मूलन में 70 वर्षों से अधिक का समय बीत जाएगा। रिपोर्ट में जो आंकड़े साझा किए गए हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि लैंगिक समानता हासिल करने के लिए निर्धारित सतत् विकास के इस पांचवे लक्ष्य और उससे जुड़े सभी संकेतक फिलहाल पहुंच से काफी दूर हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब वैश्विक नेता, 22 से 23 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में भविष्य को ध्यान में रखकर होने वाली शिखर बैठक में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनसे आग्रह किया गया है कि इस खाई को भरने और लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की दरकार है। ताकि महिला हो या पुरुष सभी को समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिल सके। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति को मूर्त रूप देना आवश्यक है। भले ही यह लक्ष्य दूर की कौड़ी नजर आता है, लेकिन इसे आपसी सहयोग से हासिल किया जा सकता है। अपनी इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सिफारिशों का पुलिंदा भी प्रस्तुत किया है।

यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा है हम इस दिशा में प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। उनके मुताबिक यह रिपोर्ट एक ऐसा सच बताती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि, हमें लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा, जैसा कि वैश्विक नेताओं ने करीब तीन दशक पहले बीजिंग में महिला सम्मेलन और 2030 के लिए जारी एजेंडा में वादा किया था। इसके मद्देनजर, उन्होंने महिलाओं व बच्चियों के समक्ष मौजूद सभी बाधाओं को दूर करने की अपील की है, और लैंगिक समानता को आकांक्षा से वास्तविकता में तब्दील करने का आव्हान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया है कि महिलाओं और बच्चियों के विरूद्ध होते भेदभाव का अंत करना होगा। साथ ही उनके बेहतर भविष्य के लिए निवेश किया जाना होगा ताकि सतत् विकास के 2030 के एजेंडे को साकार किया जा सके। यदि भारत की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और यूएन वीमेन ने अपनी रिपोर्ट द पाथ्स टू इक्वल में भारत को महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के मामले में पिछड़े देशों की लिस्ट में शामिल किया है।

● **ज्योत्सना**

असमानता की चुकानी पड़ रही भारी कीमत

रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि हम लैंगिक असमानता की एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उदाहरण के लिए, जो देश अपने युवाओं को उचित शिक्षा देने में विफल रहे हैं, वो हर साल 10,00,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खो रहे हैं। वहीं निम्न और मध्यम आय वाले देश, यदि पुरुषों और महिलाओं के बीच डिजिटल माध्यमों तक पहुंच के बीच के अंतर को भरने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ली जुन्हुआ का कहना है, लैंगिक समानता पर काम न करने की कीमत बहुत भारी है, और इसे प्राप्त करने के लाभ इतने अधिक हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम अपने 2030 के लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब महिलाओं और बच्चियों को समाज के हर हिस्से में पूरी तरह शामिल किया जाए। रिपोर्ट में सतत् विकास के सभी 17 क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को समाप्त करने की सिफारिशें की गई हैं। इसमें कानूनी सुधार भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए जिन देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी प्रावधान हैं, वहां अंतरंग साथी द्वारा हिंसा को अंजाम देने की दर कम है। जिन देशों में इसके लिए कानून हैं वहां यह दर साढ़े 9 फीसदी है, जबकि जिन देशों में ऐसे कानून नहीं है वहां यह दर 16.1 फीसदी है।

अपनी-अपनी दीपावली

दीपावली, हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पड़ता है। दीपावली संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्तियां। दीपावली, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म के लोग, इस दिन धन और समृद्धि की देवी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली का त्योहार, सिख और जैन धर्म के लोग भी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं! आइए, इनमें से कुछ के बारे में जानें।

दीपावली, हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पड़ता है। दीपावली संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है दीपों की पंक्तियां। दीपावली, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म के लोग, इस दिन धन और समृद्धि की देवी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली का त्योहार, सिख और जैन धर्म के लोग भी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं! आइए, इनमें से कुछ के बारे में जानें।

रामायण में दीपावली का उल्लेख- दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा, हिंदू महाकाव्य रामायण में है। रामायण के हिसाब से, दीपावली के दिन भगवान राम, सीता, और लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद, अयोध्या लौटे थे। भगवान राम को उनके पिता, राजा दशरथ ने वनवास पर जाने का आदेश दिया था। वनवास के दौरान, भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, और भाई लक्ष्मण ने तमाम कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान, राक्षसों के शक्तिशाली राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। दिव्य पक्षी जटायु ने बहुत बहादुरी से रावण का सामना किया। हालांकि, रावण ने बेरहमी से उसके पंख काट दिए। रावण, सीताजी को अपने साम्राज्य लंका में ले गया, जो समुद्र के दूसरी तरफ बसा था।

भगवान राम ने अपने भरोसेमंद सेनापति हनुमान और वानरों के राजा सुग्रीव की मदद से, लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाया। पत्थरों को पानी पर तैरते रहने का वरदान दिया गया था। अच्छाई और बुराई की लड़ाई में, भगवान राम ने रावण का वध करके, सीता को छुड़ा लिया। इस जीत के बाद, वे अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में, अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में साफ-सफाई की और रोशनी के लिए, उनके रास्ते में दीप जलाए। तब से लेकर आज तक, दीप जलाने की परंपरा, दीपावली के उत्सव का अहम हिस्सा है।

महाभारत में दीपावली- दीपावली से जुड़ी अन्य कथाओं में से, वनवास की एक और कहानी भी काफी प्रचलित है। पांडवों से जुड़ी इस कहानी का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में मिलता है। कपट भरे चौसर के खेल में, पांडव अपनी सारी संपत्ति धूर्त कौरवों से हार जाते हैं। कई सालों तक अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद, पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ, कार्तिक महीने की अमावस्या को अपने राज्य वापस आए थे। प्रजा उनकी वापसी पर बहुत खुश हुई और उनके स्वागत के लिए ढेरों दीप जलाए।

जैन धर्म में दीपावली- दीपावली, जैन धर्म के लोगों के लिए एक अहम त्योहार है। इसे, 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण या आध्यात्मिक जागृति के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्मग्रंथों में दीपावली को दीपलिकया कहा गया है, जिसका मतलब है शरीर से निकलने वाली रोशनी। भगवान महावीर की आध्यात्मिक जागृति के सम्मान में, हर जगह दीपों की सजावट की जाती है।

सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस- दीपावली का दिन सिख धर्म के लोगों के बीच काफी अहमियत रखता है। इस दिन सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब और 52 अन्य कैदियों को रिहा किया गया था। इसलिए, वे लोग इसे बंदी छोड़ दिवस (आजादी का दिन) के रूप में मनाते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक, बादशाह जहांगीर ने कई सालों की कैद के बाद, गुरु हरगोबिंद साहिब को रिहा किया था। हालांकि, गुरु ने कहा कि वह तब तक नहीं जाएंगे, जब तक उनके साथ कैद 52 अन्य राजकुमारों को भी रिहा नहीं किया जाता। बादशाह ने कहा कि निकलते समय जो लोग गुरु के लबादे को पकड़े रहेंगे, सिर्फ उन्हें रिहा किया जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहिब ने 52 झालरों वाला लबादा बनवाया, ताकि हर एक राजकुमार एक-एक झालर पकड़कर, उनके साथ जेल से बाहर आ सके। गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया। यह परंपरा तब से आज तक चली आ रही है।

दीपावली पांच दिनों का त्योहार है! दीपावली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ पांच दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार से जुड़े कई मिथक और कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली के त्योहार पर लोग अपने दोस्तों और परिवारों से मिलते हैं। वे उपहार और मिठाइयां लेकर एक-दूसरे के घर जाते हैं। पांच दिनों तक चलने वाले दीपावली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। कई दिनों तक साफ-सफाई के बाद, लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आने वाले साल के लिए, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरे दिन को तमिलनाडु, गोवा, और कर्नाटक में नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन त्योहार का मुख्य दिन होता है, जो कि चंद्र मास के कृ ष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। दीपावली के दिन पकवान बनाए जाते हैं, घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग-बिरंगी रंगोली बनाई जाती है, और दरवाजों को तोरण से सजाया जाता है। रात को मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं, जो इसे सही मायनों में रोशनी का त्योहार बनाता है। दीपावली के अगले दिन को उत्तर, पश्चिम, और मध्य क्षेत्रों के कुछ समुदाय गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। उत्सव का अंतिम दिन भाई दूज (भाई के दिन) के रूप में मनाया जाता है। इसे भाऊ बीज, भाई तिलक या भाई फोंटा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। वहीं, भाई उसे उपहार देकर अपना प्यार जताता है।

● **ओम**

श्राद्ध

महेश के पापा का आज श्राद्ध है। उसके बच्चे भी अपने माता पिता के साथ काम करवा रहे है, क्योंकि महेश की पत्नी राधा की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह नहा-धोकर सबने उनकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़े, फिर महेश ने तर्पण किया। राधा ने अपने ससुर की पसंद का खाना श्रद्धा से बनाया। फिर महेश ने गाय, कौवे को खीर खिलाई है। थोड़ी देर बाद पंडितजी भी आ गए। उनको महेश ने आदरपूर्वक भोजन कराया और यथाशक्ति उपहार भी दिया। उनके जाने के बाद बच्चे महेश से पूछने लगे कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं। महेश ने कहा- बच्चों, जो हमारे पूर्वज होते हैं। वो इस महीने में पहंद्र दिन के लिए धरती पर आते हैं। वो हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं उनकी जिस तिथि को मृत्यु होती है। उस दिन हम तर्पण करके उनकी पसंद का भोजन बनाकर उनके रूप में पंडितजी को खिलाते हैं। जिससे उनकी आत्मा तृप्त होती है वह हमें बहुत सारा आशीष देते हैं। बच्चों को यह समझाते हुए अपने महेश को माता-पिता की याद आ गई।

- पूनम गुप्ता

कोई बात नहीं

भूषण खाना खाकर उठा। सोफे पर बैठकर मोजे को पहनने के लिए झाड़ने लगा। सुखिया समझ गई कि आज उसे ड्यूटी जाने में देर हो गई। बोली- बारिश का मौसम है। बदली छा रही है। पता नहीं बेटा, कब और पानी गिर जाएगा। भूषण ने एक थैले में कुछ रखा और चलने लगा।

रूको बेटा, इसे पहन लो, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। शायद तुझे सर्दी भी तो है। कहते हुए सुखिया ने बाइक की डिक्की में रेनकोट डाल दिया। भूषण के चलने की आहट प्रतिभा के कानों पर पड़ी। झट से कमरे से बाहर आई- अजी! अपना लंच बॉक्स तो रख लो। बड़े भुलक्कड़ हो गए हो आजकल। कहते हुए तिरछी नजरों से मुस्कुरा दी। बाइक स्टार्ट करते भूषण पर सौम्या की नजर पड़ी। दौड़ कर आई। मुस्कुराई... पापा जी, हेलमेट तो पहन लीजिए। आराम से जाइएगा, है ना। एक विशेष संरक्षण तले भूषण घर से निकला। शाम होते ही घर में भूषण का इंतजार होने लगा। बारिश बंद हो चुकी थी। आसमान भी साफ था। रात हो रही थी। सबको चिंता सताने लगी थी। तीनों दरवाजे से झांक ही रहे थे कि एक बाइक आकर रुकी। भूषण था। घर में दाखिल हुआ। टेबल पर खाली लंच बॉक्स और सामानवाला थैला रखा। पैर से जूते सरकाते हुए कहने लगा- मां, आपके चश्मे की डंडी नहीं लगवा पाया। दरअसल मैं जल्दी में था, भूल गया और हां, प्रतिभा तुमने अपने कमर दर्द के लिए मूव्ह मंगवाया था ना... क्या हुआ कि लौटते समय मेरी बाइक स्पीड थी। मेडिकल स्टोर्स को कितने समय क्रॉस किया, मैं समझ नहीं पाया। प्रतिभा ने किचन से सुन लिया। होमवर्क करती सौम्या को सुनाई दिया- सौम्या बेटी, तेरी प्रोजेक्ट फाइल नहीं ला पाया। कल ले आऊंगा। तभी अपनत्व भरा क्षम्य की ध्वनि तरंगे भूषण के कानों को स्पर्श करने लगी- कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया न बस... छोड़ो न जी... कोई बात नहीं, कल ले आना मूव्ह को। ठीक है पापा जी, कोई बात नहीं, मैं स्कूल जाते समय खरीद लूंगी अपनी प्रोजेक्ट फाइल।

- टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला'

राह तुम्हारी तकते-तकते

राह तुम्हारी तकते-तकते,
जाने कितने मौसम बीते!
आंखों में हमने बोये थे,
साथ-साथ रहने के सपने।
किंतु तरुण मन कैसे जाने,
सपने कभी न होते अपने।।
इन सूनी-सूनी आंखों ने,
हारे मिलन, जुदाई जीते।
यादों के मेले में हम-तुम,
जाने कितने रहे अकेले।
विरही पाट नदी के हैं हम,
निर्मम धारा हमसे खेले।।
नाजुक दिल के खंड-खंड को,
बीत रहा युग सीते-सीते।
दुधिया केशों के झुरमुट से,
देख रहा हूं आंखें मीचे।
शायद आ पाओ तुम मिलने,
डोर सांस की खींचे-खीचे।।
जीवन की अंतिम बेला भी,
गुजर रही गम पीते-पीते।

- डॉ. अवधेश कुमार अवध

आईपीएल के नए नियमों ने उड़ाई नींद

इंडियन प्रीमियर लीग के अठारहवें संस्करण की नीलामी अगले महीने नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले इसके कई नियमों में बदलाव किया गया है जिनसे विदेशी खिलाड़ियों को नुकसान तो अनकैप्ड खिलाड़ियों को फायदा पहुंचता नजर आ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं राइट टु मैच कार्ड में क्या बदलाव हुआ? खिलाड़ियों को रिटेन करने पर कितना खर्च होगा? विदेशी के लिए नए नियम क्या हैं? बाहरी खिलाड़ियों को नुकसान कैसे हुआ? अनकैप्ड के लिए क्या नियम हैं? सबसे पहले समझते है आईपीएल का रिटेंशन रूल क्या है?

रिटेंशन रूल के तहत आईपीएल नीलामी से पहले अब फ्रेंचाइजी टीमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। जिनमें ज्यादा से ज्यादा 5 अंतरराष्ट्रीय और 2 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी भारत का ही होना चाहिए। मान लीजिए दिल्ली कैपिटल ने 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटेन किए तो टीम अब किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को ही छठे खिलाड़ी के रूप में रिटेन कर सकेगी। वहीं टीम ने अगर 4 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रिटेन किए तो उनके पास 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प रहेगा। वहीं नीलामी में राइट टु मैच की भी वापसी हुई है। टीमें चाहें तो 6 खिलाड़ी नीलामी से पहले रिटेन कर लें या फिर राइट टु मैच कार्ड का इस्तेमाल कर लें। टीमों ने अगर 3 खिलाड़ी रिटेन किए तो उनके पास ऑक्शन में 3 राइट टु मैच कार्ड ही बचेंगे। इसी तरह अगर 4 प्लेयर रिटेन किए तो ऑक्शन में 2 राइट टु मैच कार्ड बचेंगे।

राइट टु मैच कार्ड टीमों को नीलामी में मिलता है। मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 प्लेयर रिटेन किए और उनके पास एक राइट टु मैच कार्ड बचा है। टीम किसी खिलाड़ी को रिटेन नहीं कर सकी। अब अगर ऑक्शन में हैदराबाद ने उस खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देकर खरीदा तो चेन्नई अपने राइट टु मैच कार्ड का इस्तेमाल कर उसे अपनी टीम में ही रख सकती है। राइट टु मैच में इस बार एक नया नियम जोड़ा गया है। इस नियम के तहत बोली लगाने वाली टीमों के पास खिलाड़ी की कीमत बढ़ाने का मौका रहेगा। जैसे हैदराबाद ने किसी खिलाड़ी की 8 करोड़ की बोली लगाई और दिल्ली ने राइट टु मैच कार्ड यूज किया तो हैदराबाद उस कीमत को बढ़ाकर 9 या 10 करोड़ रुपए तक भी कर सकती है। अगर दिल्ली ने राइट टु मैच कार्ड यूज किया तो उन्हें बढ़ी हुई कीमत में उस खिलाड़ी को खरीदना होगा। तीसरा बदलाव आईपीएल फ्रेंचाइजियों की पर्स लिमिट भी अब बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दी गई है जो पहले 100 करोड़ थी। पहले खिलाड़ी को रिटेन करने पर 18 करोड़, दूसरे खिलाड़ी पर 14 करोड़ और तीसरे खिलाड़ी पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर 3 ही खिलाड़ी रिटेन किए तो पर्स से 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टीमें अगर चौथे खिलाड़ी को रिटेन करती हैं तो उन्हें उसे 18 करोड़ रुपए ही देने होंगे। वहीं पांचवें प्लेयर के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करने के लिए 4-4 करोड़ रुपए ही लगेंगे। प्लेयर रिटेंशन बताने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक है। टीमों ने अगर 5 इंटरनेशनल और एक अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन किया तो उनके पर्स से 79 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। वहीं टीमों ने 4 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए तो पर्स से 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 5 इंटरनेशनल प्लेयर ही रिटेन किए तो पर्स से 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। चौथे नियम के अनुसार विदेशी खिलाड़ियों को अब आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर उन्हें अगले मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। कोई विदेशी प्लेयर अगर ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से हट जाता है तो उन्हें अगले 2 सीजन के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। हालांकि खिलाड़ी अगर चोटिल है तो उन्हें बैन नहीं किया जाएगा लेकिन इसके लिए उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। यही नहीं आईपीएल में पहली बार विदेशी खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम भी 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। या फिर मेगा ऑक्शन में अगर सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिका तो विदेशी प्लेयर्स को मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे।

मान लीजिए, मुंबई इंडियंस ने सूर्यकुमार यादव को रिटेंशन की सबसे बड़ी कीमत 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अब अगर मेगा ऑक्शन में रिंकू सिंह सबसे महंगे रहे, लेकिन उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए ही रही तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हालांकि टीमें विदेशी प्लेयर्स को 20, 25 या 30 करोड़ रुपए की बोली लगाकर भी खरीद सकती हैं। उनके पर्स से उतना ही अमाउंट कटेगा जितने की उन्होंने बोली लगाई, लेकिन खिलाड़ी को 15 या 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम बीसीसीआई के पास जाएगी जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों पर खर्च करेगा।

● आशीष नेमा

क्या कहता है अनकैप्ड प्लेयर नियम

आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर रूल की भी वापसी हुई। यह नियम 2008 से 2021 तक रहा लेकिन किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी वापसी हो रही है। इसके तहत जिस भी भारतीय खिलाड़ी ने 5 साल पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला होगा टीमें उसे अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकेंगी। जैसे, चेन्नई सुपर किंग्स को 5 आईपीएल खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में खेला था जिसे 5 साल बीत चुके हैं। इसलिए चेन्नई उन्हें 4 करोड़ रुपए में ही अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती है। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल की नई रिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत सभी विदेशी खिलाड़ियों को नीलामी में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें बाद में होने वाले मिनी ऑक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं किसी खिलाड़ी ने अगर ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से नाम वापस लिया तो उन्हें अगले 2 सीजन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही विदेशी खिलाड़ी अब एक सीजन में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस भी नहीं पाएंगे। पिछले मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ और पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपए में बिके थे।

बॉलीवुड की वो मर्दाना एक्ट्रेस, सनी देओल संग किया डेब्यू, तलाक के बाद डूबा करियर

80 के दशक की वो टॉप एक्ट्रेस जिन्होंने डेब्यू करते ही साबित कर दिया था कि वह टॉप एक्ट्रेस बनने के लिए इंडस्ट्री में आई हैं। सनी, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे हर एक्टर्स संग भी किया काम। करियर के पीक पर आकर एक्ट्रेस ने स्ट्रगलर एक्टर से शादी रचाई, लेकिन 7 साल बाद ही तलाक के बाद एक्ट्रेस का करियर भी डूब गया।

वो टॉप एक्ट्रेस जिनकी डेब्यू फिल्म ही मीनाक्षी शेषाद्रि और मंदाकिनी को ऑफर की गई थी। लेकिन उन्होंने इस फिल्म से डेब्यू करके मेकर्स के साथ-साथ फैंस का भी दिल जीत लिया। वो टॉप एक्ट्रेस कोई और नहीं अमृता सिंह हैं, जिन्होंने सनी देओल के साथ पहली फिल्म से ही तहलका मचा दिया था। साल 1983 में एक्टिंग की दुनिया में फिल्म बेताब से कदम रखने वाली अमृता सिंह आज फिल्मी दुनिया से दूर हैं। कभी उनकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था। वह दिखने में जितनी खूबसूरत थीं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी वह एक्टिंग किया करती थीं। अपने करियर में उन्होंने खूब नाम कमाया था और अपनी खास पहचान बनाई थी।

पहली फिल्म से ही मचा दिया था तहलका

परिवार के खिलाफ जाकर की शादी... *अमृता सिंह को ऑफर घर बैठे मिला था, उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह एक्ट्रेस बनें। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के चलते उनके घर स्टार्स का आना जाना लगा रहता था। एक बार उनके घर धर्मेंद्र आए और देखते ही उन्होंने एक्ट्रेस को पहली फिल्म ऑफर कर दी। 66 साल दिग्गज अदाकारा अमृता सिंह ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनके पिता शिविंदर सिंह विर्क एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने धर्मेंद्र की बात मानकर अपने खिलाफ जाकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनके करियर में कुछ लोग उन्हें मर्दाना एक्ट्रेस भी कहा करते थे। फिल्म चमेली की शादी में भी उन्हें कास्ट किए जाने पर ये कहा गया था कि किस मर्दाना एक्ट्रेस को साइन कर लिया है। अमृता सिंह का करियर उस वक्त ढलान पर आ गया था, जब उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सैफ अली खान से शादी रचाई। इतना ही नहीं इसके बाद जब दो बच्चों के बाद उनका तलाक हुआ तो उनका करियर डूबता ही चला गया।*

मुझे पता नहीं था विलेन... जब सनी देओल का छलका था दर्द, बताया शाहरुख खान से 16 साल तक क्यों नहीं की बात?

सुपर स्टार शाहरुख खान और सनी देओल बॉलीवुड के दो बड़े नाम हैं। दोनों ने अंतिम बार 1993 में यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म डर में काम किया था। तब से दोनों ने कभी भी एक-दूसरे के साथ काम नहीं किया। दोनों कभी एक साथ सार्वजनिक रूप से भी नजर नहीं आए। 2019 में सनी देओल ने एक अन्य इंटरव्यू में कहा था, लोगों को मेरी फिल्में पसंद हैं। शाहरुख खान की फिल्में भी उन्हें पसंद हैं। डर फिल्म को लेकर मसला सिर्फ इतना है कि मुझे पता नहीं था विलेन को हीरो बनाया जाएगा। मैं दिल से फिल्म में काम करता हूं और लोगों पर भरोसा करता हूं। मुझे भरोसे में रहकर काम करना पसंद है। दुर्भाग्य से, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर हैं जो इस ढंग से काम नहीं करते। हो सकता है कि वो इस तरह से स्टारडम पाना चाहते हैं।

ऐसे दूर हुई अदावत... *सनी देओल और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से अदावत 2023 में तब दूर हुई जब गदर-2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। सन्नी देओल ने सक्सेस पार्टी रखी थी। शाहरुख खान, सलमान खान समेत इंडस्ट्री के कई दिग्गज एक्टर जश्न में शामिल हुए। सनी देओल पार्टी में शाहरुख को गले लगाते नजर आए थे। सनी देओल ने कहा था, हम सभी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि हमने क्या गलत या सही किया। समय सभी जख्मों को भर देता है। मैं बहुत खुश हूं कि हर कोई मेरी पार्टी में आया।*

सिर्फ पॉकेट मनी के लिए चुनी एक्टिंग की राह, डेब्यू फिल्म से रातोंरात बनीं स्टार, अजय देवगन संग कर चुकीं रोमांस

बॉलीवुड में कई हिट दे चुकीं रकुल प्रीत सिंह को भला कौन नहीं जानता, ये एक्ट्रेस अपने फैंस के दिलों पर राज करती हैं। अपनी कमाल की अदाकारी, एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से रकुल काफी फेमस हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने निर्माता और एक्टर जैकी भगनानी से शादी की है। वो करीब 10 साल से हिंदी और साउथ सिनेमा में एक्टिव हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रकुल ने पहली फिल्म महज 18 साल की उम्र में साइन कर ली थी। लेकिन ये उन्होंने फेम के लिए नहीं बल्कि पॉकेट मनी के लिए साइन की थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 18 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज वो अपने हुनर के दम पर सिनेमा जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं।

अक्षय-अजय के साथ कर चुकी हैं काम... *बता दें कि अजय देवगन के साथ फिल्मों में भी वह काम कर चुकी हैं। पर्दे पर रकुल और अजय की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। दोनों ने अब तक साथ में रनवे 34 और दे दे प्यार दे में काम किया है। रकुल ने जाने-माने प्रोड्यूसर जैकी भगनानी से शादी रचाई है। अपने छोटे से करियर में रकुल प्रीत सिंह अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। हालांकि, यहां तक का सफर तय करना उनके लिए आसान नहीं रहा। गौरतलब है कि डेब्यू फिल्म से ही वह रातोंरात स्टार बन गई थीं।*

सियासत में मोटी चमड़ी पाने के अचूक उपाय!

कुर्सी पर टकटकी बांधे एकाएक उन्हें जीवन का लक्ष्य मिल गया। मिलते ही पाने की दिशा में बढ़ने लगे। शुरुआत में किचन के चमचे पर प्यार आया। फिर उनके मुंह से फूल झरने लगे। कुछ आगे बढ़ने पर वे चरणों में लौटने लगे। फिर लड़ाई-झगड़े की दिशा में रुख किया। बीच में वक्त मिलने पर गाली-गलौज की भी प्रचंड प्रैक्टिस करने लगे। इस तरह उनका विकास लगातार जारी है।

चमकती-दमकती-निखरी त्वचा...रूप निखर आएगा गुणकारी हल्दी-चंदन से...दुनिया ग्लोइंग स्किन पाने के लिए मचल रही है। लाख रुपए खर्च कर रही है। कई देशों में डोल रही है। कई तरह के ट्रीटमेंट की मौज ले रही है। और दूसरी तरफ एक प्रजाति ऐसी भी है, जिसे ग्लोइंग-विलोइंग स्किन से कोई मतलब नहीं, उसे तो थिक स्किन चाहिए बोले तो मोटी चमड़ी... तलवार भले ही जिसके आर-पार हो जाए लेकिन किसी बात के आर-पार होने की गुंजाइश ना हो। कोई नैतिक बात आकर टकराए तो प्रचंड रफ्तार से वापस चली जाए। सिद्धांतों की बात आए तो चमड़ी कछुए की खाल बन जाए। परिवारवाद, भाई-भतीजावाद जैसा आरोप सामने आए तो चमड़ी पर वज्र का लेपन हो जाए।

बाबा! ऐसी स्किन चाहिए, जिससे हर आरोप बूमरैंग टाइप टकराकर लौट जाए। एक प्रजाति की आशा, आकांक्षा, उम्मीद वाली मोटी चमड़ी पाने की डेली एक्सरसाइज के बारे में जरा खुलकर बताया जाए...कहानी में गजब ट्विस्ट-टर्न हैं... राज तो क्लाइमेक्स में खुलेगा। तो शुरू करते हैं...।

कुर्सी पर टकटकी बांधे एकाएक उन्हें जीवन का लक्ष्य मिल गया। मिलते ही पाने की दिशा में बढ़ने लगे। शुरुआत में किचन के चमचे पर प्यार आया। फिर उनके मुंह से फूल झरने लगे। कुछ आगे बढ़ने पर वे चरणों में लौटने लगे। फिर लड़ाई-झगड़े की दिशा में रुख किया। बीच में वक्त मिलने पर गाली-गलौज की भी प्रचंड प्रैक्टिस करने लगे। इस तरह उनका विकास लगातार जारी है। उनका विकसित होते जाने में भारी भरोसा है। वे बचपन से ही विकास पुरुष हैं।

उनका मानना है कि कठिन परिश्रम से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। उनका व्यक्तित्व प्रतिदिन निखरता चला जा रहा है। लोग उनके आने-जाने अर्थात् दोनों ही क्रम के पश्चात उनको भला-बुरा कहते हैं। ऐसे किसी भी तथ्य की जानकारी मिलने पर वे प्रसन्न होते हैं। मान के चलते हैं कि यदि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, तो क्षणभंगुर जीवन में आपकी कोई पहचान नहीं है। धन्य है ऐसी फिलॉसफी और चिंतक!

नारी कल्याण और ओछापन करने में वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव करने पर कइयों को बख्शना पड़ता है। यूं ही सब बख्शे जाएंगे तो वे लक्ष्य की दिशा में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। यानी लक्ष्य की दिशा में जाने के लिए वे हर तरह के भेदभाव से बचते हैं। उनका पूरा भरोसा है कि हर तरह के गिरे हुए को ऊंचा उठाना चाहिए। वे हर गिरे काम को ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं। बल्कि उन्हें आदर्श के स्तर पर प्रतिष्ठित करने में लगे हैं। वे निजी तौर पर भी ऊंचा उठना चाहते हैं। कितना ऊंचा? इस बारे में ठीक-ठीक नहीं बता पाते हैं। जोर देकर पूछने पर बताते हैं कि इतना चालू आदमी तो भाई साब आज तक नहीं देखा, के आसपास का मामला बैठना ही चाहिए।

वे व्यक्तित्व में कई खूबियां जोड़ना चाहते हैं। जोड़ भी रहे हैं। एक बीड़ी, 100 ग्राम मूंगफली में दिन गुजार सकते हैं। धरती पर लेटकर धूलभरा फर्श ओढ़ सकते हैं। किसी से झूमा-झटकी करने से पीटने की रफ्तार पकड़ने में कुल साढ़े छह मिनट का समय लगाते हैं। जूते से घातक चोट जबान से पहुंचाने के एक्सपर्ट हो चुके हैं। चांटे मारने की जगह चरित्र पर थूकने लगे हैं। सामने वाला खुद से ज्यादा चरित्रवान हो तो झट से चाटने का अभ्यास भी साध रखा है। झुककर और मौका पड़ने पर लेटकर भी पैर छू सकते हैं। हाइकमान की तरफ से आते हर विचार को पकड़ने के लिए पूरी बॉडी ट्यून कर चुके हैं।

किसी भी दिशा और हवा से नोट पैदा किए जाने का जादू सीख चुके हैं। जितना मिले उसका अधिकतम हिस्सा हड़पने का प्रबंधन आ चुका। ऐसी लौ लगाई है कि छल-फरेब-धूर्तता करने में अपने-पराए का अंतर भूल चुके हैं। इस मामले में व्यक्तिगत स्वार्थ के सख्त खिलाफ हैं। खिलाफत या सत्याग्रह जैसे शब्दों से भी फिलहाल दूर ही हैं। जिन शब्दों से वे निकट का वास्ता रखते हैं, उनमें कई भाषाओं में गालियां प्रमुख हैं।

वे इस दिशा में लोक भाषाओं से भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि चीखने में तीन लोगों से एकसाथ मुकाबला कर सकते हैं। शरीर को साधने का ऐसा दावा है कि पांच लोग भी पीटें तो मुंह से आह तक न निकले। मोटी चमड़ी पाने की उनकी साधना शैली की प्रसिद्धि शहर की सीमाओं से परे पहुंचने लगी है। लोग उन्हें देखकर यह ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं। शरीर के साथ जब बरसों यह अभ्यास नियमित तौर पर किया जाता है, तब इस तरह की चमड़ी का वरदान प्राप्त होता है।

यह भी जान लो... चमड़ी को मोटा करने की इस साधना को करना हरेक के बस की बात नहीं है। तप में सफल हुए... तब व्यक्तित्व में आता है निखार... बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर मुद्दे को भी सिर्फ सिर हिलाकर उड़ा देने का हुनर आता है। ऐसी नजर विकसित होती है कि सामने वाला अपने ही आरोप पर पछताने पर विवश हो जाए। पत्रकार कितने भी पूछें मुंह से कोई जवाब न फूटे। गुरु! जब इतना तगड़ा अभ्यास साध लिया जाता है, तब सियासत में सफलता की संभावना बनती है। तब आपके लिए राह खुलती है। फिर इस 24 कैरेट के सोने सी दमकती स्किन वाले जुझारू व्यक्तित्व के लिए घर के सामने लाइन लगती है...।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

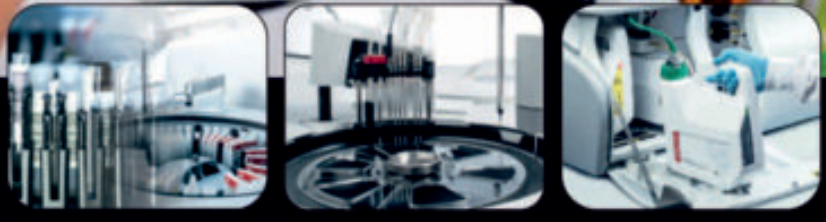

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com